चिंतन

ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच यूके से एफटीए

वैश्विक व्यापार इस समय एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की चेतावनी देकर आर्थिक दबाव की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) लागू होना आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। ये दोनों घटनाएं बताती हैं कि आज दुनिया में व्यापार केवल वस्तुओं के आदान-प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कूटनीति, रणनीति और राष्ट्रीय हितों का सबसे प्रभावी माध्यम बन चुका है। अमेरिका की प्रस्तावित टैरिफ नीति का निशाना रूस की ऊर्जा आय को कम करना है, लेकिन इसका असर भारत जैसे देशों पर भी पड़ सकता है, जिन्होंने अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। भारत आज रूस से सबसे अधिक कच्चा तेल खरीदने वाले देशों में शामिल है। सस्ते रूसी तेल ने भारत को महंगाई नियंत्रित रखने, ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण मदद की है। ऐसे में यदि रूस से तेल खरीदने के आधार पर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की कोशिश होती है, तो यह केवल व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति होगी। अमेरिकी सीनेट में रूस पर प्रतिबंधों से जुड़ा एक संशोधित बिल पेश किया गया है। इसमें रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके। इसी बीच भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते का लागू होना भारत के लिए सकारात्मक संकेत है। यह समझौता केवल टैरिफ घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। भारतीय उत्पादों को ब्रिटेन के बाजार में लगभग शुल्क-मुक्त पहुंच मिलने से वस्त्र, चमड़ा, इंजीनियरिंग, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र को बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। दूसरी ओर भारतीय उपभोक्ताओं को ब्रिटेन से आने वाली कारें, स्कॉच व्हिस्की, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल उपकरण और कई प्रीमियम उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होंगे। हालांकि, एफटीए का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब भारतीय उद्योग गुणवत्ता, तकनीक और उत्पादकता के स्तर पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। केवल आयात सस्ता होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्यात बढ़ाना और घरेलू उद्योगों को मजबूत बनाना भी उतना ही आवश्यक है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुक्त व्यापार का लाभ किसानों, एमएसएमई और छोटे उद्योगों तक भी पहुंचे। कुल मिलाकर ट्रंप की टैरिफ चेतावनी और भारत-यूके एफटीए, दोनों यह साबित करते हैं कि आने वाले समय में वैश्विक व्यापार का स्वरूप केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी होगा। जहां टैरिफ व्यापार को सीमित करने और दबाव बनाने का माध्यम बन सकता है, वहीं मुक्त व्यापार समझौते विकास, निवेश और साझी समृद्धि के रास्ते खोलते हैं। भारत के लिए सही रास्ता यही है कि वह दबाव की राजनीति से अप्रभावित रहते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करे और एफटीए जैसे समझौतों के जरिए वैश्विक बाजार में अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत बनाए। यही संतुलित नीति भारत को बदलती विश्व व्यवस्था में एक भरोसेमंद और प्रभावशाली आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करेगी।

नवाचार
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान

> त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विश्व में उस परिवर्तनकारी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सहकारिता को केवल डेयरी, चीनी या बैंकिंग तक सीमित नहीं किया जाएगा अपितु सहकारिता का विस्तार जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स, हरित ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को समेकित करते किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक दृष्टि पर बहसें होंगी। देश के उत्थान पॉलिसीज पर कार्य करने वाले चेंज मेकर यह मान रहे हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय संभावनाओं का संस्थागत स्वरूप है।

भारत का सहकारिता आन्दोलन अपने नए स्वरूप में आ गया है। बौद्धिक समाज का उत्पादन एवं उनसे राष्ट्र निर्माण की कोशिश भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वैसे तो आणंद का नाम श्वेत क्रांति के स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है, जहां त्रिभुवनदास पटेल, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा और डॉ. वर्गीज़ कुरियन की दूरदर्शिता व आत्मविश्वास अपना नया आकार पाया। इस भूमि पर जिन मनीषियों ने कार्य किया उन्होंने सिद्ध किया कि यदि उत्पादक स्वयं अपने संगठन के स्वामी बन जाएं, तो आर्थिक स्वतंत्रता किसी स्वप्न से कम नहीं होती। उदाहरणतया अमूल की सफलता केवल दुग्ध उत्पादन की कहानी नहीं है, यह विश्वास, सहभागिता और लोकतांत्रिक प्रबंधन की सफलगाथा है। इसी विरासत को नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप आगे बढ़ाने का संकल्प है-त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, जिसे अमित शाह वर्षों से स्थापित करना चाहते थे। विश्व में यह विश्वविद्यालय उस परिवर्तनकारी सोच का प्रतीक माना जा रहा है, जिसमें सहकारिता को केवल डेयरी, चीनी या बैंकिंग तक सीमित नहीं किया जाएगा अपितु सहकारिता का विस्तार जैविक खेती, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य पालन, बीज उत्पादन, पर्यटन, डिजिटल सेवाओं, ई-कॉमर्स, हरित ऊर्जा और ग्रामीण उद्यमिता को समेकित करते किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में आधुनिक प्रबंधन, डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वित्तीय अनुशासन और वैश्विक दृष्टि पर बहसें होंगी। देश के उत्थान पॉलिसीज पर कार्य करने वाले चेंजमेकर यह मान रहे हैं कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय संभावनाओं का संस्थागत स्वरूप है। यहां से निकलने वाले विद्यार्थी केवल डिग्रीधारक नहीं लेकर निकालेंगे अपितु वे सहकारिता के नए राजदूत होंगे। वे गांवों में नई आशा की लौ जगाएंगे।

किसानों को बाजार से जोड़ेंगे। महिलाओं को आर्थिक शक्ति देंगे। युवाओं को उद्यमिता की राह दिखाएंगे। समाज में साझेदारी की संस्कृति को सुदृढ़ करेंगे। उनका कार्य आर्थिक प्रगति और सामाजिक संवेदनाओं दोनों को निर्मित करेंगे। इस विश्वविद्यालय के विजन प्लान को सही से पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि एनईपी-2020 के माध्यम से शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध करने हेतु नहीं निर्धारित हुए हैं, अपितु वह व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए भी है। उसके लिए ठीक-ठीक कार्य आईआईएम जैसे संस्थाओं से अधिक सहकारिता विश्वविद्यालय करेगा। यह उस क्षण का आरंभ है जब विद्यार्थी पुस्तकों से बाहर निकलकर जीवन की खुली पाठशाला में प्रवेश कर रहे हैं। वास्तव में वास्तविक विश्वविद्यालय वही है जो वास्तविक जीवन मूल्य परिवर्तन का माध्यम बने। नए जीवन की शुरुआत प्रथम दीक्षांत समारोह से जो शुरू करने जा रहे हैं वे रिश्क में नहीं हैं, अपितु वे सन्देश दे रहे हैं कि जीवन मूल्य भी अब सहकारिता से सुरक्षित होंगे। यह सहकारिता में नए आकाश में नई उड़ान है, चाहे कोई माने या न माने। यह उड़ान निःसंदेह सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह के संकल्पों से संभव हो पा रही है, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिश्योक्तिपूर्ण बात न होगी। हम सभी आज यह महसूस करने लगे हैं कि भारत की सहकारी व्यवस्था आज विश्व की सबसे बड़ी जन

आधारित आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक है। करोड़ों नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहकारी संस्थाओं से जुड़े हैं। किसानों, महिलाओं, छोटे व्यापारियों, कारीगरों और ग्रामीण युवाओं के लिए सहकारिता केवल संस्था नहीं, बल्कि अवसर का द्वार है। लाभ और लोकहित के बीच संतुलन स्थापित कर नवाचार हेतु विकास का माध्यम सहकारिता बनने जा रही है। सहकारिता का प्राण उसके नैतिक मूल्यों में निहित है। विश्वास, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक निर्णय, ये वे आधार हैं जिन पर सहकारिता का विशाल भवन खड़ा हुआ है। यदि इन मूल्यों के साथ त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय दायित्वबोध लेकर ऐसे चरित्रवान नेतृत्व का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है तो इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए।

विशेष विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि यह विश्वविद्यालय सहकारिता के नए पक्षियों के कलरव से लोकमंगल का माध्यम बनने वाला है। जो 302 विद्यार्थी एवं 2 स्कॉलर को स्नातक एवं पीएचडी की उपाधि मिली है, यह तो एक शुरुआत है। केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर ने गुजरात के आणंद में 'त्रिभुवन' सहकारी विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में कहा भी कि नरेंद्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" के संकल्प तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के दूरदर्शी नेतृत्व में स्थापित 'त्रिभुवन' सहकारी यूनिवर्सिटी सहकारिता क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। यह यूनिवर्सिटी भविष्य के सहकारी नेतृत्वकर्ताओं, शोधकर्ताओं और पेशेवर प्रबंधकों को तैयार कर भारत के सहकारी आंदोलन को नई दिशा और नई गति प्रदान करेगी। यह बात शत-प्रतिशत सही भी है और उनके प्रयासों का एक तरह से अभिनंदन भी है। सहकारिता को नया बौद्धिक आधार ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से जो मिलने लगा है, जिसने ज्ञान, शोध, नवाचार और मानवीय मूल्यों का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया है तो ऐसे ऐतिहासिक पहल को स्वर्णाक्षरों में अंकित भी किया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह की मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की जानी चाहिए। दरअसल, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय उस विश्वास का प्रतीक अब बनने जा रहा है, जो संगठित समाज की शक्ति व किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पहल है। भारत इससे विश्व की सहकारिता को टक्कर देगा और देश को सशक्त बनाएगा, इसे नहीं भूलना चाहिए। महिला डिग्रीधारिकों की एक नई नवाचार की प्रयोगशाला होगी। महिलाएं सशक्तिकरण का नया अध्याय लिखेंगी, यह विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में शामिल होने जा रहा है।

हम खुद विश्व जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और असमानता जैसी चुनौतियों से लड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से सशक्त बनकर और भारतीय जनमानस को सशक्त बनाकर सामुदायिक भागीदारी और टिकाऊ विकास का नया मार्ग तैयार करेंगे। सहकारिता विश्वविद्यालय के संबंध में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के आणंद में इस विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में इसके उद्देश्यों को विस्तार से रखा तो इसके बारे में जो भी कल्पनाएं लोग किए हों, लेकिन अब तो इस विश्वविद्यालय से सैकड़ों छात्र व शोधार्थी उपाधि प्राप्त करके भारत देश की सेवा में आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब जो अनमने ढंग से इस पहल की आलोचना करते रहे होंगे उनके लिए भी एक सीख है कि देश के लिए पहले अपने मन में इच्छा पैदा करो, उसे संजोकर उसकी संकल्पना को स्वरूप दो और फिर उसे स्थापित करके मिसाल के रूप में पेश करो। अमित शाह की प्रसन्नता की अनुभूति निःसंदेह असीमित होगी क्योंकि सहकारिता के नए आकाश में नई उड़ान की यह देशव्यापी हर्ष व उल्लास की बेला है।

(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय में चेयर प्रोफ़ेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

रक्षा प्रणाली

प्रमोद भार्गव

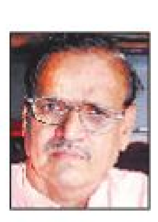

लंबी जंग की तैयारी के लिए सक्षम होता भारत

ऑपरेशन सिंदूर की छोटी लड़ाई के बाद भारत रक्षा-रणनीति में बदलाव के ऐसे संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान या अन्य किसी देश से लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़े तो उसकी युद्ध क्षेत्र में सक्षमता बनी रहे। नतीजतन पिछले सवा साल में भारत ने हथियार व अन्य उपकरणों की बड़ी खरीद की है अथवा उसकी तैयारी चल रही है। अतएव स्पष्ट संकेत है कि तीनों सेनाओं को अब सीमित जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि लंबी और बहुस्तरीय लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है। रक्षा क्रियान्वयन सलाहकार परिषद ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए संघर्ष के बाद 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनकी कुल कीमत 9.80 लाख करोड़ रुपये हैं। यह राशि कई वर्षों में धीरे-धीरे खरीद सौदों, निर्माण कार्यों और योजनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होगी। हाल ही में भारतीय निजी उद्योगपतियों को भी बड़ी रक्षा सामग्री के निर्माण की अनुमति दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर तीन नौसेनिक जहाजों आइएनएस दूनागिरी, आइएनएस संशोधक और आइएनएस अग्रय को नौसेना के बेड़े को सुपुर्द करते हुए कहा है कि 'कोई भी राष्ट्र समुद्र में अपनी क्षमता बढ़ाए बिना बड़ी शक्ति नहीं बन सकता है। ये संकेत स्पष्ट करते हैं कि ये तैयारियां भारत को सामरिक दृष्टि से वैश्विक पटल पर महत्वपूर्ण बना रही हैं। इन खरीदों में टैंक, तोप, ड्रोन, एयरडिफेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के सटीक हमले के लिए एआई नेटवर्क आधारित युद्ध क्षमता को विकसित करने के बड़े संकेत हैं। दरअसल रूस-यूक्रेन, इजरायल-हमास और अमेरिका-ईरान तथा पश्चिम एशिया के देशों में चल रहे युद्ध को देखते हुए भारत की सैन्य सोच बदली है। हालांकि पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की भी बड़ी संख्या में जरूरत है। भारत ने मार्च 2025 में 54 हजार करोड़, जुलाई में 1.05 लाख करोड़, अगस्त में 67 हजार करोड़, अक्टूबर में 79 हजार करोड़ की रक्षा सामग्री खरीद के प्रस्ताव अलग-अलग देशों को दिए हैं। फरवरी 2026 में 3.6 लाख करोड़ की रक्षा सामग्री खरीद प्रस्तावों को मंजूरी देने के साथ 114 नए राफेल विमान भी खरीदे जा रहे हैं। इसी माह जुलाई में 52 हजार करोड़ की सामग्री सैन्य-बलों की जंगी क्षमता बढ़ाने के लिए दिए गए हैं। साफ है, भविष्य में भारत का किसी देश से युद्ध होता है तो वह लंबी लड़ाई की सामर्थ्य दिखाने में अग्रणी रहेगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो तीन युद्धपोत सेना में शामिल किए गए हैं, उनसे वाकई भारत की समुद्र में ताकत बढ़ी है, क्योंकि बीते कुछ वर्षों में 40 से अधिक स्वदेश में ही निर्मित युद्धपोत और पनडुब्बियां समुद्र में तैनात कर दिए हैं। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने वाले ये जहाज और पनडुब्बियां भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के साथ-साथ देश की औद्योगिक क्षमता बढ़ाने वाली है। आने वाले दिनों में इनके निर्यात के द्वार भी खुल जाएंगे। अतएव पश्चिम बंगाल की ब्लू इकोनोमी का बड़ा केंद्र बन जाएगा। भारत में नौसैनिकों की सुविधाओं के लिए 45 बड़े प्लेटफॉर्म भी तैयार किए जा रहे हैं। आइएनएस दूनागिरी अत्याधुनिक हथियारों और संवेदनशील प्रणालियों के साथ ब्रह्मोस मिसाइल से संपन्न है।

ब्रह्मोस सतह से सतह और सतह से आकाश तक शत्रु पर सटीक हमला करने में युद्धपोत पर लगे नवीनतम उपकरण एवं स्टेल्थ तकनीक के कारण यह मिसाइल रडार की पकड़ में नहीं आती है। इसकी इस विलक्षणता के चलते ब्रह्मोस मिसाइल को दूसरे देश भी खरीद रहे हैं। आइएनएस संशोधक देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। इसे तटीय क्षेत्रों व गहरे समुद्री इलाकों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने तथा रक्षा एवं नगरिक क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े जुटाने के उद्देश्य से निर्मित किया गया है। आइएनएस अग्रय पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। उथले समुद्री क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों और अन्य खतरों का मुकाबला करने में इसे अत्यंत प्रभावी माना जा रहा है। यह टारपीडो, स्वदेशी रॉकेट लांचर और उथले जल के लिए विकसित सोनार प्रणाली से लैस है। इसके चलते समुद्र के भीतर गुप्त खतरे का इसे पता चल जाता है। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण की इस क्षमता ने भारत को पोत निर्माण में आत्मनिर्भर बना दिया है। इस उपलब्धि से समुद्र में भारतीय हितों की रक्षा का अभियान और प्रभावी ढंग से चलाया जा सकेगा। इसके पहले भारत स्वदेशी तकनीक से परमाणु पनडुब्बी आईएनएस 'अरिहंत' का निर्माण 2009 में शुरू करके 2013 में इसे समुद्र में जलावतरण भी कर चुका है। इस स्वदेशी परमाणु चालित पनडुब्बी अरिहंत का परमाणु रिएक्टर चालू होना हमारी स्वदेशी तकनीकि क्षमताओं को विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम था।

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

आत्मसंयमी होना श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम लक्षण

संकलित
दर्शन

आत्मसंयम मनुष्य की ऐसी आंतरिक क्षमता है, जिसके आधार पर मनुष्य अपना समग्र विकास करने में सक्षम होता है। बुरी आदतों पर नियंत्रण आत्मसंयम की शक्ति से ही संभव है। असल में यही खराब आदतें हमारी प्रगति की राह में अवरोध बनती हैं। यदि दृढ़ इच्छाशक्ति और आत्मसंयम में सही ताल मिल जाए तो असंभव से लक्ष्य को भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। संयम एक ऐसा बीज मंत्र या आवरण है, जो हर स्थिति में कारगर होता है। इस संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनका जीवन यही संदेश देता है कि उनके उत्कर्ष में आत्मसंयम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आत्मसंयमी होना श्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम लक्षण है। जिन लोगों में आत्मसंयम होता है उनका स्वास्थ्य, रिश्ते, आर्थिक स्थिति और करियर अन्य लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। ऐसे लोग जीवन से अधिक संतुष्ट रहते हैं। उन्हें जीवन अधिक सार्थक लगता है। आत्मसंयम का जीवन रचनात्मकता से ओतप्रोत होता है। यह सद्गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय को दूर करने के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई एवं गंभीरता प्रदान कर उसके जीवन को सुखप्रद बनाता है। आत्मसंयम का महामंत्र आत्मसात कर हम असीमित इच्छाओं के अश्व की लगाम अपने हाथ में रख सकते हैं। थोड़ा गहराई में जाएं तो संयमी की यात्र कंकर से शंकर बनने की है। हमें अपने जीवन में आत्मसंयम की आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है, ताकि हम पथ से भटके बिना अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो सकें।

गुरु की कृपा से असंभव काम पूरे हो पाते हैं

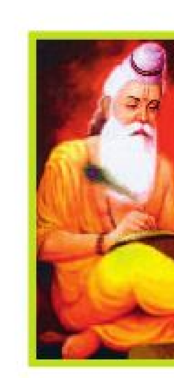

संकलित
प्रेरणा

महाभारत और श्रीमद् भागवद् कथा के रचियता महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। इनका पूरा नाम कृष्णद्वैपायन था। इन्होंने ही वेदों का संपादन किया। इसलिए इनका नाम वेदव्यास पड़ा। इनके पिता महर्षि पाराशर और माता सत्यवती थीं। पैल, जैमिन, वैशम्पायन, सुमन्तु मुनि, रोमहर्षण आदि महर्षि वेदव्यास के महान शिष्य थे। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर गए। उस समय गांधारी और धृतराष्ट्र ने उनकी बहुत सेवा की थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने सौ पुत्रों की माता होने का वरदान गांधारी को दिया था। कुछ समय बाद जब गांधारी गर्भवती हुईं। जब संतान के जन्म का समय आया तो संतान की जगह एक मांस पिंड प्रकट हुआ। जब ये बात वेदव्यास जी को मालूम हुई तो वे तुरंत गांधारी के पास पहुंचे। वेद व्यास जी ने अपनी विद्या से उस मांस पिंड से सौ पुत्र बना दिए। गुरु की कृपा से गांधारी सौ पुत्रों की माता बन गई। महर्षि के आशीर्वाद से ही गांधारी को सौ पुत्र हुए जो आगे जाकर कौरव कहलाए। जिनके सेनापति दुर्याधन हुए। महाभारत के युद्ध में दुर्याधन ने ही कौरव सेना की कमान संभाली थी। गुरु की कृपा हो जाती है तो असंभव काम भी पूरा हो जाता है। इसी लिए हम गुरु की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए ताकि उसका फल हमें मिले। कहा गया है की बिना गुरु ज्ञान अधूरा है। गुरु ही हमारा विपत्ति के समय मार्ग दर्शन करते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

होर्मुज संकट : विश्व आर्थिकी के लिए बढ़ता खतरा

अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य को वैश्विक चिंता का विषय बना दिया है। यदि यह समुद्री मार्ग लंबे समय तक बाधित रहता है, तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार व्यवस्था प्रभावित होगी। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय संघर्ष अब वैश्विक संकट का रूप ले सकता है। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। प्रतिदिन दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। जहाजों की आवाजाही अगर बाधित होती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आना स्वाभाविक है। – *सुभाष यादव, बलौदाबाजार*

करंट अफेयर

ग्रेट बैरियर रीफ के लिए खतरा बना है जल प्रदूषण

जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले प्रवाल विरंजन (कोरल ब्लीचिंग) को आमतौर पर ग्रेट बैरियर रीफ के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, लेकिन दुनिया की इस सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली के सामने खराब जल गुणवत्ता भी एक गंभीर चुनौती है। खेती, शहरों और वन क्षेत्रों से बहकर नदियों में पहुंचने वाली मिट्टी (तलछट) समुद्र में दूर तक पहुंच जाती है। इसकी अधिक मात्रा प्रवाल भित्तियों और समुद्री घास (सीग्रास) के मैदानों को ढक सकती है, जबकि उर्वरकों और कीटनाशकों के अवशेष स्थिति को और खराब कर देते हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन जल गुणवत्ता ऐसा मुद्दा है जिस पर ऑस्ट्रेलिया सीधे कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने हाल के वर्षों में बार-बार इस पर चिंता जताई है। वर्ष 2023 के बाद जारी चौथे मसौदा निर्णय में भी जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ खराब जल गुणवत्ता को प्रमुख खतरा बताया गया है। मसौदे में 2024-25 में प्रवाल विरंजन, खराब जल गुणवत्ता, मछली पकड़ने के ऐसे गैर टिकाऊ तरीके और तटीय भूमि के अनुचित उपयोग से हुए नुकसान पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है।

ऑफ बीट

खुद सब्जियां उगाने वाले कम भोजन करते हैं बर्बाद

जीवन यापन के बढ़ते खर्च से लोगों, विशेष रूप से कम आय वाले (जिनका आहार अक्सर समुचित नहीं होता है), के लिए स्वस्थ आहार का खर्च उठा पाना कठिन होता जा रहा है। इसके बावजूद, ब्रिटेन में घरों में हर साल आश्चर्यजनक मात्रा में भोजन बर्बाद होता है। इसमें लगभग 68 किलोग्राम फल और सब्जियां भी शामिल है। खाने की बर्बादी न केवल आपकी जेब पर भारी पड़ती है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। वैश्विक स्तर पर, हर साल 1.3 अरब टन भोजन बर्बाद हो जाता है, जिससे दुनिया के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आठ प्रतिशत उत्पन्न होता है। ये उत्सर्जन खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के सभी चरणों में अप्रयुक्त भोजन से उत्पन्न होता है। हमारे हालिया अध्ययन से हालांकि पता चला है कि जो लोग बगीचों और आवंटित जमीनों में फसल और सब्जियां स्वयं उगाते हैं, वे औसतन केवल 3.4 किलोग्राम फल और सब्जियां बर्बाद करते हैं – जो ब्रिटेन के औसत से 95 प्रतिशत कम है। इन परिवारों ने भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए विभिन्न प्रथाओं को अपनाया, जिसमें अपनी अतिरिक्त उपज को संरक्षित करना या किसी अन्य को दे देना भी शामिल है। हाल के वर्षों में ब्रिटेन और अन्य जगहों पर बगीचों, सामुदायिक उद्यानों और आवंटित भूमि पर ताजा फसल एवं सब्जियां उगाने में दिलचस्पी फिर से बढ़ी है।

X ट्रेंड f

ट्रेड एग्रीमेंट

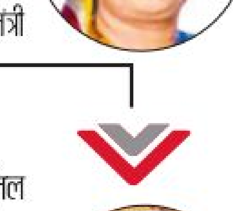

आज से भारत-यूके कॉम्प्रिहेन्सिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। उम्मीद है कि यह अहम समझौता 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $100 बिलियन तक पहुंचाएगा।
-अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय महिला विकास मंत्री

अंतरिक्ष उड़ान

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कदम रखा है। यह मिशन नई रिसर्च, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और अंतरिक्ष अभियानों के लिए नई संभावनाओं का रास्ता खोलेगा।
- सम्राट चौधरी, सीएम, बिहार

पारदर्शी परीक्षा प्रणाली

पारदर्शी परीक्षा प्रणाली हर छात्र का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी देश भर में छात्रों के इस अधिकार के लिए लड़ रही है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह समस्या और भी गंभीर है, जहां व्यापम, पटवारी भर्ती, कॉन्स्टेबल भर्ती और नर्सिंग कॉलेज जैसे घोटाले हुए हैं।
- कमलनाथ, पूर्व सीएम, मध्यप्रदेश

दर्शकों का अपमान

फिल्मों पर सेंसरशिप असल में दर्शकों का अपमान है। स्मार्टफोन और बेहिसाब जानकारी तक पहुंच के इस दौर में, यह सोचना कि सरकार की बनाई कमेटी किसी सच्चाई के बारे में फिल्ममेकर के नज़रिए से बालिग लोगों को बचा सकती है, ये सिर्फ़ पुरानी सोच है, बल्कि बेवकूफ़ी भी है।
- रामगोपाल वर्मा, फिल्मकार

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
आदर्श आचरण ही व्यक्तित्व को अनुकरणीय बनाता है

आयात घटाने की चुनौती

गत दिवस केंद्रीय कैबिनेट ने जो अनेक फैसले लिए, उनमें अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा। ये फैसले यही अधिक रेखांकित करते हैं कि सरकार यह चाहती है कि आयात घटे और मैन्यूफैक्चरिंग बढ़े ताकि निर्यात बढ़े। सरकार ऐसे प्रयत्न पहले भी करती रही है। इसका प्रमाण है उसकी ओर से मेक इन इंडिया के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू करना और साथ ही स्वदेशी के मंत्र को दोहराना। इन अभियानों को जोर-शोर से शुरू करने और कारोबारियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय करने के बाद भी बात पूरी तरह बन नहीं रही है। देश को अनेक ऐसे उत्पादों का आयात करना पड़ रहा है, जिनका उत्पादन देश में आसानी से किया जा सकता है। तथ्य यह भी है कि भारतीय उत्पादों का निर्यात अपेक्षा के अनुरूप नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश के वे कारोबारी भी आयात पर निर्भरता कम करने वाले तौर-तरीके अपनाने और विश्वस्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पादों का निर्माण करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, जिनके पास पूंजी और संसाधनों की कमी नहीं। समझना कठिन है कि हमारे बड़े कारोबारी भी शोध एवं नवाचार पर अपेक्षित निवेश करने के लिए तैयार क्यों नहीं हैं? उचित यह होगा कि सरकार इसके कारणों की तह तक जाए, क्योंकि आयात कम करना और निर्यात बढ़ाना तब तक संभव नहीं, जब तक हमारे कारोबारी अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते।

भारतीय कारोबारी बहुत कम ऐसे उत्पाद बनाते हैं, जिनकी विश्व में मांग, पहचान और प्रतिष्ठा हो। यदि वे विश्वस्तरीय सेवाएं दे सकते हैं तो विश्व स्तर की गुणवत्ता वाले उत्पाद क्यों नहीं बना पा रहे हैं? यह ध्यान रखा जाए कि भारतीय उत्पाद विश्व में तभी अपना स्थान बना सकते हैं, जब उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी। आज यह अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि समृद्ध होता भारतीय मध्य वर्ग कम गुणवत्ता वाले उत्पाद इस कारण खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि वे स्वदेश में निर्मित हैं। जब उन्हें उसी मूल्य पर विदेशी उत्पाद आसानी से उपलब्ध हैं तो फिर वे गुणवत्ता से समझौता क्यों करें? निःसंदेह यह भी ठीक नहीं कि भारत जिस तैयार माल का निर्यात बढ़ा रहा है, उसे बनाने के लिए कई आवश्यक कल-पुर्जे बाहर और विशेष रूप से चीन से आयात किए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं के साथ दवाएं और इंजीनियरिंग सामान भी शामिल है। यह चिंताजनक है कि तमाम जतन के बाद भी चीन से आयात पर निर्भरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यदि भारत को निर्यात बढ़ाना है तो कपड़ा, रत्न-आभूषण और रसायनों जैसे परंपरागत उत्पादों के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक्स सामग्री के निर्माण पर भी ध्यान देना होगा।

आर्थिक विकास की नींव

बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास की नींव है। बिजली, परिवहन और संचार निवेश आकर्षित करने, व्यापार और उद्योग को बढ़ाने के प्रमुख स्तंभ हैं। सब जानते हैं कि पूंजी निवेश पनपने से रोजगार बढ़ता है। बड़ी जनसंख्या के दबाव वाले बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए तीव्र औद्योगिक विकास अपरिहार्य है। अपने स्तर से इस प्रदेश ने विकास की गतिशक्ति को बढ़ाने की भरपूर चेष्टा की है। समरूप दृष्टि वाली केंद्र सरकार के सहयोग ने इसको और आगे बढ़ाया है। देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे का संजाल होने से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि के नए-नए द्वार सृजित हो रहे हैं। इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए योजनाओं पर अभी से काम शुरू किया जा रहा है। लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे के पूरा होने के अवसर पर जिस प्रकार राजधानी के चतुर्दिक सड़कों के संजाल के लिए कार्ययोजना घोषित की गई, वह निश्चय ही नई जीवनरेखा की नींव है। प्रदेश में अगले दो साल में पांच लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश को 'भारत का दिल' कहा जाता है। देश की समृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित होना आवश्यक है। लखनऊ-सीतापुर हाईवे को छह लेन, हवाई अड्डे से शहीद पथ के ऊपर बाहरी रिंग रोड तक 23 किलोमीटर के नए परिपथ और उसके ऊपर मेट्रो जैसी परियोजना की मंजूरी इस बात की आश्वस्ति है कि राजधानी अपनी बुनियादी संरचना में भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप सुगठित होने जा रही है।

नई परियोजनाओं की मंजूरी से राजधानी भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगठित होगी

गहरी पीड़ा देने वाला प्रकरण

चेतन भगत

जब धर्म के आवरण वाले परिसर में भी लोभ पर नियंत्रण न रह जाए तो समझिए कि समस्या चरित्र में खोट की अधिक हैं

भारतीय क्या स्वभाव से ही भ्रष्ट होते हैं? ऐसे भ्रष्ट कि भगवान राम तक को न बख्शें। दशकों से लोग जिस मंदिर के स्वप्न की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहे, उसी मंदिर से यह बात सामने आई कि जिन लोगों को इस पवित्र संस्थान की सेवा का दायित्व सौंपा गया था, वही शायद यहां चोरी या हेराफेरी करते रहे। यह किसी सरकारी विभाग, ऐरे-गैरे ठेकेदार या अनाम कंपनी से नहीं, बल्कि भगवान राम की संपदा में ही सेंधमारी का मामला है। याद रहे कि इस मंदिर निर्माण के संकल्प की पूर्ति में कई पीढ़ियां खप गईं। इस मुद्दे ने देश की राजनीति की दशा-दिशा को बदल कर रख दिया। समुदायों के बीच विभाजन की खाई खींच दी। पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और आधुनिक भारत के सर्वाधिक भावनात्मक मुद्दों में से एक बन गया। जब राम जन्मभूमि मंदिर का स्वप्न वास्तव में साकार हुआ, तो दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने जश्न मनाया। अनगिनत श्रद्धालुओं के लिए यह महज एक और मंदिर नहीं था, उनके लिए यही मंदिर था। ऐसे में यहां चोरी की घटना मन को गहरी टीस देने वाली है। यह कोई सामान्य भारतीय घपला-घोटाला नहीं कि किसी ने कोई गमला चुरा लिया या किसी सरकारी कर्मचारी ने किसी काम के एवज में रिश्वत ली हो। एक ऐसे देश में जहां नैतिकता का पतन एक सामान्य परिपाटी बनता जा रहा हो, वहां राम मंदिर से चोरी का मामला कल्पनातीत ही प्रतीत होता है। गर्त में जा रही नैतिकता को अपनी नियति मान चुके समाज के लिए भी यह पाप की पराकाष्ठा है।

जिस प्रकरण ने समूचे देश की चेतना को झकझोर कर रख दिया, उसके उजागर होने पर भी हमने वही सब किया, जो ऐसी स्थितियों में करने के लिए विख्यात या कहें कि कुख्यात रहे हैं। मसलन-कुछ खलनायकों को चिह्नित करो, कुछ को जेल भेज दो, कड़ी निंदा के साथ मामला रफा-दफा करने के साथ आगे बढ़ो। यह बहुत ही सहज प्रक्रिया है, लेकिन इसमें उस असहज करने वाली सच्चाई को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि भारत में भ्रष्टाचार महज कुछ लोगों की करतूतों से ही नहीं फलता-फूलता आया है। यह इस कारण भी अपनी पैठ जमाता गया, क्योंकि तमाम सामान्य भद्र जनों ने इसके साथ जीने और इसे अनदेखा करने के साथ ही इसके संग अनुकूलन की क्षमता विकसित कर ली और इस क्रम में जब कभी अवसर मिला, तो वे इससे लाभ उठाने से भी नहीं चूके। हम इसी सोच के वशीभूत रहते हैं मानो भ्रष्टाचार केवल दूसरों की करतूत है-जैसे नेता, नौकरशाह और ठेकेदार ही इसके लिए जिम्मेदार हों। क्या वाकई ऐसा है? आखिर ये लोग हैं कौन? ये सभी हमारे इर्द-गिर्द के ही लोग हैं। कहीं न कहीं हमने भ्रष्टाचार को एक नैतिक नाकामी के रूप में लेना बंद कर उसे एक 'कौशल' मानना शुरू कर दिया है। हमारे लिए कर चोरी करने वाला कारोबारी स्मार्ट, ऊपरी कमाई करने वाला सरकारी कर्मचारी 'पूरी तरह सेटल्ड' और कानूनी विसंगतियों का फायदा उठाकर काम निकालने वाला संसाधन-संपन्न माना जाता है। निजी जीवन में ही इसके तमाम उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे विवाह के लिए लिए सरकारी नौकरीपेशा लड़का खोज रहे अभिभावक लड़के की 'ऊपरी कमाई' के बारे में पूछताछ को लेकर शायद ही झिझकते हों।

अक्सर हम धार्मिकता और नैतिकता को एक दूसरे का पर्याय मान लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म के प्रति अतिशय आस्था रखने वाला व्यक्ति भी दैनंदिन जीवन में बेईमानी कर सकता है। भारतीय समाज में नैतिकता की पूर्ति के लिए धर्म का सहारा लेने की एक विचित्र परिपाटी विकसित हो गई है। मतलब चाहे कारोबारी धोखाधड़ी हो या कमजोर लोगों का शोषण, ऐसा कोई भी 'पाप' करो और किसी मंदिर को चंदा भेजकर स्वयं का आध्यात्मिक शुद्धीकरण समझ लो। मानो भगवान ने कोई 'पाप-पुण्य समायोजन सेवा' चला रखी हो कि भगवान को दी गई 'रिश्वत' से आपकी बेईमानी में ईमानदारी का भाव घोल दिया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण ने ऐसी ही तमाम धारणाओं को ध्वस्त किया है। जब धर्म के आवरण वाले परिसर में भी लोभ पर नियंत्रण न रह जाए तो समझिए कि समस्या चरित्र में खोट की अधिक है और इसका समाधान भी अपेक्षाकृत अधिक कठिनाई भरा है।

कुछ लोग यह दलील दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो हर जगह है। अन्य धर्मों, संस्थानों और देशों में भी ऐसे प्रकरण सामने आते रहते हैं। मान लिया कि यह भी सही है, लेकिन इससे क्या साबित होता है? कहीं और भ्रष्टाचार होने से यहां के भ्रष्टाचार का मामला कम शर्मनाक नहीं हो जाता। इसे हिंदू बनाम गैर-हिंदू का मुद्दा भी न बनाया जाए। इस मामले में जो आरोपित हैं, वे बाहर से आए हमलावर नहीं, बल्कि भीतर बैठे वे लोग हैं, जिन पर यहां सेवा एवं संचालन का दायित्व था। इस प्रकरण से यही सीख मिलती है कि एक संस्थान केवल विश्वास के भरोसे ही न रहे। हमारी समस्या यह भी है कि हम कुछ लोगों पर आवश्यकता से अधिक भरोसा कर उन्हें तमाम बुराइयों से परे मान लेते हैं। वास्तव में हमें प्रभावी तंत्र विकसित करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग बुरे होते हैं, लेकिन यह भी न भूला जाए कि मनुष्य अंततः मनुष्य ही होता है और उसके साथ गलतियों की गुंजाइश बनी रहती है। यह बात काफी हद तक सही है कि सभी भारतीय एक जैसे नहीं, लेकिन यह भी उतनी ही सही है कि अधिकांश तो ऐसे ही मिल जाएंगे।

हम हिंदुओं के लिए यह बहुत पीड़ा देने वाला प्रकरण है। हममें से तमाम लोगों ने धर्म को प्रतीकों, पहचान और कर्मकांडों तक सीमित कर लिया है। धर्म मंत्रोच्चार, तीर्थाटन और दान तक ही सीमित नहीं है। धर्म का मर्म तो व्यक्ति के चरित्र से निर्धारित होता है कि आप कैसे धनार्जन करते हैं? कैसे लोगों से व्यवहार करते हैं? जब गलत कार्य करना बहुत आसान लगता हो तो स्वयं को उस राह पर फिसलने से कैसे बचाते हैं? जब कोई न देख रहा हो तो स्वयं को कैसे संचालित करते हैं? याद रहे कि हमारे चरित्र में खोट हो तो घंटों पूजा-पाठ का कोई अर्थ नहीं रह जाता। संभव है कि चढ़ावा चोरी प्रकरण से प्रभु श्रीराम ने हमें संभलने का एक अवसर दिया हो कि न केवल मंदिर परिसर में गड़बड़ियों को दूर किया जाए, बल्कि हम स्वयं एवं समाज को सुधार हेतु प्रयासरत रहें।

(स्तंभकार विख्यात लेखक हैं)
response@jagran.com

अवधेश राजपूत

बंगाल में पंथनिरपेक्षता की वापसी

कृपाशंकर चौबे

वाम दल और तृणमूल, दोनों खुद को पंथनिरपेक्ष कहते नहीं थकते, पर दोनों ने तसलीमा को कोलकाता नहीं आने दिया

बांग्लादेश की बहुचर्चित लेखिका तसलीमा नसरीन का एक साहित्य समारोह में शामिल होने के लिए अगस्त की शुरुआत में कोलकाता जाना एक शुभ संकेत है। बंगाल की पूर्ववर्ती सरकारों ने कट्टरपंथियों के दबाव में दो दशकों तक तसलीमा को कोलकाता आने की अनुमति नहीं दी। तसलीमा की कोलकाता यात्रा को सुगम बनाकर शुभेंदु अधिकारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की खोखली पंथनिरपेक्षता की पोल खोल दी। तसलीमा को कोलकाता आने की अनुमति दिया जाना कट्टरपंथियों के लिए कड़ा संदेश है। तसलीमा को मजहबी कट्टरपंथ और पुरुष प्रभुत्व का विरोध करने की कीमत दो दशकों से बंगाल के बाहर रहने के रूप में चुकानी पड़ रही थी। अपने देश से तो वे 32 वर्षों से निर्वासित हैं। निर्वासित जीवन के दौरान उन्हें कई बार अपनी पुस्तकों पर प्रतिबंध और मौत के फतवों का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश से निर्वासित होने के पहले तसलीमा वहां अधिकारों से वंचित महिलाओं के पक्ष में लगातार कलम चलाती रहीं। इस पर कट्टरपंथियों ने कहा कि तसलीमा बांग्लादेश की महिलाओं को पथभ्रष्ट कर रही हैं। 1992 में ढाका पुस्तक मेले में उनकी पुस्तकें जलाई गईं। उन पर पथराव हुआ। पुस्तक मेले की आयोजक बांग्ला अकादमी ने उन्हें चेताया कि वे ढाका मेडिकल कालेज में चिकित्सक की सेवा या लेखन में किसी एक का चयन कर लें। तसलीमा ने लेखन चुना।

तसलीमा की विख्यात पुस्तक 'लज्जा' ने उनके विरोध में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के अभियान को और तेज कर दिया। इस पुस्तक में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले नृशंस अत्याचार का वर्णन किया है। उनके सिर पर पहले 50 हजार और फिर एक लाख टका का इनाम घोषित किया गया। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बांग्लादेश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर-जमानती वारंट जारी किया। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने बांग्लादेश पर दबाव बनाया, तब जाकर वहां की सरकार ने 1994 में तसलीमा को सुरक्षित स्वीडन जाने दिया। तभी से तसलीमा अपने देश से निर्वासित हैं। निर्वासित जीवन के आरंभिक वर्षों में तसलीमा का अधिकतर समय स्वीडन और फ्रांस में बीता। देश से निर्वासित होने के बाद उनके कोलकाता आने का सुयोग बीच-बीच में बनता रहा। 2004 से तो वे प्रायः भारत में ही रह रही हैं। कोलकाता में उन्होंने एक फ्लैट ले लिया था, जहां 2004 से 21 नवंबर 2007 तक वे रहीं। कोलकाता में रहते हुए वे अपनी जड़ों से जुड़े रहने का बोध करती थीं। तसलीमा के अनुसार पश्चिम बंगाल एक अर्थ में बांग्लादेश का मौसेरा भाई है। अपने भाषाभाषी समाज में आकर उन्हें एक तरह से घर में रहने जैसा लगता है। कोलकाता से वे 9 अगस्त, 2007 को हैदराबाद प्रेस क्लब में आयोजित अपने उपन्यास 'शोध' के तेलुगू अनुवाद के लोकार्पण समारोह में गईं तो कट्टरपंथियों ने वहां उन पर जानलेवा हमला किया। उसके कुछ माह बाद कोलकाता में कट्टरपंथियों ने 21 नवंबर, 2007 को तसलीमा को भारत से निकालने की मांग करते हुए हिंसक प्रदर्शन किया तो खुद के पंथनिरपेक्षता का रक्षक होने का दावा करने वाली बंगाल की तत्कालीन वामपंथी सरकार ने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेकते हुए तसलीमा को राज्य से बाहर कर दिया। इसके पहले इसी सरकार ने तसलीमा की आत्मकथा के तीसरे खंड 'द्विखंडित' पर रोक लगाकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात किया था। 22 नवंबर, 2007 को तसलीमा कोलकाता से जबरन जयपुर ले जाई गईं और वहां से दिल्ली। वाम मोर्चा के बाद सत्ता में आई और खुद को पंथनिरपेक्षता का चैंपियन कहने वाली ममता सरकार ने भी तसलीमा को कोलकाता आने नहीं दिया। यह तब हुआ, जब बंगाल की विभिन्न संस्थाओं ने तसलीमा को कोलकाता आने के लिए आमंत्रित किया, किंतु वाम मोर्चा और तृणमूल सरकार ने उन्हें कोलकाता आने की अनुमति दी।

करीब दो दशक बाद तसलीमा की कोलकाता वापसी उनका न्यूनतम प्राप्य है। एक तरह से बंगाल में उनके संग सच्ची पंथनिरपेक्षता की वापसी हो रही है और साथ ही फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल खुल रही है। तसलीमा की रचनाओं में सर्वत्र मजहबी कट्टरता और स्त्री-पुरुष विषमता के प्रति प्रतिरोध है। वे प्रतिरोध की नायिका हैं। नास्तिक और बेबाक तसलीमा ने दृढ़तापूर्वक जताया है कि वे मौत के फतवों, अपनी किताबों पर प्रतिबंध और निर्वासन का दंड सह सकती हैं, किंतु कट्टरपंथ के समझ नहीं झुक सकतीं। तसलीमा की एक पुस्तक का शीर्षक है-नारी का कोई देश नहीं। यहां देश का आशय जगह है। यह शीर्षक स्वयं में एक चीख है। निर्वासित जीवन में निःसंगता उनके लिए एक कठोर, भयावह और भोगा हुआ यथार्थ है। उनकी एक अन्य पुस्तक का शीर्षक है-दुखियारी लड़की। यह शीर्षक उनके स्वयं के लिए है। उनकी एक अन्य पुस्तक का शीर्षक है-निर्वासन। यह एक स्त्री की दिल दहला देने वाली कहानी है, जो बांग्लादेश से निर्वासित होने के अलावा उस कोलकाता से भी बाहर की जाती है, जहां रहने के लिए वह व्याकुल है। आशा है कि अब उनकी व्याकुलता खत्म होगी।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

अपनी जड़ों से दूरी की व्यथा सहती रहीं लेखिका। फाइल

ऊर्जा

निरंतरता

शास्त्रों में 'चरैवेति, चरैवेति' की राह सुझाई गई है। इसका अर्थ है चलते रहो-चलते रहो और अथक, अविराम एवं अनवरत चलते रहने का सिलसिला रुके नहीं। इस प्रसंग में देवराज इंद्र राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित को भटकाव और विपत्तियों से निकालकर निरंतर पुरुषार्थ करते रहने की शिक्षा देते हैं। इस मंत्र का सीधा संदेश है गतिशील रहना ही जीवन है। यह निरंतरता अटूट परिश्रम और जीवन मे आने वाली बाधाओं की परवाह किए बिना सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जो व्यक्ति परिस्थितियोंवश हार मान लेता है, उसका भाग्योदय नहीं हो पाता। निरंतरता से ही सफलता के गंतव्य तक की यात्रा संपन्न होती है।

चरैवेति का संदेश जीवन को जड़ता से मुक्त कर उसे अनवरत गतिशीलता, जीवंतता और अंतहीन ऊर्जा से भर देता है। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि मनुष्य की जिजीविषा और उसकी चेतना का महाघोष है। इसे आत्मसात करते हुए यह सदैव स्मरण रहे कि जीवन के संघर्षों और असफलताओं से निराश नही होकर सदैव प्रयासरत रहना ही जीवन को सार्थकता प्रदान करता है। प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से डरकर लक्ष्य से विमुख हो जाना मृत्यु के समतुल्य है। इसलिए आगे बढ़ने की गति में किन्हीं भी परिस्थितियों मे ठहराव नहीं आने देना चाहिए। संपूर्ण सकारात्मकता के साथ यदि निरंतर गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित रखा गया तो हम निश्चित ही असफलताओ को पीछे छोड़कर सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे।

जीवन में प्रत्येक व्यक्ति सफलता तो चाहता है, लेकिन असफलताओं के कुछ थपेड़े उन्हें व्यथित कर देते हैं, जिससे उनके प्रयास निस्तेज पड़ने लगते हैं। स्पष्ट है कि निरंतर प्रयास एवं अविराम गति ही प्रगति एवं सफलता की कुंजी है। इसलिए, चाहे जो स्थिति-परिस्थिति हो, गति ही उचित है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

क्वासर्स का गहराता रहस्य

प्रदीप

क्वासर ब्रह्मांड की चमकीली, शक्तिशाली और रहस्यमय खगोलीय पिंडों में से एक हैं

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) के यूक्लिड स्पेस टेलिस्कोप ने हाल ही में ब्रह्मांड के अब तक के सबसे प्राचीन ज्ञात क्वासर्स समेत 31 नए प्राचीन क्वासर्स की खोज की है, जिनमें से दो क्वासर्स ऐसे हैं, जिनका प्रकाश तब निकला था, जब हमारे ब्रह्मांड की उम्र महज 67 करोड़ साल थी। यानी उस समय ब्रह्मांड आज की तुलना में केवल पांच प्रतिशत ही पुराना था।

इस खोज ने विज्ञानियों को ब्रह्मांड के प्रारंभिक दौर को समझने का नया अवसर दिया है, लेकिन साथ ही कई नए सवाल भी खड़े किए हैं। दरअसल क्वासर्स ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से हैं, जो वास्तव में ऐसी मंदाकिनियों के बीचों-बीच होते हैं, जिनके केंद्र में एक महाविशालकाय ब्लैक होल मौजूद होता है। जब गैस और धूल इस ब्लैक होल की ओर तेजी से गिरती है, तो उससे इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है कि पूरा केंद्र अरबों सूर्यों जितना चमकने लगता है। कई बार एक क्वासर अपनी मंदाकिनी से भी सैकड़ों गुना ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। हालिया खोजे गए क्वासर्स की विशेषता यह है कि ये हमें ब्रह्मांड के बचपन की झलक दिखाते हैं। उस समय ब्रह्मांड एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। शुरुआती अंधकारयुग समाप्त हो रहा था और तारे एवं मंदाकिनियां बनने लगी थीं। इन्हीं से निकली ऊर्जा ने पूरे ब्रह्मांड में फैली हाइड्रोजन गैस को आयनित किया। अब तक विज्ञानियों के पास इस शुरुआती दौर के केवल कुछ ही क्वासर्स की जानकारी थी। यूक्लिड टेलिस्कोप ने केवल डेढ़ वर्ष में ही 31 नए प्राचीन क्वासर्स खोज लिए हैं।

हालांकि इस खोज ने एक पुरानी पहेली को और भी गहरा कर दिया है। महाविशालकाय ब्लैक होलों को बनने और इतना बड़ा होने में बहुत लंबा समय लगना चाहिए। लेकिन अगर ब्रह्मांड के जन्म के केवल 67 करोड़ वर्ष बाद ही इतने विशाल ब्लैक होल मौजूद थे, तो वे इतनी तेजी से कैसे बने? क्या प्रारंभिक ब्रह्मांड में ब्लैक होलों के बनने की प्रक्रिया हमारी वर्तमान समझ से अलग थी? या फिर डार्क मैटर ने इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इन सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। यूक्लिड की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह अंतरिक्ष के बहुत बड़े हिस्से को बेहद संवेदनशील नियर-इंफ्रारेड कैमरों से देख सकता है। इस कारण वह ऐसे धुंधले और बहुत दूर स्थित क्वासर्स को भी ढूंढ पा रहा है, जिन्हें पहले पहचानना लगभग नामुमकिन था। आधुनिक कंप्यूटिंग तकनीकों और मशीन लर्निंग की मदद से इन दुर्लभ पिंडों की पहचान और भी आसान हो गई है।

बहरहाल, यूक्लिड का मिशन अभी जारी है। आने वाले वर्षों में यह और भी अधिक प्राचीन क्वासर्स खोजेगा। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास, पहली मंदाकिनियों और महाविशालकाय ब्लैक होलों के जन्म के बारे में नई जानकारी देगी।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

आतंक पर प्रहार आवश्यक

'दिल्ली दंगे के दोषी' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय दंगों का स्याह सच और दंगाइयों की और अमानवीय प्रकृति को उजागर करता है। वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी से जुड़े पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य आरोपितों को अदालत द्वारा दोषी ठहराया जाना न्याय व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह फैसला स्पष्ट करता है कि हिंसा और साजिश के पीछे ठोस साक्ष्य मौजूद थे, जिसने राजनीतिक संरक्षण और अपराधियों का बचाव करने वाले तत्वों की जवाबदेही तय कर दी है। आतंक पर ऐसा प्रहार आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान राजधानी में इस तरह की भीषण हिंसा भड़काना न केवल आंतरिक सुरक्षा पर हमला, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को प्रभावित करने का एक सुनियोजित प्रयास भी था। इस संवेदनशील मामले में दोषियों पर उनके अपराध के अनुपात में कठोरतम दंड और भारी जुर्माना लगाना चाहिए, ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। इसके साथ ही दंगों से जुड़े अन्य लंबित मामलों का भी त्वरित निपटान बहुत जरूरी है, जिससे पीड़ित परिवारों को सांत्वना मिल सके।

अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

न्याय व्यवस्था में सुधार जरूरी

"अन्याय सरीखा दिखने वाला न्याय" शीर्षक से लिखे गए लेख में राजीव सचान ने भारतीय न्याय व्यवस्था की एक गंभीर समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। कई बार न्याय में देरी, प्रभावशाली व्यक्तियों का प्रभाव, कमजोर जांच और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। वास्तव में न्याय, केवल न्यायालय के अंतिम निर्णय का नाम नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया का नाम है। यदि पुलिस निष्पक्ष जांच न करे, गवाहों पर दबाव डाला जाए, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अच्छे वकील का खर्च न उठा सके या मुकदमे वर्षों तक लंबित रहें तो संविधान द्वारा प्रदत्त न्याय का अधिकार अधूरा रह जाता है। न्यायपालिका पर जनता का विश्वास तभी बना रह सकता है, जब न्यायाधीश पूर्णतः निष्पक्ष, निर्भीक और किसी भी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत प्रभाव से मुक्त होकर निर्णय दें। समय-समय पर कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने न्यायपालिका की पारदर्शिता और जवाबदेही पर प्रश्न उठाए हैं। उदाहरणस्वरूप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के संबंध में 2025 में एक विवाद सामने आया, जिसके बाद उनके आचरण को लेकर जांच शुरू की गई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंतरिक प्रक्रिया के तहत मामले की जांच कराई गई। ऐसे मामलों से यह स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था उतनी ही आवश्यक है जितनी अन्य संवैधानिक संस्थाओं में होती है। न्याय का अर्थ केवल सही निर्णय देना नहीं है, ऐसा निर्णय देना भी है, जिस पर नागरिक भरोसा कर सके। आज आवश्यकता न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की है।

शिवम सिंह, बबेरू, बांदा, उत्तर प्रदेश

मेलबाक्स

सनातन और पंथनिरपेक्षता

'सनातन और सेक्युलरिज्म के द्वंद्व' में लेखक ने भारत की पंथनिरपेक्षता का वर्णन किया है। भारत विविधताओं का देश है। यहां अनेक संस्कृतियां और परंपराएं विकसित हुई हैं। इसी विविधता को सुरक्षित रखने के लिए संविधान ने पंथनिरपेक्षता को राज्य की मूल भावना के रूप में स्वीकार किया। दूसरी ओर, सनातन भारतीय सभ्यता की प्राचीन सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। सनातन धर्म केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं है, यह सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, कर्तव्य और मानव कल्याण जैसे मूल्यों पर आधारित जीवन-दृष्टि है। भारत की सांस्कृतिक पहचान, लोक परंपराएं, त्योहार, दर्शन और आध्यात्मिक चिंतन इसी विरासत से गहराई से जुड़े हैं। लोकतंत्र में आस्था का सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का पालन दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।

हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

18.8 लाख भारतीय छात्र विदेश में अध्ययन कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार। इनमें से लगभग 12.5 लाख छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों या उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं, जबकि करीब सवा छह लाख विद्यार्थी स्कूल स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं।

आजकल

भारतीय उच्च शिक्षा का वैश्विक क्षितिज

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप केंद्र सरकार ने बीते दिनों 15 विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। उच्च शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण नीतिगत पहल है। ऐसे में प्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों के भारतीय कैंपस विद्यार्थियों को वैश्विक पाठ्यक्रम, अनुसंधान संस्कृति, उद्योगोन्मुख शिक्षण और अंतरराष्ट्रीय डिग्री का अवसर अपने ही देश में उपलब्ध कराएंगे। इससे विदेशी शिक्षा की ऊंची लागत और भौगोलिक दूरी जैसी बाधाएं भी कम हो सकती हैं

रोहित प्रियदर्शी
लोक नीति विश्लेषक

देश में ही विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसर स्थापित होने से छात्रों को होगी सुविधा। फाइल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के साथ भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रही है, जहां केवल नए विश्वविद्यालय खोलने की नहीं, बल्कि संपूर्ण शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पुनर्गठित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया सहित अनेक प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिलना एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन माना जा रहा है। मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा जैसे केंद्र अब अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा के नए प्रवेश द्वार बनने की ओर बढ़ रहे हैं।

उम्मीद है कि इससे भारतीय विद्यार्थियों को लगभग आधी लागत पर अंतरराष्ट्रीय डिग्री अनुसंधान सुविधाएं वैश्विक फैकल्टी और छात्र विनिमय कार्यक्रम उपलब्ध होंगे। इससे हर वर्ष विदेश जाने वाले लाखों विद्यार्थियों का आर्थिक बोझ कम हो सकता है और उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण नई गति पकड़ सकता है। किंतु किसी भी बड़े शैक्षणिक परिवर्तन की तरह यह पहल भी केवल अवसरों का द्वार नहीं बल्कि अनेक नीतिगत प्रश्नों और संस्थागत चुनौतियों को भी साथ लेकर आई है। इसलिए इस निर्णय का मूल्यांकन उत्साह और विवेक दोनों के साथ किया जाना चाहिए।

कम खर्च में संभव उच्च शिक्षा : विदेश मंत्रालय और विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि भारतीय विद्यार्थी आज 150 से अधिक देशों में अध्ययन कर रहे हैं। केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि आवास, भोजन, स्वास्थ्य, बीमा, यात्रा और अन्य खर्चों को जोड़ दिया जाए तो हर वर्ष लाखों करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। यह केवल देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है। यह प्रतिभा के प्रवाह का भी प्रश्न है। ऐसे समय में यदि वही विश्वविद्यालय भारत में अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान संस्कृति और वैश्विक डिग्री के साथ उपलब्ध होने लगें तो स्वाभाविक रूप से यह एक बड़ा परिवर्तन होगा। विशेष रूप से उन मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए जिनके बच्चे विदेश में पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आर्थिक सीमाएं उन्हें रोक देती हैं। अब उम्मीद दिखाई देती है।

इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता लागत में संभावित कमी है। उदाहरण के लिए जहां किसी प्रतिष्ठित ब्रिटिश विश्वविद्यालय में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम पर दो करोड़ रुपये तक का व्यय हो सकता है वहीं भारत स्थित उसी विश्वविद्यालय के कैंपस में यह लागत लगभग तीस से चालीस लाख रुपये के बीच रह सकती है। अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में भी इसके दूरगामी प्रभाव दिखाई दे सकते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय लंबे समय से वैश्विक शोध रैंकिंग में सीमित उपस्थिति दर्ज करा पाए हैं। ऐसे में रोजगार बाजार के दृष्टिकोण से भी यह परिवर्तन महत्वपूर्ण है। आज उद्योग जगत केवल डिग्री नहीं, बल्कि समस्या समाधान, क्षमता संप्रेषण, कौशल वैश्विक दृष्टिकोण और अनुसंधान दक्षता की मांग कर रहा है। यदि विदेशी विश्वविद्यालय उद्योग आधारित पाठ्यक्रम इंटर्नशिप और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार हो सकता है।

फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी नहीं की जा सकती। सबसे पहला प्रश्न समान अवसर का है। यदि इन विश्वविद्यालयों की फीस भारतीय निजी विश्वविद्यालयों से भी अधिक रही तो क्या यह अवसर वास्तव में व्यापक सामाजिक वर्ग तक पहुंच पाएगा या केवल आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों तक सीमित रह जाएगा। शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण तभी सार्थक होगा जब वह समावेशी भी हो। दूसरी चुनौती नियामकीय निगरानी की है। विदेशी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही गुणवत्ता मानकों पारदर्शिता छात्र हितों और शुल्क संरचना पर प्रभावी निगरानी भी आवश्यक होगी। केवल ब्रांड नाम के आधार पर किसी संस्थान को स्वतः उत्कृष्ट मान लेना उचित नहीं होगा। भारतीय नियामक संस्थाओं को गुणवत्ता आश्वासन की मजबूत व्यवस्था विकसित करनी होगी।

तीसरी चिंता भारतीय विश्वविद्यालयों के भविष्य को लेकर है। यदि विदेशी संस्थान केवल श्रेष्ठ विद्यार्थियों और श्रेष्ठ शिक्षकों को आकर्षित करेंगे तो क्या इससे घरेलू विश्वविद्यालयों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति कमजोर होगी। दूसरी ओर यदि यह प्रतिस्पर्धा भारतीय संस्थानों को भी पाठ्यक्रम अनुसंधान और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रेरित करती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे शिक्षा तंत्र पर पड़ सकता है। इसलिए इसे प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि क्षमता निर्माण के अवसर के रूप में देखने की आवश्यकता है।

वस्तुतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य भारत को वैश्विक ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करना है। विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य हैं लेकिन यह यात्रा केवल भवन बनाने से पूरी नहीं होगी। इसके लिए उत्कृष्ट संकाय, मजबूत अनुसंधान और पारिस्थितिकी तंत्र उद्योग साझेदारी समावेशी प्रवेश नीति छात्रवृत्ति व्यवस्था और गुणवत्तापूर्ण नियमन की समानांतर आवश्यकता रहेगी। अंततः यह कहा जा सकता है कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन केवल शिक्षा का विस्तार नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा के दर्शन में परिवर्तन का संकेत है।

भारत में भी हो विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था

आज भारत से लाखों छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा रहे हैं। विभिन्न आकलनों के अनुसार, वर्ष 2025 तक उनकी संख्या 12 से 18 लाख के बीच पहुंच चुकी है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया और जर्मनी उनके प्रमुख गंतव्य बने हुए हैं। यह प्रवृत्ति केवल विदेशी डिग्री हासिल करने की आकांक्षा का परिणाम नहीं है, बल्कि गुणवत्ता, अनुसंधान, रोजगार क्षमता और वैश्विक अवसरों की तलाश का भी संकेत है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण अवसरों की सीमित उपलब्धता है, क्योंकि एक ओर आइआइटी, आइआइएम, एम्स और देश के कुछ चुनिंदा संस्थान वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगिता इतनी तीव्र है कि लाखों प्रतिभाशाली विद्यार्थी पर्याप्त योग्यता होने के बावजूद सीटों के अभाव में बाहर रह जाते हैं। परिणामस्वरूप वे ऐसे विश्वविद्यालयों की ओर रुख करते हैं, जहां आधुनिक प्रयोगशालाएं, परियोजना आधारित अधिगम, उद्योग सहभागिता, नवाचार उन्मुख शिक्षण पद्धति और बहुसांस्कृतिक अकादमिक वातावरण उन्हें अपेक्षाकृत अधिक सहजता से उपलब्ध हो जाता है। शिक्षा केवल परीक्षा नहीं होती, वह संभावनाओं का विस्तार भी होती है।

विदेशी विश्वविद्यालयों का दूसरा बड़ा आकर्षण उनकी अकादमिक विविधता और भविष्य उन्मुख पाठ्यक्रम हैं, क्योंकि आज एआइ, साइबर सुरक्षा, जलवायु वित्त, स्पेस पालिसी, गेम डिजाइन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलाजी, रोबोटिक्स और डिजिटल इकोनमी जैसे अनेक विशिष्ट विषय वैश्विक रोजगार बाजार की नई मांग बन चुके हैं, जबकि भारतीय विश्वविद्यालयों में इन क्षेत्रों की उपलब्धता अभी सीमित है। यही कारण है कि छात्र केवल डिग्री नहीं, बल्कि ऐसे कौशलों की तलाश में विदेश जाते हैं जो आने वाले दशक की अर्थव्यवस्था में उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को मजबूत बना सकें। विदेश में अध्ययन का सबसे व्यावहारिक आकर्षण रोजगार बाजार से उसका सीधा संबंध है। वैश्विक विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप, उद्योग सहयोग, कैंपस प्लेसमेंट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक पहुंच अपेक्षाकृत अधिक सुदृढ़ होती है, जिस कारण विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ ही करियर निर्माण का स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है। अंतरराष्ट्रीय डिग्री केवल प्रमाणपत्र नहीं होती, बल्कि वैश्विक कार्य संस्कृति, नेतृत्व क्षमता, बहुसांस्कृतिक संवाद और समस्या समाधान कौशल का प्रमाण भी मानी जाती है। इसी कारण अनेक भारतीय छात्र विदेश से लौटकर देश में भी बेहतर अवसर प्राप्त करते हैं। योग्यता जब अनुभव से जुड़ती है तभी उसका वास्तविक मूल्य बढ़ता है।

विदेश में अध्ययन का प्रभाव रोजगार के साथ ही व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व को भी नया आयाम देता है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच रहना, स्वयं निर्णय लेना, आर्थिक प्रबंधन करना, संवाद कौशल विकसित करना, वैश्विक नेटवर्क बनाना और विविध समाजों के साथ कार्य करना विद्यार्थियों को अधिक आत्मनिर्भर, लचीला और नेतृत्वसक्षम बनाता है। यही स्किल्स आज उद्यमिता, स्टार्टअप संस्कृति और वैश्विक कारपोरेट जगत में सबसे अधिक मूल्यवान मानी जाती हैं।

इन परिस्थितियों में भारत के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि विद्यार्थी विदेश क्यों जा रहे हैं, बल्कि यह है कि उन्हें यहां वही गुणवत्ता, वही अनुसंधान संस्कृति, वही अकादमिक स्वतंत्रता और वही वैश्विक रोजगार क्षमता कब उपलब्ध होगी। यदि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विदेशी विश्वविद्यालयों के भारतीय परिसर, उद्योग-अकादमिक सहयोग, अनुसंधान निवेश, कौशल आधारित पाठ्यक्रम और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को समान गति से आगे बढ़ाया जाता है, तो भारत केवल प्रतिभा भेजने वाले देश के साथ ही वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था का प्रमुख केंद्र भी बन सकता है।

(रोहित प्रियदर्शी)

खरी-खरी

एसी ने कर दी ऐसी की तैसी

विनय कुमार पाठक

एसी को एक समय वरदान माना गया था गरमी से निजात पाने के लिए। वरदान था भी। अभी भी है। पर अब सिर्फ वरदान नहीं रहा। कभी-कभी अभिशाप भी बन जा रहा है। कारण जो भी हो। निम्न गुणवत्ता वाले पार्ट्स, समय पर सर्विसिंग न होना, हमेशा आन रहना। पर कभी-कभी ऐसा अनुभव दे दे रहा है लोगों को, कि मुंह से निकल जाता है एसी की ऐसी की तैसी।

अभी मुंबई लोकल एसी ने कुछ ऐसा ही अनुभव दिया यात्रियों को। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से जब एसी लोकल चली तो सबकुछ ठीक-ठाक था। एसी का आनंद लेते कोई मोबाइल पर गेम खेल रहा था तो कोई अपने लैपटाप पर कोई मूवी देख रहा था। यानी सभी डिजिटल ही थे। इस बीच लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई तब जाकर ध्यान आया कि एसी तो काम कर ही नहीं रहा। यानी यह अब सिर्फ लोकल रह गया था, एसी लोकल नहीं।

मुंबई देश के गिने चुने शहरों में है जो दिन दूनी रात चौगुनी विकास कर रहा है। जैसे अमीर और अमीर होते जाते हैं, अपने देश में वैसे ही बड़े शहर और भी बड़े होते जा रहे हैं। वैसे गरीब और भी गरीब होने के तर्ज पर छोटे शहर और भी छोटे नहीं हो रहे हैं। छोटे शहर भी बड़े हो रहे हैं, पर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों की तेजी से नहीं। तो मुंबई में क्या सेकेंड क्लास, क्या फर्स्ट क्लास और क्या एसी, सभी की स्थिति भीड़ के कारण ऐसी की तैसी हो जाती है। तो एसी कंपार्टमेंट भी खचाखच भरा था। जाहिर है अधिकांश टिकट लेकर बैठे थे। पर कुछ बिना टिकट के भी थे जिन्हें किसी का डर नहीं होता। कंपार्टमेंट भरा होने के कारण टेक्नीशियन स्विच तक पहुंच नहीं पा रहा था। उस कंपार्टमेंट में यात्रा कर रहे लोगों को 'वो पंद्रह मिनट' याद रहेंगे जो उन्होंने भोगा।

एसी कभी हवाई जहाज में रुष्ट होकर यात्रियों को यातना देने लगता है तो कभी बस में, कार में, यहां तक कि घर में ब्लास्ट होकर लोगों को चेता रहा है कि इतना भी भरोसा मत करो मशीन पर। जहां तक संभव हो प्राकृतिक तरीके से शीतल रहने की कोशिश करो।

पोस्ट

देश की राजनीति बदलने वाली है। बंगाल चुनाव से पहले सरकार संविधान संशोधन विधेयक पर हार गई थी। केजरीवाल, ममता और ठाकरे के सांसद तोड़े गए। परिसीमन की तैयारी हो चुकी है। संख्या बल भी पूरा है। फिर आएगा संविधान संशोधन विधेयक और लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। विपक्ष के सामने एक और चुनौती आने वाली है!

आदेश रावल@AadeshRawal

मेरी निजी राय हमेशा से परिसीमन और ऐसी संसद के पक्ष में रही है, जो सच में लोगों की ताकत को दर्शाती हो, प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ संसद और विधानसभाओं में कामकाज के दिनों की संख्या भी बढ़नी चाहिए।

प्रियंका चतुर्वेदी@priyankac19

अंकित शर्मा हत्याकांड में कुछ कथित 'फेंडेड फैक्ट-चेकर्स' और 'पत्रकार' होने का दिखावा करने वाली 'जुल्म-जख्म गैंग' की दो प्रमुख महिलाओं ने हत्यारे ताहिर को बचाने में शर्मनाक भूमिका निभाई। एक और 'एंकर' ने भी इस पेशे को शर्मसार किया। दिल्ली पुलिस को इन झूठों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए।

स्वाति चतुर्वेदी@bainjal

जागरण जनमत — कल का परिणाम

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में कलह से पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी?

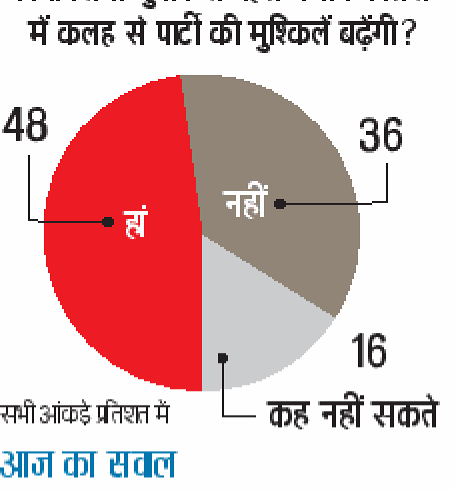

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

काशी, मथुरा, संभल के धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को सुप्रीम कोर्ट को हल करना चाहिए?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

अब्दुल्ला परिवार को नहीं भा रही शांति,
उमर शिगूफे छोड़कर करना चाहें क्रांति।
करना चाहें क्रांति पिताजी लिखते चिट्ठी,
पुत्र उमर बक झूठ पढ़ाते सबको पट्टी।
बीजेपी के संग जायगा क्यों कठमुल्ला,
सौ फीसद बकवास कर रहे हैं अब्दुल्ला!

-ओम प्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

भाजपा की चिंता, बिल्ली ने घर का रास्ता देख लिया

सद्गुरु शरण
संपादक, नईदुनिया, मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़

हम 'पार्टी विद डिफरेंस' हैं, भाजपा ने यह दावा पिछली सदी के अंतिम वर्षों में केंद्र में अपनी सरकार बनने के बाद ही बंद कर दिया था। यद्यपि गत 10 जुलाई को प्रदेश के दतिया में भाजपा कार्यकर्ताओं (जिन्हें शर्म में डूबी पार्टी अपना कार्यकर्ता स्वीकार करने के बजाय नरोत्तम मिश्रा के समर्थक बता रही है) ने जो कुछ किया, उसकी कल्पना भाजपा नेतृत्व ने नहीं की होगी। नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव का टिकट नहीं मिलने पर तमतमाए कार्यकर्ताओं ने रातभर हाईवे जाम करके जो अराजकता फैलाई, वह अपनी जगह है। हद तब हो गई, जब इन कार्यकर्ताओं या नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए मुर्दाबाद और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव के लिए मां-बहन की गालियों के नारे लगाए।

वैसे नरोत्तम मिश्रा स्वयं इस अराजक प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, लेकिन उन्होंने अब तक ऐसा भी नहीं कहा कि प्रदर्शनकारी उनके समर्थक नहीं थे। इन प्रदर्शनकारियों ने रातभर ग्वालियर-झांसी हाईवे जाम करके निर्दोष लोगों को परेशान किया। पुलिस ने करीब 12 घंटे बाद सुबह अपने डंडे तब सीधे किए, जब प्रदर्शनकारियों के पत्थर कलेक्टर के हेलमेट पर आ लगे और कई पुलिस अधिकारियों की वर्दी उनके खून से रंग गई। पुलिस के डंडे पड़ते ही यह आक्रामकता ठंडी पड़ गई, लेकिन अपने पीछे ऐसी कथा छोड़ गई जिसे भाजपा नेतृत्व भूल जाना चाहेगा। वैसे यह आसान नहीं है। मुर्दाबाद और गालियों के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं और भाजपा के प्रतिपक्षी जमकर मजे ले रहे हैं। क्या भाजपा या नरोत्तम मिश्रा के पास प्रायश्चित करने का कोई उपाय है?

नरोत्तम मिश्रा को प्रत्याशी न बनाने के विरोध में ग्वालियर-झांसी हाईवे पर जाम लगाते समर्थक। फाइल

वस्तुतः दतिया विधानसभा सीट पर इसी महीने उपचुनाव होने जा रहा है। इस सीट पर वरिष्ठ भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा वर्ष 2008 से 2018 तक लगातार तीन चुनाव जीते, पर हर चुनाव में घटता उनकी जीत का अंतर उनके अलोकप्रिय होते जाने के संकेत दे रहा था, फिर भी सत्ता के नशे में डूबे मिश्रा जी जन-मन की थाह नहीं ले पाए। अंततः पानी सर के ऊपर बहने लगा और वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए अनुकूल परिस्थिति के बावजूद वह चुनाव हार गए। हारने के बाद भी वह नरम नहीं पड़े। चुनाव बाद जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक होकर प्रायश्चित करने के बजाय वह अक्सर बुलंद स्वर में एक कविता दोहराते रहते थे जिसमें वह लगभग धमकाने की शैली में स्वयं को समंदर बताकर कहते थे कि मेरा पानी उतरता देखकर मेरे किनारे घर मत बना लेना, मैं लौटकर आऊंगा।

इधर दतिया के लोग उनकी बातें चुपचाप सुनते रहे। इस बीच मिश्रा जी ने पार्टी की मुख्यधारा में वापसी के लिए हर कोशिश की, पर नेतृत्व ने उन्हें कोई भाव नहीं दिया। वह इसके संकेत भी नहीं समझ पाए और अपने तौर-तरीकों पर अडिग रहे। दतिया उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होते ही उन्होंने स्वतः स्फूर्त प्रचार कार्य शुरू कर दिया, पर 10 जुलाई को उनके बजाय पार्टी के अनुशासित एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता आशुतोष तिवारी को टिकट मिलते ही उनके समर्थक आपा खो बैठे और अकल्पनीय आचरण करने लगे। दो दिन बाद मिश्रा जी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मिले और पार्टी के प्रति अपनी वफादारी की कसमें खाईं, यद्यपि पार्टी के सूत्र बताते हैं कि उनके समर्थकों के बुलंद नारों की ध्वनि दिल्ली दरबार तक पहुंच गई थी जिसके बाद मिश्रा जी को अल्टीमेटम दिया गया कि 24 घंटे के भीतर सबकुछ ठीक नहीं हुआ तो पार्टी अपने ढंग से हालात नियंत्रित करेगी। इस बार मिश्रा जी को सबकुछ आसानी से समझ में आ गया। अब वह सभा मंच पर आंखों में आंसू भरकर आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए घर-घर जाकर माथा टेकने की दुहाई दे रहे हैं।

टिकट न मिलने पर विरोध प्रदर्शन कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। अन्य दलों की तरह भाजपा में भी ऐसा होता रहता है, पर अनुशासन की परिधि के भीतर। 10 जुलाई की शाम और रात दतिया में जो कुछ हुआ, उसकी नजीर कम से कम भाजपा में तो नहीं मिलती। भाजपा नेतृत्व को यह चिंता सता रही होगी कि यदि इस घटना को नजरअंदाज किया गया तो भविष्य में अन्य प्रसंगों में इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है जो पार्टी के लिए कतई ठीक नहीं होगा। शायद उपचुनाव देखते हुए नेतृत्व शांत है, पर चुनाव पूरा होते ही पार्टी कड़ा रुख दिखाएगी, ऐसी संभावना है। दरअसल, भाजपा नेतृत्व को यह अफसोस नहीं है कि बिल्ली दूध पी गई, पार्टी की असली चिंता यह है कि बिल्ली ने घर का रास्ता देख लिया।

हिमाचल प्रदेश डायरी

हार्मनी आफ पाइन्स और आचरण संहिता

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

कभी समोसे को सरकारी संपत्ति बता कर जांच कर चुकी हिमाचल प्रदेश पुलिस इन दिनों एक अन्य महत्वपूर्ण जांच कर रही है। जांच यह है कि प्रदेश पुलिस के म्यूजिकल बैंड/ आर्केस्ट्रा 'हार्मनी आफ पाइन्स' के प्रमुख, इंस्पेक्टर विजय कुमार ने इंटरनेट मीडिया से कमाई की और कुछ वीडियो एल्बम निजी तौर पर बनाए जिनसे उन्हें आय हुई। जांच का कोण यह भी है कि क्या वीडियो एल्बम बनाने से पहले उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से अनुमति ली थी? विजय कुमार के आचरण को नियमों के विरुद्ध मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच जारी है। क्योंकि विषय अन्वेषणाधीन है, इसलिए निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्या पता जांच की पुस्तिका में कौन पन्ना मुड़ा हुआ निकले। इस बीच एक शासकीय आदेश यह भी आया है कि सभी विभाग प्रमुख ऐसे कर्मचारियों की सूची भेजें जो अन्य स्रोतों से कमाई कर रहे हैं। यानी सख्ती... जो सब पर हो तो अच्छी।

हार्मनी आफ पाइन्स का अर्थ है चीड़ों की मधुर स्वर संगति। इसकी स्थापना 1996 में इस उद्देश्य से हुई कि पुलिस कर्मचारियों का मनोरंजन हो। 2016 में इसे पुनर्जीवित किया गया और 2017-18 में जब संजय कुंडू पुलिस महानिदेशक बने तो उन्होंने इसे पेशेवर रुख देते हुए पुलिस के अच्छे गाने-बजाने वाले लोग शामिल किए। बात ऐसी निकली कि फिर दूर तलक जा पहुंची। कलर्स टीवी के 'हुनरबाज देश की शान' के फाइनल तक पहुंचे। बैंड पर डाक टिकट का प्रकाशन हुआ। गोवा के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हुनर दिखाया। हाउस आफ लार्ड्स के भवन में किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था ने विजय कुमार को सम्मानित किया। इंडिया, एशिया और वर्ल्ड बुक आफ रिकार्ड में भी स्थान मिला।

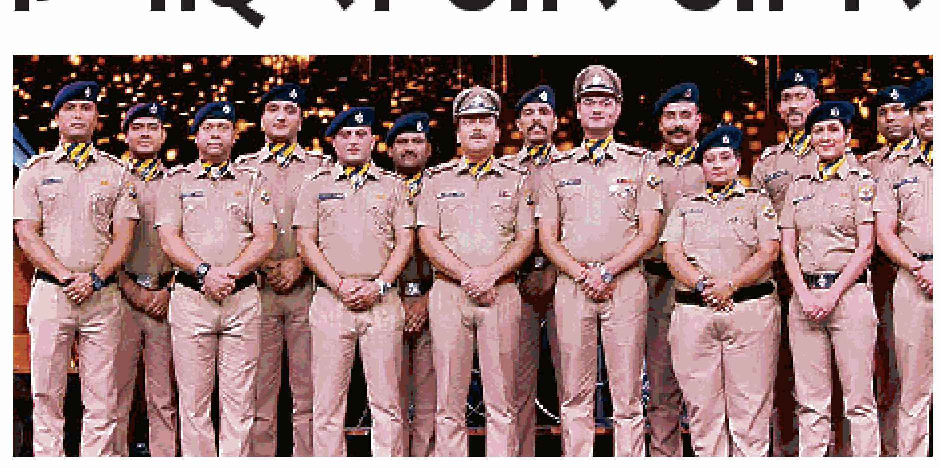

इंस्पेक्टर विजय कुमार (प्रथम पंक्ति में बाएं से पांचवें) के साथ हार्मनी आफ पाइन्स का दल। फाइल

हालांकि, यह सैद्धांतिक रूप से गहन विमर्श का विषय है कि पुलिस की मूल पहचान कानून व्यवस्था के लिए होनी चाहिए या अच्छा गाने बजाने के लिए। बैंड की सेवाएं पैसे देकर कोई भी ले सकता है। कुछ शादियों या अन्य नितांत निजी कार्यक्रमों में जाम दर जाम और प्लेटों की खनखनाहट में बैंड के सदस्य बावर्ची, मेजबान और उसके परिवार की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे। यह देख कर जो भावना आई, उसके लिए उपयुक्त शब्द आज तक नहीं मिले। खैर, जब समूह का सृजन हो ही गया, और इतनी उपलब्धियां खाते में आ ही गईं तो कहा जा सकता है कि विजय को सिस्टम ने प्रोमोट किया, तब वह यहां तक पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के चिट्टा प्रतिरोधी अभियान में भी इस बैंड ने भीड़ को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

लेकिन आह... हार्मनी आफ पाइन्स! चीड़ ने हिमाचल की जैव विविधता को कितना नुकसान दिया है, उस विषय पर फिर कभी, लेकिन इसकी एक विशेषता यह होती है कि जब तापमान बढ़ता है तो इसकी पत्तियां झुलसने लगती हैं। संभवतः विभाग के आंतरिक ऋतुचक्र परिवर्तन के प्रभाव हार्मनी आफ पाइन्स पर पड़ने लगे हों। अन्यथा, विजय कुमार तो फेसबुक से कमाए छह हजार रुपये जमा करवा चुके थे। वीडियो के बारे में कह चुके थे कि वर्दी में नहीं बनाई और भविष्य की सारी कमाई सरकार को दे दूंगा। नियम यह कहता है कि सरकारी अधिकारी ऐसे किसी स्रोत से कमाई करे तो एक तिहाई सरकारी खजाने में देना चाहिए। यह नियम तो फिर उन सरकारी अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए जो सरकारी उपक्रमों के सदस्य इसलिए होते हैं, क्योंकि वे प्रदेश सरकार के अधिकारी होते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा सचिव, एसजेवीएनएल के पैनल में होता है। वार्षिक सम्मेलन में सूट और धन मिलता है। क्या किसी सचिव ने एक तिहाई धन जमा करवाया? वैध और अवैध कमाई की जांच होती आई है, गुप्त कमाई की जांच कौन करेगा?

हिमाचल प्रशासनिक सेवा में क्या उदाहरण नहीं जहां काम से अधिक रील पर अदाओं से फालोवर जुटाए जाते हैं? और तो और ब्रांड प्रोमोशन भी हुई है, लेकिन आह को चाहिए इक उम्र असर होने तक...।

दो नावों के सवार के साथ क्या होता है, यह रहस्य नहीं। जब विभाग में परस्पर प्रतिद्वंद्वी हवाओं में ठन गई और लू ही चलने लगी, तब विजय कुमार ने नौ माह पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया जिसे यह कह ठुकराया गया कि ऐसे लोग नहीं मिलते, इससे पुलिस विभाग की छवि पर असर पड़ेगा आदि, इसलिए इन्हें वीआरएस नहीं दी जा सकती। अब वही व्यक्ति जांच का सामना कर रहा है। आचरण संहिता के अपने दुख हैं, क्योंकि इसकी जद में वही लोग आते हैं, जिन्हें लाया जाना होता है। अन्यथा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य करने वालों को तो लिखित छूट थी। संभव है, उन पंक्तियों की स्याही फीकी पड़ गई हो। वैसे मामला कोई 'अति गंभीर श्रेणी' का ही लगता है, क्योंकि निलंबन भी हो गया। निलंबन का अर्थ है व्यक्ति को अस्थाई रूप से दायित्व से मुक्त रखना, 50 प्रतिशत वेतन देना, बहाली पर पिछला वेतन भी देना, यह सरकार पर बोझ होता है। नियमानुसार निलंबन किसका होता है, यह नियमावली में स्पष्ट है।

वैसे बैंड का नाम हार्मनी आफ सिडार्स (देवदार) होता तो भी विभागीय मौसम का प्रभाव ऐसा ही होता? सोचिएगा। अच्छा यही है कि जांच के निष्कर्ष की प्रतीक्षा करें।

इंडियन गैस एक्सचेंज ने आइपीओ के लिए जमा किए दस्तावेज

नई दिल्ली: इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड (आइजीएक्स) ने आइपीओ के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा किए हैं। आइजीएक्स, देश का पहला आनलाइन डिलीवरी-आधारित प्राकृतिक गैस बिजनेस प्लेटफार्म है। प्रस्तावित आइपीओ पूरी तरह बिक्री पेशकश पर आधारित होगा। इसके तहत प्रमोटर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 1.67 करोड़ तक शेयर बेचेगी। निर्गम से मिलने वाली पूरी राशि शेयर बेचने वाली कंपनी आईईएक्स को जाएगी। (प्रेट्र)

आने वाले सालों में, इस्तेमाल होने वाली अलग-अलग तरह की टेक्नोलाजी को आसान बनाने से ही यह तय होगा कि कौन सफल होगा और कौन नहीं।
– **ब्लेक मोरेट, चेयरमैन और सीईओ, राकवेल आटोमेशन**

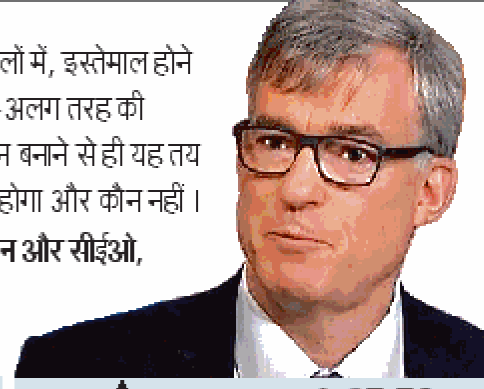

संसेक्स	77,185.43	▲ 130.49	
निफ्टी	24,078.50	▲ 26.45	
सोना	₹1,46,300	बदलाव नहीं	प्रति दस ग्राम
चांदी	₹ 2,26,000	▼ ₹ 100	प्रति किलो ग्राम
डालर	₹ 96.25	▲ ₹ 0.09	
क्रूड	$ 85.50		प्रति बैरल

एक नजर में

ग्रो की पैरेंट कंपनी का शुद्ध लाभ 94 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली: डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफार्म ग्रो की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेन्स गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 94.3% बढ़कर 735.04 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 378.35 करोड़ का शुद्ध लाभ हुआ था। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 66% बढ़कर 1,501.42 करोड़ हो गया जो एक साल पहले 904.40 करोड़ रुपये था। कुल खर्च एक साल पहले की अवधि के 444.67 करोड़ से 555.69 करोड़ हो गया। (प्रेट्र)

क्यूब हाईवेज के इनविट का मूल्य दायरा तय

नई दिल्ली: क्यूब हाईवेज ट्रस्ट ने 5,000 करोड़ रुपये के सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) निर्गम के लिए मूल्य दायरा 151-152 रुपये प्रति यूनिट तय किया है। निर्गम 22 को खुलेगा और 24 जुलाई को बंद होगा। यह निर्गम बिक्री पेशकश पर आधारित है। सेबी में पंजीकृत इनविट क्यूब हाइवेज ट्रस्ट के पास 31 मार्च, 2026 तक 12 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में फैली 8,754 लेन किलोमीटर लंबी 27 परिचालन सड़क परिसंपत्तियों का खंड था। (प्रेट्र)

एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन होंगे राजीव कुमार

नई दिल्ली: आरबीआइ ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने को मंजूरी प्रदान कर दी है। उनकी नियुक्ति 15 जुलाई यानी बुधवार से प्रभावी हो गई। बैंक ने कहा है कि अंतरिम चेयरमैन केकी मिस्त्री गैर कार्यकारी निदेशक बने रहेंगे। राजीव कुमार भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और वित्त सचिव रह चुके हैं। 2017 से 2020 के बीच वित्तीय सेवा विभाग के सचिव के तौर पर कुमार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को फिर से मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी। (प्रेट्र)

पहले दिन ब्रिटेन गया 14 करोड़ डालर का माल

भारत और ब्रिटेन के बीच कंप्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर अमल शुरू

- निर्यातकों का दावा-कुल 40-50 करोड़ डालर का माल ब्रिटेन भेजा गया
- प्रतिमाह कम से कम 20 प्रतिशत अधिक अपैरल का निर्यात होने की उम्मीद

ट्रेड डील के अमल में आने के बाद बुधवार को जयपुर से ब्रिटेन भेजे जाने वाले सामान के साथ निर्यातक व अधिकारी ● एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : भारत एवं ब्रिटेन के बीच 15 जुलाई से कंप्रेहेंसिव इकोनमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (सीटा) पर अमल शुरू हो गया। बुधवार को वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बताया कि अमल के पहले दिन 14 करोड़ डालर का सामान निर्यात करने की सूचना प्राप्त हुई है। हालांकि निर्यातकों का दावा है कि रोजगारपरक सेक्टर टेक्सटाइल, लेदर फुटवियर, जेम्स और ज्वैलरी जैसे आइटम को जीरो शुल्क पर माल डिलिवरी के लिए पहले ही अच्छी मात्रा में आर्डर मिल चुके थे, इसलिए अमल के पहले दिन ब्रिटेन 40-50 करोड़ डालर का माल निर्यात हुआ है। भारत ब्रिटेन में सालाना 13 अरब डालर का वस्तु निर्यात करता है।

फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के सीईओ व महानिदेशक अजय सहाय ने बताया कि पहले दिन 40-50 करोड़ डालर के निर्यात पर शक नहीं होना चाहिए। जेम्स व ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक ब्रिटेन को होने वाले उनके निर्यात में इस व्यापार समझौते के बाद तीन गुना बढ़ोतरी हो सकती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए.शक्तिवेल ने बताया कि पहले की तुलना में अब प्रतिमाह कम से कम 20 प्रतिशत तक अधिक अपैरल का निर्यात ब्रिटेन को होगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को भी इस समझौते से ब्रिटेन में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी की पूरी उम्मीद है। बुधवार को वाणिज्य सचिव और ब्रिटेन की उच्चायुक्त के समक्ष विभिन्न एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने अपने-अपने निर्यात को लेकर जानकारी दी। अग्रवाल ने बताया कि इस समझौते को करने में दोनों देशों के बीच 800 टेक्निकल सत्र किए गए। पिछले साल जुलाई में दोनों देशों ने सीटा पर हस्ताक्षर किए थे और कुछ माह पहले ही सीटा पर अमल की तारीख तय हो गई थी। निर्यातकों ने बताया कि इसका फायदा यह हुआ कि उन्हें जीरो शुल्क पर डिलिवरी के लिए पहले ही काफी आर्डर मिल गए हैं। गारमेंट, फुटवियर, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स व ज्वैलरी जैसे आइटम का निर्यात पहले से ब्रिटेन में हो रहा है, इसलिए इन सेक्टर के निर्यातकों को वहां खरीदार की तलाश नहीं करनी है। उनके खरीदार को अब ये माल कम दाम पर मिलेंगे।

950 अरब डालर का सालाना आयात करता है ब्रिटेन

ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था का आकार भले ही भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार से छोटा है, लेकिन ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय 40,000 डालर से अधिक है और वहां के लोगों की क्रय क्षमता काफी अधिक है। इसलिए ब्रिटेन 950 अरब डालर का सालाना आयात करता है। प्रोसेस्ड फूड व कृषि पदार्थों के लिए ब्रिटेन का बाजार खुलने से किसानों को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है।

उत्कृष्टता का मापदंड है भारत-ब्रिटेन के बीच एफटीए: ब्रिटिश उच्चायुक्त

भारत और ब्रिटेन के बीच बुधवार से लागू हुए एफटीए को ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने व्यापार समझौतों का नया स्वर्ण यानी उत्कृष्टता का मापदंड बताते हुए कहा कि यह समझौता दुनिया को नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था प्रभावी होने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि समझौता द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डालर तक ले जाने में मदद करेगा।

भारत-ब्रिटेन एफटीए से किसानों और एमएसएमई को होगा लाभ

नरेन्द्र मोदी ●

- पीएम मोदी ने कहा-समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे
- सामाजिक सुरक्षा समझौता भारतीय कारोबारियों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने को दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया और कहा कि इससे आर्थिक संबंधों को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों समझौतों से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे तथा दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षा लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेगी।

मोदी ने कहा कि सीईटीए से किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को नई गति मिलेगी। साथ ही कई प्रमुख क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक अधिक मजबूत पहुंच प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को भी गहरा करेगा तथा कुशल भारतीय प्रतिभाओं की अधिक आवाजाही को बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म 'एक्स' पर लिखा, 'यह भारत-ब्रिटेन साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (सीईटीए) तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होने से हमारे आर्थिक संबंध और अधिक गहरे होंगे। ये दोनों समझौते मिलकर हमारी साझा महत्वाकांक्षा को हमारे लोगों के लिए ठोस अवसरों में बदलेंगे।'

मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहयोग प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, 'यह क्षण हमारे देशों के बीच विश्वास और व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश एवं नवाचार से प्रेरित भविष्य की साझेदारी बनाने के हमारे संकल्प को दर्शाता है। भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।' सीईटीए पर पिछले साल जुलाई में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता 2030 तक दोनों देशों के बीच मौजूदा अनुमानित 48 अरब पाउंड के सालाना व्यापार को कम से कम दोगुना करने में मदद करेगा।

भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से रोजगारपरक सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और देश के 99 प्रतिशत निर्यात को शून्य शुल्क पर वहां की बाजारों में पहुंच मिलेगी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम है। –**अमित शाह**, गृह मंत्री

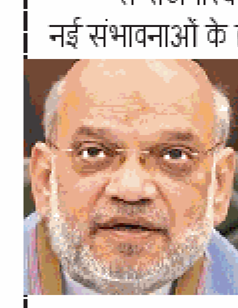

11 लाख टन से अधिक इस्पात के शुल्क मुक्त निर्यात की सुविधा मिलेगी

व्यापार समझौता लागू होने के साथ ही भारतीय निर्यातक अब हर साल 11 लाख टन से अधिक इस्पात का ब्रिटेन को शुल्क-मुक्त निर्यात कर सकेंगे। ब्रिटेन द्वारा मार्च में लागू किए गए इस्पात सुरक्षा उपाय 24 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षरित सीईटीए के क्रियान्वयन में प्रमुख अड़चन बन गए थे। इस मुद्दे के समाधान के बाद 15 जुलाई से समझौते को लागू करने का रास्ता साफ हो गया। वर्ष 2025 में भारत का कुल इस्पात निर्यात 96 करोड़ डालर का था।

अप्रैल-मई में चालू खाता अधिशेष 2.8 अरब डालर रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: विदेश से आने वाले रेमिटेंस में वृद्धि और सेवा निर्यात में बढ़ोतरी से अप्रैल-मई, 2026 में भारत का चालू खाता अधिशेष (सरप्लस) 2.8 अरब डालर रहा।

आरबीआइ के मुताबिक-पिछले साल की समान अवधि में 4.1 अरब डालर का घाटा हुआ था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष के पहले दो महीनों में देश का कुल बैलेंस आफ पेमेंट (भुगतान संतुलन) 11 अरब डालर के घाटे में रहा जबकि पिछले साल इसी अवधि में पांच अरब डालर का सरप्लस था। 2026-27 के पहले दो महीनों में वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 55.9 अरब डालर हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 49.7 अरब डालर था। इस दौरान आयात 127.1 अरब डालर से बढ़कर 146.5 अरब डालर हो गया, जबकि निर्यात 77.4 अरब डालर से बढ़कर 90.7 अरब डालर हो गया।

पहली तिमाही में यात्री वाहनों की रिकार्ड बिक्री

मजबूत मांग और जीएसटी की कम दरों के चलते बिक्री में वृद्धि दर्ज की गई, पिछले साल थोक बिक्री 10,11,884 इकाई रही थी

पश्चिम एशिया में व्यवधानों से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सभी वाहन श्रेणियों का मजबूत प्रदर्शन घरेलू मांग के समर्थन, जीएसटी की कम दरों, वित्तपोषण लागत में नरमी, कम आधार प्रभाव और नए माडल की पेशकश का परिणाम है।
–**शैलेश चंद्रा**, प्रेसिडेंट, सियाम

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश में चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 25.9 प्रतिशत बढ़कर रिकार्ड 12,73,811 इकाई रही। उद्योग संगठन सियाम ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया युद्ध से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद मजबूत घरेलू मांग के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 10,11,884 इकाई रही थी। वहीं इससे पहले 2024-25 की अप्रैल-जून तिमाही में रिकार्ड करीब 10.3 लाख इकाई की बिक्री दर्ज की गई थी।

सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल (सियाम) के अनुसार, पहली तिमाही में दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री 20.3 प्रतिशत बढ़कर 56,28,675 इकाई रही, जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 46,77,990 इकाई थी। जून में दोपहिया वाहनों की कुल थोक बिक्री 18.6 प्रतिशत बढ़कर 18,51,400 इकाई हो गई, जो जून 2025 में 15,61,283 इकाई थी। तिपहिया वाहनों की थोक बिक्री भी पहली तिमाही में अब तक के उच्चतम स्तर 2,14,339 इकाई पर पहुंच गई।

यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की 1,65,211 इकाई की तुलना में 29.7 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री भी सर्वाधिक 2.65 लाख इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 18.3 प्रतिशत अधिक है। इस बीच, घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून में सालाना आधार पर 24.1 प्रतिशत बढ़कर 3,88,144 इकाई रही। यात्री वाहनों की थोक बिक्री जून 2025 में 3,12,851 इकाई थी।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

तीन साल में सबसे कम रही जून तिमाही में चीन की वृद्धि दर

हांगकांग, आइएएनएस: चीन की अर्थव्यवस्था अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 4.3 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह पिछले तीन वर्षों से अधिक समय में सबसे धीमी वृद्धि दर है। सरकारी आंकड़े पूर्वानुमानों से कम और जनवरी-मार्च तिमाही में दर्ज पांच प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर की तुलना में भी नीचे रहे।

यह स्थिति ऐसे समय में रही, जब एआइ के तेजी से बढ़ते उपयोग के दम पर और चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों की मजबूत वैश्विक मांग के कारण निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। अमेरिका-ईरान संघर्ष से ऊर्जा कीमतों में तेज वृद्धि से वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक असर नहीं पड़ा। वर्ष की पहली छमाही में चीन का निर्यात सालाना आधार पर 17.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि जून में इसमें 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

राष्ट्रीय फलक

देश के सबसे बड़े परमाणु उर्जा संयंत्र से संवेदनशील डाटा लीक

- तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का मामला
- डार्क वेब पर गोपनीय दस्तावेज अपलोड करने का किया गया दावा

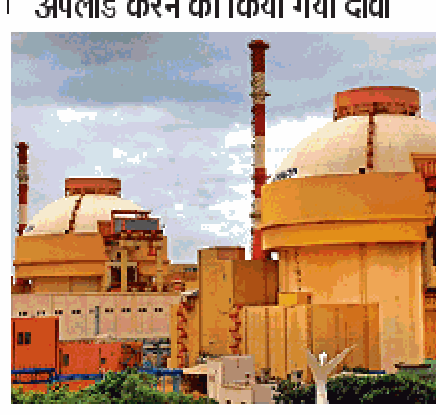

कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। फाइल

बेंगलुरु, रायटर: देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से संवेदनशील डाटा चोरी किए जाने का दावा किया गया है। 'वर्ल्ड लीक्स' नामक एक कुख्यात रैनसमवेयर समूह ने दावा किया है कि उसने प्लांट में कांट्रैक्टर के रूप में काम कर रहे अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की करीब 8,58,000 फाइलें चुराई हैं और उन गोपनीय दस्तावेजों को डार्क वेब पर पोस्ट किया है। इन दस्तावेजों में संयंत्र के कुछ हिस्सों के कथित ब्लूप्रिंट, सप्लायर्स की जानकारी, बैठकों के ब्योरे और बीमा दस्तावेज शामिल बताए जा रहे हैं।

इस खबर के आने के बाद न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआइएल) ने कहा है कि इससे परमाणु सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। एनपीसीआइएल के कार्यवाहक चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश वी ने कहा कि ये मामले प्लांट सिस्टम के सामान्य सर्विस बैलेंस से जुड़े हैं, जिनका न्यूक्लियर सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि फाइलें संयंत्र की सामान्य सेवाओं से जुड़ी हैं, जिनका मुख्य परमाणु सुरक्षा प्रणालियों से कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि सरकारी कंपनी न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड देश में कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने और चलाने के लिए ज़िम्मेदार एकमात्र संस्था है।

वर्ल्ड लीक्स' नाम के एक रैंसमवेयर ग्रुप ने डार्क वेब पर कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़ी फाइलें पोस्ट की हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें न्यूक्लियर प्लांट की सुविधाओं के कुछ हिस्सों के कथित ब्लूप्रिंट और सप्लायर की जानकारी शामिल थी। कुडनकुलम भारत के सात न्यूक्लियर प्लांट में सबसे बड़ा है, जिसकी कुल क्षमता 6,000 एमडब्ल्यू है। रिपोर्ट में प्लांट के एक कांट्रैक्टर के हवाले से कहा गया है कि देश में एक थर्ड-पार्टी योट्टा डाटा सेंटर द्वारा होस्ट किए गए उसके सर्वर डाटा में आंशिक सेंध लगी थी, हालांकि यह नहीं बताया गया कि कौन सा डाटा लीक हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रोथ ने कहा कि इस सेंध से प्लांट की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्स रूस की सरकारी कंपनी रोसाटाम द्वारा सप्लाई किए गए न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर सिस्टम से जुड़े नहीं लगते हैं। इस बीच, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और संबंधित सरकारी एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारियों की ओर से अभी तक इस कथित डाटा लीक की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत टिप्पणी जारी नहीं की गई है।

दूसरी बार कुडनकुलम संयंत्र पर साइबर हमला

इस डाटा लीक में शामिल रैंसमवेयर ग्रुप 'वर्ल्ड लीक्स' अपनी वेबसाइट पर चोरी किया गया कार्पोरेट डाटा पोस्ट करने के लिए कुख्यात है। यह ऐसा तब करता है, जब कंपनियां उसे फिरौती देने से अन्कार करती हैं। इसकी वेबसाइट केवल एक खास ब्राउजर से ही एक्सेस की जा सकती है। यह दूसरी बार है जब कुडनकुलम प्लांट में साइबर हमले की खबर आई है। 2019 में एनपीसीआइएल ने कहा था कि उसने अपने एक कंप्यूटर में मैलवेयर का पता लगाया है। हालांकि, उसने जोर देकर कहा था कि प्लांट के सिस्टम प्रभावित नहीं हुए थे।

जींद से 'ग्रीन' क्रांति: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री

राज्य ब्यूरो, जागरण ● चंडीगढ़

- हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को 26 हजार 800 करोड़ रुपये की देंगे सौगात
- दिल्ली-कटरा एक्सप्रेस-वे का होगा उद्घाटन, 14 नहीं छह घंटे में तय होगा सफर
- जींद में सीधे जंक्शन के पास लैंड कर सकता है पीएम का हेलीकाप्टर

पीएम नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को उत्तर भारत के विकास को नई रफ्तार देते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को 26,800 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सबसे बड़ा आकर्षण जींद-सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित ट्रेन होगी, जिसकी तस्वीरें पीएम ने 'एक्स' पर साझा की हैं।

प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार सुबह 11:00 बजे जींद पहुंचेंगे। सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने उनके रूट प्लान में बदलाव किया है। इस संबंध में बुधवार को माक ड्रिल भी की। संभावना है कि पीएम सीधे रेलवे जंक्शन पर उतरकर हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर एकलव्य स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। जींद के बाद पीएम दोपहर 1:45 बजे चंडीगढ़ और फिर वहां से जालंधर (पंजाब) के लिए रवाना होंगे।

तीनों क्षेत्रों को मिलने वाली प्रमुख सौगातें

हरियाणा (14,700 करोड़): हाइवे और मेडिकल का जाल

दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे: 9,680 करोड़ की लागत से बने 157.92 किमी लंबे इस मार्ग के खुलने से दिल्ली से कटरा का सफर 14 घंटे से घटकर मात्र छह घंटे रह जाएगा। 33.81 किमी लंबे अंबाला-कालाअंब हाईवे और जींद-गोहाना ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन होगा। भिवानी में पं. नेकीराम शर्मा मेडिकल कालेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कालेज का लोकार्पण होगा। कुरुक्षेत्र में सिख संग्रहालय की आधारशिला रखी जाएगी।

चंडीगढ़ (6600 करोड़): पीजीआइ में न्यूरो-मदर चाइल्ड सुपर स्पेशियलिटी

पीजीआइएमईआर: 6600 करोड़ के बजट से पीजीआइ में 300 बेड का 'एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर' व 'एडवांस्ड न्यूरोसाइंसेज सेंटर' का उद्घाटन होगा, जहां न्यूरो की तमाम सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेंगी। आइटी सिटी से कुराली तक छह-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन होगा।

पंजाब (5470 करोड़): धार्मिक स्थलों की राह आसान

अमृत भारत स्टेशन: जालंधर से पीएम देश के 20 राज्यों में पुनर्विकसित किए गए 75 आधुनिक रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिन्हें 1570 करोड़ से संवारा गया है।

धार्मिक पर्यटन: दौलतपुर चौक-करटोली नई रेल लाइन शुरू होने से माता चिंतपूर्णी और श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंच आसान होगी। साथ ही अमृतसर-वाराणसी नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी।

स्विगी इंस्टामार्ट से अब एलपीजी सिलिंडर मंगा सकेंगे ग्राहक

- स्विगी इंस्टामार्ट ने एचपीसीएल के साथ साझेदारी की घोषणा की
- पांच व 10 किलोग्राम के गैस सिलिंडर भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध

नई दिल्ली, प्रेट्र: क्विक कामर्स प्लेटफार्म स्विगी इंस्टामार्ट ने बुधवार को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के साथ साझेदारी की घोषणा की। इसके तहत अब ग्राहक इंस्टामार्ट के माध्यम से एलपीजी सिलिंडर मंगा सकेंगे। इस सेवा की शुरुआत बेंगलुरु से होगी।

इस पहल के साथ एचपीसीएल के नए 'एचपी नव्या' 10 किलोग्राम कंपोजिट एलपीजी सिलिंडर की भी इंस्टामार्ट पर शुरुआत हुई है। पांच किलोग्राम का मेटल एलपीजी सिलिंडर भी उपलब्ध होगा। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों के पास पहले से घरेलू एलपीजी कनेक्शन होना जरूरी नहीं है। यह सुविधा छात्रों, कामकाजी पेशेवरों व छोटे परिवारों सहित उन उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी होगी, जिन्हें एलपीजी सिलेंडर की जरूरत होती है। ग्राहक इंस्टामार्ट एप पर जाकर अपनी पसंद का 10 किलो कंपोजिट या पांच किलो मेटल सिलिंडर चुनकर आर्डर कर सकेंगे। पहली बार किए गए आर्डर में नया सिलिंडर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके बाद ग्राहक खाली सिलिंडर वापस देकर रिफिल आर्डर कर सकेंगे। कंपनी ने बताया कि आर्डर की आपूर्ति एचपीसीएल के अधिकृत वितरक नेटवर्क के माध्यम से की जाएगी और प्रशिक्षित डिलीवरी कर्मी सुरक्षा नियमों के अनुसार सिलिंडर पहुंचाएंगे।

इंस्टामार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमितेश झा ने कहा कि प्लेटफार्म अब केवल किराना सामान तक सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आवश्यक सेवाओं का हिस्सा बन रहा है। एचपीसीएल के साथ साझेदारी के जरिए एलपीजी जैसी जरूरी घरेलू सेवा को भी ग्राहकों तक आसानी और भरोसे के साथ पहुंचाया जाएगा।

पेपाल को 53 अरब डालर में खरीदने को तैयार एडवेंट और स्ट्राइप

न्यूयार्क, रायटर: स्ट्राइप व प्राइवेट इक्विटी फर्म एडवेंट इंटरनेशनल ने पेपाल होल्डिंग को 60.50 डालर प्रति शेयर के भाव पर खरीदने का संयुक्त प्रस्ताव दिया है। यह सौदा 53 अरब डालर में होने की संभावना है। एक सूत्र ने बताया कि इस माह की शुरुआत में दिए गए इस आफर के लिए बैंकों से 50 अरब डालर के वित्तपोषण का भरोसा मिला है। स्ट्राइप और एडवेंट मिलकर पेपाल के संयुक्त स्वामित्व संभालेंगे। दोनों की हिस्सेदारी बराबर होगी।

गत दशक के नौंवे दशक के आखिर में शुरू हुई पेपाल डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में शुरुआती कंपनियों में से एक थी। बाद में पेपाल की बाजार हिस्सेदारी को एपल पे और गूगल पे ने काफी कुछ हासिल कर लिया। कंपनी का बाजार पूंजीकरण 2021 में 360 अरब डालर था। इस साल 36 अरब डालर रह गया। गत 12 माह में इसके बाजार मूल्य में 40% से ज्यादा की गिरावट आई है।

संघ शताब्दी उत्सव में 'मातृत्व' विषय पर भागवत करेंगे कामकाजी महिलाओं से संवाद

नेमिष हेमंत ● जागरण

- दिल्ली में 24 व हैदराबाद में 26 जुलाई को मातृशक्ति के साथ होगा विशेष बौद्धिक सत्र

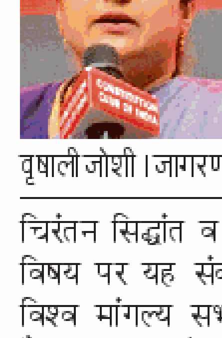

वृषाली जोशी। जागरण

राष्ट्र निर्माण, कार्यक्षेत्र में योगदान के साथ मातृत्व चुनौतियों के समाधान पर तय होगा रोडमैप

नई दिल्ली: बदलते हालत में भारतीय मातृत्व के सामने चुनौतियां नई हैं। हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ने के साथ उन्हें मातृत्व में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो रहा है। भारतीय समाज के इस बदलते स्वरूप पर कामकाजी महिलाओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत संवाद करेंगे। इससे उन्हें और समाज को नई दिशा मिलेगी, बल्कि सरकारों के लिए भी रोडमैप तैयार होगा।

विजयादशमी तक चलने वाले संघ के शताब्दी वर्ष आयोजनों में यह कार्यक्रम दो स्थानों दिल्ली में 24 जुलाई और भाग्य नगर (हैदराबाद) में 26 जुलाई को आयोजित होगा। कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख करीब दो हजार मातृत्व शक्ति से बौद्धिक विमर्श करेंगे।

'युगानुकूल मातृत्व' (मातृत्व के चिरंतन सिद्धांत व युग सापेक्ष परिवर्तन) विषय पर यह संवाद राष्ट्रव्यापी संगठन विश्व मांगल्य सभा द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन मातृशक्ति के सशक्तीकरण, परिवार, सामाजिक जागरण में कार्यरत है। दिल्ली में डा. आंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में संवाद का आयोजन 24 जुलाई को है, जिसमें दिल्ली समेत 17 राज्यों की 800 मातृशक्ति भाग लेंगी। इस दौरान संघ से प्रेरित विश्वमांगल्य सभा के केंद्र व प्रांतों की पदाधिकारियों सहित प्रशासनिक, सेना, चिकित्सा, न्याय, साहित्य, समाज, राजनीति, उद्योग समेत अन्य क्षेत्र की प्रबुद्ध कामकाजी महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। इसी तरह, भाग्य नगर के कार्यक्रम में फिल्म व टीवी जगत की हस्तियों समेत 1300 कामकाजी महिलाएं शामिल होंगी।

विश्व मांगल्य सभा की राष्ट्रीय संगठन मंत्री वृषाली जोशी ने कहा, कामकाजी महिलाओं की चुनौतियों पर पर पूर्व में 22 प्रांतों में मातृ संगम में व्यापक चिंतन व मंथन हुआ था। अब सरसंघचालक के नेतृत्व में इसका निदान कर बदलाव लाने के लिए 10 वर्ष का रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसमें विशेष है कि संघ के पांचों सरसंघचालकों के कार्यकाल में यह पहला अवसर होगा, जब सरसंघचालक मोहन भागवत देश की प्रबुद्ध मातृशक्ति के साथ 'मातृत्व' विमर्श करेंगे।

केस खत्म करने के लिए कोई डील नहीं की: गौतम अदाणी

नई दिल्ली, प्रेट्र: अमेरिका में अदाणी के खिलाफ आपराधिक मामले को खत्म करने के लिए अदालत ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे। अब उन्हीं सवालों के जवाब भारतीय अरबपति गौतम अदाणी ने दिए हैं। अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने इस बात से इनकार किया है कि उनके खिलाफ आपराधिक आरोप खारिज करने के अमेरिकी न्याय विभाग के कदम के पीछे कोई वादा, समझौता या डील थी। उन्होंने एक हलफनामे में कहा, उन्हें इस फैसले से जुड़े किसी भी लेन-देन की जानकारी नहीं थी। अदाणी की ओर से यह हलफनामा न्यूयार्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आठ जुलाई के आदेश के जवाब में दाखिल किया गया था। कोर्ट ने अदाणी से शपथ पत्र देकर यह बताने को कहा था कि क्या उन्हें आरोप खारिज करने से जुड़े किसी वादे, ऑफर या समझौते के बारे में जानकारी थी।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

दानपेटी हवीच कशाला?

'राम-रक्षा!' हा अग्रलेख (लोकसत्ता- १५ जुलै) वाचला. मंदिरांमधील किंवा अन्य धर्मीयांच्या प्रार्थनास्थळांमधील दानात मिळालेल्या रकमेचा, दागिन्यांचा व्यवस्थापनातील लोकांकडून अपहार होणे आपल्याकडे नवे नाही. बद्रीनाथ मंदिर घोटाळादेखील सध्या चर्चेत आहे. प्रभू राम मंदिर घोटाळा हा त्यावरील कळस. यावरून 'देवळात देव नसतो तर देवळात फक्त पुजाऱ्याचे पोट असते,' या संत गाडगे बाबा यांच्या वक्तव्याची तीव्रतेने आठवण येते.

या घोटाळ्यानंतर अयोध्येतील प्रभू राम मंदिराला भेट देणाऱ्या भक्तांची संख्या अर्ध्यावर आल्याच्या आणि ५०० रुपयांच्या जागी १०, २०, ५० रुपयांच्या नोटांचे दानपेटीतील प्रमाण वाढल्याच्या बातम्या येत आहेत. हा प्रभू रामभक्तांमध्ये झालेला बदल सकारात्मक आणि स्वागतार्ह आहे. प्रभू रामचंद्र हे सकल हिंदूंचे परमोच्च श्रद्धास्थान असले तरी मंदिराशी संबंधितांचीच त्यांच्यावर श्रद्धा नाही हे आता कळून चुकल्याने भक्त श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील फरक ओळखू लागले आहेत, असे या प्रकरणातून दिसून येते. मुळात मंदिरे, मशिदी, चर्च इत्यादी धार्मिक ठिकाणी दानपेटी का असावी, यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. या धार्मिक ठिकाणांच्या देखभालीसाठी पैसे आवश्यक असतात हे मान्य; परंतु त्यासाठी आवश्यक तेवढे पैसे देण्याचे आवाहन करून भक्तांकडून ऑनलाइन देणग्या मागवल्या जाऊ शकतात. आवश्यक तेवढी रक्कम जमा झाल्यावर अशा देणग्या थांबवल्या जाऊ शकतात, ज्यायोगे धार्मिक स्थळी प्रचंड संपत्ती गोळा होणे आणि त्यातून अपहार होणे कमी करता येईल.

■ **उत्तम जोगदंड** (कल्याण)

डोलारा उभारणाऱ्यांकडूनच हातोडा

'राम-रक्षा!' हा अग्रलेख (१५ जुलै) वाचला आणि धर्माच्या नावाने सुरू असलेली देशाची दुर्दशा पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. ज्या विश्वासाने, ज्या प्रेरणेने अयोध्येतील राम मंदिर उभारले त्याच विश्वासाला राम मंदिरात झालेल्या देणगी घोटाळ्यामुळे तडा गेला. दोन धर्मांमध्ये फूट पाडून या मंदिराचा डोलारा ज्यांनी मोठ्या दिमाखात उभारला त्यांनीच त्याच्या पायावर हातोड्याचे घाव घालावेत, हे अतिशय शोचनीय आणि निंदनीय आहे. सर्वांत मोठी खंत या गोष्टीची वाटत आहे की यावर कुणी ब्र काढण्यास तयार नाही.

हाच घोटाळा जर आधीच्या सरकारच्या काळात झाला असता तर सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी देशभर रान उठवून त्या सरकारला पायउतार होण्यास भाग पाडले असते. पण सध्या विरोधात कोणी राहिलेच नाही आणि आहेत त्यांना इतका संवेदनशील प्रश्न कसा हाताळावा हेच कळत नाही, ही लोकशाहीची जननी वगैरे म्हणवणाऱ्या देशाची फार मोठी शोकांतिका आहे. एपस्टीन फाइलचा आवाज क्षीण होतो न होतो तोच राम मंदिर घोटाळ्याची घंटा जोरजोरात वाजू लागली आहे. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना हिंदू धर्मातील हे वचन नक्कीच ठाऊक असेल की पापाचा घडा कधी तरी भरतोच! सामान्य भक्तांचा विश्वासघात करणाऱ्या कथित हिंदुत्ववाद्यांना ही सणसणीत चपराक आहे.

■ **प्रा. मार्तंड औघडे,** भाईंदर

वेदना हे भाबडेपणाचेच फळ!

'राम-रक्षा!' हा अग्रलेख वाचला. 'लाखो हिंदूंच्या हृदयास भरून न येणारी, वेदनादायी जखम झाली,' असे वाक्य यात आहे. भाबडेपणाचे फळ वेदना हेच असते. निवडणुकीच्या तोंडावर राम मंदिराचे घाईगडबडीने उद्घाटन करणे, स्वतः श्रीरामाहून महान असल्याचे चित्र निर्माण करणे, उद्घाटन सोहळ्यात सर्व संत-महंतांना पूर्णपणे बाजूला सारून स्वतःवर सर्व लक्ष केंद्रित करून घेणे, वगैरे गोष्टी या श्रद्धाळूंना खटकल्या कशा नाहीत? रामाचे नाव घेऊन कोणीही काहीही खपवत असेल आणि आपण ते गोड मानून घेतले तर तो भाबडेपणा नाही तर काय? असो, पण यानिमित्ताने भाबडेपणा टाळून खरा देवभक्त ओळखण्याच्या निकषासाठी भगवद्गीतेतील 'अद्वेष्टा सर्वभूतानाम्' या तत्त्वाची उजळणी व्हावी असे वाटते. अस्तित्वात असलेल्या कशाचाही आणि कोणाचाही द्वेष न करणारा, तो खरा भक्त. ज्या व्यक्तींच्या मनात द्वेषाला जागा आहे ते कोणत्याही देवाचे खरे भक्त असू शकत नाहीत, असे धर्मच सांगतो.

■ **के. आर. देव,** सातारा

भाविकांनी यातून धडा घ्यावा

'राम-रक्षा!' हे संपादकीय वाचले. अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरीचे प्रकरण कोट्यवधी हिंदूंच्या धार्मिक भावनेवर आघात करणारे आहेच, पण त्या संदर्भातील भाविकांचे मौन अधिक आश्चर्यकारक आहे. मंदिरात घोटाळा आणि त्यात सामील असलेल्यांना देवाचीही भीती वाटली नाही, यातून भाविकांनी बोध घेतला पाहिजे. 'धर्म ही अफूची गोळी आहे', या मार्क्सच्या सुविचाराची साक्ष समाजाच्या मौनातून पटते.

अलीकडे घोटाळे अगदी वरच्या पातळीवर घडताना दिसतात, मात्र ते लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची तसदी घेणे बहुतेक माध्यमे टाळतात, बोटचेपी भूमिका घेतात. ही आणीबाणीसदृश स्थिती आहे. त्यामुळे घोटाळ्यातील आरोपींना पकडण्याऐवजी घटना विस्मृतीत जावी, यासाठी प्रयत्न केले जातात. धार्मिक व्यवहारांतील घोटाळ्यांत इतरांचा हस्तक्षेप नको, ही भूमिका कायद्याच्या राज्याला पूरक नाही. काही साधू, महंतांनी मंदिरात योग्य प्रकारे पूजाविधी होत नसल्याचाही आरोप केला आहे, हे धक्कादायकच! देणग्यांच्या पावत्या दिल्या जात नव्हत्या हाही आरोप झाला आहे. लोक भीतीच्या सावटाखाली असल्याने मोकळेपणाने यावर व्यक्त होत नाहीत. आता तिथे प्रशासकीय अधिकारी नेमण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. तो नेमताना सचोटी, प्रामाणिकपणा आणि व्यवस्थापन कौशल्ये या प्रमुख अटी असणे गरजेचे आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या कामात हस्तक्षेप होणार नाही, याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. देणग्यांची माहिती पारदर्शीपणे द्यावी. त्यामुळे किमान लागलेला कलंक पुसला तरी जाऊ शकेल.

■ **अनिरुद्ध कांबळे,** राजर्षीनगर (नागपूर)

बेजबाबदार अधिकारी निर्दोषच असणार

'महापौरांनाच अहवाल अमान्य' ही बातमी (लोकसत्ता- १५ जुलै) वाचली. अधिकारी कार्यालयात बसून कंत्राटदाराचा 'सर्व काही व्यवस्थित' असल्याचा अहवाल स्वीकारत असतील, तर अशा दुर्घटनेत अधिकाऱ्यांनी झटकलेली जबाबदारी कोणाची? आजवर कधीही अशा दुर्घटनेत कोणत्या अधिकाऱ्यांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्याचे आठवत नाही. त्यामुळे बेजबाबदार अधिकारी हे नेहमी निर्दोषच असणार व अशा घटनेला निसर्गच जबाबदार असणार, हे अहवाल आता नागरिकांच्या अंगवळणी पडले आहेत.

■ **प्रवीण आंबेसकर,** ठाणे

हे तर चोरीवर पांघरूण घालणे!

'केवळ शोक पुरेसा नाही' हे पत्र (१५ जुलै) वाचले. पत्रात वरकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला खडसावण्याचा आव आणला असला, तरी प्रत्यक्षात संघावर पांघरूण घालण्याचेच काम करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसते. 'संबंधित यंत्रणा आणि व्यक्तींवर संघाचे नियंत्रण नव्हते का?' म्हणजे जणू ही सगळी मंडळी अनियंत्रित होती, संघाची पकड घट्ट असती तर गैरव्यवहार झालाच नसता! हे लक्षात घ्यायला हवे की संघाच्या नियंत्रणात, संघाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि संघाच्याच लोकांनी केलेली ही सुनियोजित लूट असल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता उघड झालेली दानचोरी हा हिमनगाचे टोक म्हणावा एवढाच भाग असू शकतो. हे संपूर्ण आंदोलन ज्या हेतूने उभे केले गेले आणि त्यात रामभक्तांच्या धार्मिक अस्मिता जागवून आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर जी लूट झाली, तो संघाच्या धोरणाचाच भाग आहे.

■ **संदेश पेठकर,** चिंचपोकळी (मुंबई)

शिक्षकांना शिकवू द्या!

'एसआयआरच्या ताणामुळे शिक्षिकेचा आत्महत्येचा प्रयत्न' ही बातमी (लोकसत्ता- १५ जुलै) वाचली. शिक्षकांना एसआयआरसारख्या कामांची सक्ती केली जाणे अयोग्य आहे. निवडणूक आयोगाला या कामासाठी स्वतःचे कर्मचारी ठेवता येत नाहीत का? देशात इतके बेरोजगार तरुण आहेत, त्यांना या कामांसाठी नियुक्त करावे. यापूर्वीही बीएलओ म्हणून काम करत असताना आलेल्या मानसिक तणावामुळे पाथर्डी तालुक्यातील प्राथमिक शिक्षिकेचे हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. शाळेची ड्युटी करून एसआयआरचे काम, सततचा अपमान, रात्री उशिरापर्यंत फोनवर कॉल आणि एफआयआरच्या धमकीमुळे शिक्षक तणावाखाली आहेत. हे प्रकार तातडीने बंद करण्यात यावेत.

■ **प्रा. जयवंत पाटील,** भांडुप (मुंबई)

चित्रपटातून द्वेषप्रसार हा नियोजनबद्ध अजेंडा!

चित्रपट इतिहासाचा आणि वर्तमानाचा वापर केवळ द्वेष पसरवण्यासाठी करतो, तेव्हा ती केवळ एक कलाकृती उरत नाही, तर ती एका लोकशाही मूल्याची हत्या ठरते. चित्रपट हे माणसांना परस्परांपासून तोडणारे शस्त्र न होता, ते जोडण्याचे माध्यम होणे, हीच काळाची गरज आहे...

हरीश एस. वानखेडे
'जेएनयू'तील सहयोगी प्राध्यापक
enarish@gmail.com

सिनेकारण

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील १९९० नंतरच्या काळावर नजर टाकल्यास, पडद्यावरील मुस्लीम व्यक्तिरेखांच्या सादरीकरणात एक अस्वस्थ करणारा बदल दिसून येतो. जागतिक स्तरावर ९/११ नंतर निर्माण झालेली दहशतवादाची भीती आणि देशांतर्गत राजकारणात उजव्या विचारसरणीचा झालेला उदय यांमुळे, हिंदी चित्रपटसृष्टी आज एका विशिष्ट साच्यात अडकलेली दिसते. 'द काश्मीर फाइल्स', 'छावा' किंवा 'धुरंदर'सारख्या चित्रपटांतून मुस्लीम व्यक्तिरेखांना निर्दयी, हिंसक किंवा समाजासाठी धोकादायक म्हणून चित्रित करण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे. अशा प्रकारच्या चित्रण शैलीला आज 'हिंदुत्ववादी चित्रपट' असे नाव दिले जात असून, हे केवळ व्यावसायिक यश नसून, एका नियोजित अजेंड्याचा भाग असल्याचे स्पष्ट होते. हे चित्रपट अतिरंजित नाट्य आणि द्वेषाच्या माध्यमातून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचे काम एखाद्या घातक शस्त्रासारखे करत आहेत.

मात्र, हे वास्तव १९९० पूर्वीच्या हिंदी चित्रपटसृष्टीतील मूळ मूल्यांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. एक ऐतिहासिक विसंगती अशी की, पडद्यावर 'सद्गुणी मुस्लीम' ही प्रतिमा कोणत्याही शांततामय काळात निर्माण झाली नव्हती, तर ती १९४०च्या दशकातील अत्यंत अस्थिर राजकीय वातावरणात जन्माला आली होती. तो काळ म्हणजे भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वावटळीचा आणि हिंदू-मुस्लीम यांच्यात निर्माण होत असलेल्या दुफळीचा होता. असे असूनही, त्या काळातील चित्रपटसृष्टीने समाजात द्वेष पेरण्याऐवजी, एकोपा आणि माणुसकीची मूल्ये जपली.

मुस्लिमांच्या आधुनिक आणि धर्मनिरपेक्ष प्रतिमेला चालना देण्यासाठी चित्रपट माध्यमाचा एक नैतिक घटक म्हणून वापर करण्याची ही परंपरा, जातीय ध्रुवीकरण आणि हिंसाचाराने व्यापलेल्या राजकीय वातावरणाला आव्हान देणारी एक प्रभावी सर्जनशील शक्ती होती. हिंदी चित्रपटसृष्टीने बराच काळ हे वैशिष्ट्य जपले आणि राजकीय प्रचाराचे उघड साधन होणे टाळले. मात्र, बदलत्या परिस्थितीत हिंदी चित्रपटसृष्टीचे हे मौल्यवान नैतिक चारित्र्य आता लयास जाऊ लागले असून, ते उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय अजेंड्याचा प्रसार करण्याचे एक महत्त्वाचे साधन ठरू लागले आहे.

फाळणीच्या छायेतील निधर्मी मूल्ये

१९४० चे दशक भारतीय इतिहासात अत्यंत अस्थिर होते. द्वि-राष्ट्र सिद्धांत जोर धरत होता, एका बाजूला मुस्लीम लीगची पाकिस्तानची मागणी होती, तर दुसऱ्या बाजूला हिंदुत्ववादी विचारांकडून 'हिंदू राष्ट्रा'ची हाक दिली जात होती. अशा काळात बॉलीवूडचा धार्मिक विद्वेषाचे माध्यम म्हणून वापर केला जाणे, सहज शक्य होते. अनेक मुस्लीम कलाकारांवर तर स्वतःची ओळख लपवण्याचा दबावही होता. परंतु, बॉम्बे सिनेमातील कलाकारांनी अशा जातीयवादी दबावाला बळी न पडता आपली सर्जनशीलता आणि बौद्धिक स्वायत्तता जपली.

गांधी आणि नेहरू यांच्या धर्मनिरपेक्ष-राष्ट्रवादी विचारांनी प्रेरित होऊन, चित्रपट निर्मात्यांनी सिनेमा हे शांतता आणि समन्वयाचे साधन म्हणून वापरले. त्यांनी मुस्लीम सम्राटांना किंवा व्यक्तिरेखांना केवळ आक्रमक किंवा धार्मिक कट्टरपंथी न दाखवता, त्यांना संस्कृतीचे रक्षणकर्ते आणि सहिष्णू शासक म्हणून सादर केले. हे चित्रपट केवळ ऐतिहासिक काळाचे चित्रण नव्हते, तर तो एका मोठ्या सांस्कृतिक संघर्षाचा भाग होता, ज्याद्वारे समाजमानसात तुटलेली माणुसकी जोडण्याचे काम केले जात होते.

सांस्कृतिक समन्वयाचा पाया

'पुकार' (१९३९), 'शहंशाह अकबर' (१९४३), 'शहंशाह बाबर' (१९४४), 'मुमताज महल' (१९४४), 'हुमायून' (१९४५) आणि 'शाहजहान' (१९४६) यांसारख्या चित्रपटांनी मध्ययुगीन भारताला एक 'समन्वयी कालखंड' म्हणून दाखवले. मेहबूब खान यांच्या 'हुमायून' चित्रपटात सम्राट आणि त्यांचे राजपूत सरदार यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंध ज्या प्रकारे दाखवले आहेत, ते आजच्या इतिहासाच्या विकृत मांडणीला चपराक देणारे आहे. वजात मिर्झा यांच्या 'शहंशाह बाबर'मध्ये बाबरला एक 'विद्वान आक्रमक' नाही, तर या भूमीवर प्रेम करणारा आणि तिला समृद्ध करू पाहणारा राजा म्हणून दाखवले आहे.

या चित्रपटांची भाषाही हिंदुस्तानी होती, ज्यात हिंदी आणि उर्दूचा सुंदर संगम होता. गांधीजींना अभिप्रेत असलेली ही हिंदुस्तानी भाषा एका वैविध्यपूर्ण समाजाला एकत्र बांधण्याचे काम करत होती. मुन्शी शाम यांची पटकथा आणि खेमचंद प्रकाश यांचे संगीत असणे, हे त्या काळातील हिंदू-मुस्लीम एकतेच्या व्यावसायिक भागीदारीचे प्रतीक होते. हे चित्रपट जाणीवपूर्वक अशा प्रकारे तयार केले जात होते की, ज्यामुळे इतिहासातील चुकीचे समज दूर व्हावेत आणि दोन्ही समुदायांत प्रेमाचे, विश्वासाचे नाते घट्ट व्हावे.

७०-८०च्या दशकातील वैविध्य

१९४० च्या दशकाचा वारसा पुढे १९७० आणि ८० च्या दशकातही कायम राहिला. या काळात मुस्लीम व्यक्तिरेखांना केवळ एकआयामी रूपात न मांडता, त्यांना मानवी छटा देण्यात आल्या. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे 'कुली' (१९८३) चित्रपटातील इक्बाल खानची व्यक्तिरेखा. हा केवळ एक मुस्लीम तरुण नव्हता, तर तो कामगार वर्गाचा आवाज होता, जो अन्यायाविरुद्ध लढत होता.

तसेच, 'सलीम लंगडे पे मत रो' (१९८९) हा चित्रपट मुस्लीम समाजातील अंतर्गत संघर्षावर आणि त्यांच्या आर्थिक-सामाजिक वास्तवावर भाष्य करणारा एक मास्टरपीस होता. त्यात सलीम ही व्यक्तिरेखा कोणत्याही उपकाराच्या लाटेवर स्वार नसून, ती संघर्षातून आपली ओळख शोधणारी आहे. त्याचबरोबर 'कुर्बानी' (१९८०) सारख्या चित्रपटांत अमजद खान यांनी साकारलेल्या पोलीस इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेने मुस्लीम पात्राला आधुनिकतेची स्टायलिश चौकट दिली. या चित्रपटांतून मुस्लीम पात्रे ही केवळ धर्माच्या प्रतीकांपुरती मर्यादित न राहता, ती या देशाच्या मुख्य प्रवाहातील एक जिवंत आणि धडपडणारा घटक म्हणून समोर आली.

वारसा पुसण्याची प्रक्रिया

हिंदी चित्रपटसृष्टीने एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला तो २००० च्या दशकात. या काळात एका बाजूला जागतिक पातळीवरील दहशतवादाची चर्चा आणि दुसरीकडे देशांतर्गत राजकारणात उजव्या विचारसरणीचा वाढता प्रभाव यामुळे पडद्यावरील मुस्लीम व्यक्तिरेखांच्या मांडणीत मोठा बदल घडून आला. २००० नंतरच्या काळात खलनायक हा मुस्लीम धार्मिक ओळख असलेला गुंड म्हणून अधिक ठळकपणे मांडला जाऊ लागला. 'वॉर', 'उरी', 'बॉर्डर २' आणि 'गदर २' सारखे चित्रपट मुस्लीम आणि पाकिस्तानी यांना एकच मानून, त्यांना भारताचा कायमचा शत्रू म्हणून चित्रित करत आहेत. मुस्लीम व्यक्तिरेखांना केवळ दहशतवादी किंवा हिंसक गुन्हेगार दाखवून, एक अशी राष्ट्रवादी ओळख तयार केली जात आहे, जी दुसऱ्याच्या तिरस्कारावर आधारित आहे.

हे चित्रपट केवळ मनोरंजनाचे साधन नाहीत, तर ते राजकीय ध्रुवीकरणाचे घातक शस्त्र झाले आहेत. एकदा का सिनेमाच्या आरशातून समन्वयाचे स्वप्न पुसले गेले की, तो आरसा केवळ द्वेषाचे प्रतिबिंब दाखवतो. आजचा चित्रपट सहअस्तित्वाकडून विजयाकडे प्रवास करत आहे.

आशेचा किरण

जरी आज द्वेषाचे राजकारण चित्रपटसृष्टीवर वरचढ ठरत असले, तरी काही चित्रपट निर्माते अद्याप त्या निधर्मी वारशाचा दिवा तेवता ठेवत आहेत. 'माय नेम इज खान' (२०१०) हा चित्रपट मुस्लीम व्यक्तीच्या अस्मितेचा आणि त्याच्या देशप्रेमाचा संघर्ष अत्यंत संवेदनशीलतेने मांडतो. 'गली बॉय'मधील 'मुराद'ची भूमिका एका सामान्य मुस्लीम तरुणाची स्वप्ने आणि त्याच्या संघर्षाचे प्रतिनिधित्व करते, जी कोणत्याही धार्मिक कट्टरतेपासून मुक्त आहे. इम्तियाज अली यांचा अलीकडचा 'मैं वापस आऊंगा' सारखा प्रयोगही याच परंपरेचा एक भाग आहेत, जिथे कथांच्या केंद्रस्थानी माणुसकी आणि भावनांना महत्त्व दिले जाते. ही उदाहरणे हे सिद्ध करतात की, आजही चित्रपटसृष्टीत एक असा गट आहे जो मुस्लीम व्यक्तिरेखांना केवळ 'व्हिलन' म्हणून पाहण्याऐवजी, त्यांना मानवी दृष्टिकोनातून पाहतो. परंतु, ही संख्या मुख्य प्रवाहातील हिंदुत्ववादी सिनेमाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.

हिंदी चित्रपटांनी आपला निधर्मी आत्मा पुन्हा मिळवण्यासाठी त्या १९४० च्या दशकातील ध्येयधोरणांकडे आणि १९७०-८० च्या दशकातील वैविध्याकडे पुन्हा वळण्याची गरज आहे. जेव्हा सिनेमा इतिहासाचा आणि वर्तमानाचा वापर केवळ द्वेष पसरवण्यासाठी करतो, तेव्हा ती केवळ एक कलाकृती उरत नाही, तर ती एका लोकशाही मूल्याची हत्या ठरते. हा भग्न आरसा आपल्याला हेच सांगतोय की, जर आपण आजच्या या विषारी सादरीकरणाला प्रश्न विचारले नाहीत आणि 'माय नेम इज खान' किंवा 'गली बॉय'सारख्या संवेदनशील कथानकांना प्रोत्साहन दिले नाही, तर आपण पुढच्या पिढ्यांना केवळ द्वेषाचा वारसा देऊन जाऊ. सिनेमा हे माणसांना परस्परांपासून तोडण्याचे शस्त्र न होता, ते जोडण्याचे माध्यम होणे, हीच काळाची गरज आहे.

कुतूहल

हेलिकॉप्टर उंच का जात नाही?

विमानाला उड्डाणासाठी लांब धावपट्टीची गरज असते. त्यामुळे जिथे लांब धावपट्टीसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसते अशा ठिकाणाहून उड्डाण करण्याकरता हेलिकॉप्टर तयार केलं गेलं. उडण्यात पहिली अडचण येते ती गुरुत्वाकर्षण बलाची. या बलाच्या विरुद्ध दिशेने पुरेसं बल लावता आलं तरच वस्तू उडू शकते. हे बल निर्माण करण्यासाठी हेलिकॉप्टरच्या उड्डाणात भौतिकशास्त्रातील दोन मूलभूत सिद्धांतांचा वापर केला जातो.

पहिला सिद्धांत म्हणजे न्यूटनचा गतीविषयक तिसरा नियम. हेलिकॉप्टरवर लांब व विशिष्ट आकाराची पाती असलेला पंखा असतो. तसंच मागच्या दिशेला आणखीन एक पंखा असतो. हेलिकॉप्टरचं इंजिन सुरू झाल्यावर वरचा पंखा वेगाने फिरू लागतो. गोल फिरताना हा पंखा हवा खालच्या दिशेला दाबतो. न्यूटनच्या तिसऱ्या नियमाप्रमाणे हीच हवा मग विरुद्ध दिशेने म्हणजे वरच्या दिशेने बल लावते आणि हेलिकॉप्टरला वर उड्डाण करणं शक्य होतं. या पंख्याची पाती विशिष्ट आकाराची असतात. या आकारास भौतिकशास्त्रात 'एरोफॉईल' असं म्हणतात. हा आकार वरती फुगीर व खालच्या बाजूस सपाट असतो. त्यामुळे हवेचा प्रवाह विभागला जातो. पात्यांच्या वरती हवेचा वेग जास्त असतो. बर्नोलीच्या सिद्धांताप्रमाणे हवेचा वेग वाढला की दाब कमी होतो. याउलट पात्यांच्या खाली हवेचा वेग कमी, परिणामतः दाब अधिक असतो. हवेच्या प्रवाहाची दिशा कायम जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे असते. म्हणून बल खालून वरच्या दिशेला हेलिकॉप्टरवर काम करतं. या दुहेरी कारणांमुळे ते हवेत उडू शकतं.

जास्त उंचावर म्हणजे साधारण दहा हजार फुटांवर गेल्यावर हवा विरळ होते. ही विरळ हवा कितीही खालच्या दिशेला दाबली गेली तरी वरच्या दिशेने पुरेसं बल निर्माण होत नाही. म्हणून सर्वसाधारणपणे हेलिकॉप्टर जास्तीत जास्त चार किलोमीटर उंची गाठू शकतं.

याशिवाय हेलिकॉप्टर अधिक उंच न जाण्यामागे हवेचा दाब आणि हवेतील ऑक्सिजन ही कारणंही आहेत. हवा उंच गेल्यावर जशी विरळ होते तसाच तिचा दाब कमी होतो आणि हवेतील ऑक्सिजनचं प्रमाणसुद्धा कमी होतं. मोठ्या विमानांमध्ये केबिन प्रेशर (दाब) व आतील हवेतील ऑक्सिजनचं प्रमाण हे संतुलित ठेवलं जातं. अशी सोय हेलिकॉप्टरमध्ये नसते. या कारणामुळे हेलिकॉप्टर जास्त उंच जाऊ शकत नाही.

हेलिकॉप्टरच्या मागच्या बाजूला जो पंखा असतो त्याला 'टेल रोटर' म्हणतात. हेलिकॉप्टरवरील पंखा फिरल्याने हेलिकॉप्टर त्याच्या उलट्या दिशेने फिरू नये म्हणून हा टेल रोटर असतो. हा पंखा हेलिकॉप्टरचं संतुलन राखतो तसंच दिशा बदलण्यासाठीदेखील याचा उपयोग होतो.

– सुधा सोमणी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

चोरी तर होणारच!

प्रवाशांकडून बेडरोल *चोरीच्या संदर्भात प्रकाशित झालेल्या बातम्यांना बरोबर एक वर्ष पूर्ण झाल्यावर रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव मंत्रालयात आढावा बैठकीला उपस्थित झाले तेव्हा आता नक्कीच काही तरी चांगले ऐकायला मिळणार ही आशा त्यांच्या मनात होती. 'करा सुरू' असे म्हणताच बोर्डाचा एक अधिकारी उभा राहिला. 'सर, चोरी रोखण्यासाठी तीन उपाययोजना अमलात आणल्या. त्यातली पहिली होती बेडरोलमधील प्रत्येक वस्तू साखळीने बांधणे. देशात रोज रात्री आठ लाख प्रवासी वातानुकूलित कक्षातून प्रवास करतात. त्यातल्या तीन लाखांसाठी आपण डब्यांमध्ये ५० कोटी खर्चून ही व्यवस्था उभारली. शौचालयातला लोटा साखळीने बांधणे सुरू केल्यापासून त्याची चोरी कमी झाल्याने हा उपाय योजला. साखळीने बांधलेली उशी, चादर हिसका देऊन तोडण्याचा प्रयत्न कुणी केलाच तर सायरन वाजेल असे याचे स्वरूप होते. वर्षभरात रोज सरासरी ३० हजार सायरन वेगवेगळ्या ठिकाणी वाजले. मात्र पोलीस पोहोचायच्या आत प्रवासी पसार झाले. त्यांची नावे हुडकून गुन्हे दाखल केले. त्यांचा शोध घेऊन तपास करायचा तर रेल्वे पोलीस दलात दहा हजार जवानांची तातडीने भरती करणे गरजेचे. त्याकरिता पद व निधी मंजुरीला त्वरित मान्यता द्यावी.' हे ऐकून वैष्णव यांचा चेहराच पडला.*

मग दुसरे अधिकारी उभे राहिले. 'उरलेल्या पाचपैकी तीन लाख प्रवाशांसाठी आपण बेडरोल देताना व परत घेताना स्वाक्षरी घ्यायची असे ठरवले. त्यासाठी बेडरोल पुरवठादाराकडून नियुक्त कोच साहाय्यकांना प्रशिक्षण दिले. त्यावर १२ कोटी खर्च झाले. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू झाली तेव्हा दररोज ५० हजार प्रवाशांनीच स्वाक्षरी देत बेडरोल परत केले. स्वाक्षरीच्या मुद्द्यावरून कोच साहाय्यकांना मारहाण करण्याच्या रोज सरासरी तीनशे घटना ठिकठिकाणी घडल्या. स्वाक्षरी न करता बेडरोल घेऊन रोज साधारण २० हजार प्रवासी पसार झाले. या सर्वांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. मनुष्यबळ अपुरे असल्याने यातील केवळ एक टक्केच आरोपी शोधता आले. उर्वरितांचा शोध सुरू असून ते केव्हा सापडतील हे नक्की सांगू शकत नाही. मारहाणीच्या घटनांमुळे कोच साहाय्यक या डब्यांमध्ये कर्तव्य बजावण्यास इच्छुक नाहीत, असे पुरवठादारांचे म्हणणे असून त्यांनी साहाय्यकांना जादा वेतन देण्यासाठी कंत्राटाची रक्कम वाढवून देण्याची मागणी केली आहे.' हे ऐकून वैष्णव यांचा चेहरा आणखी पडला.

ते तिसऱ्याकडे वळले. 'वातानुकूलित श्रेणीचे तिकीट कमी करून उर्वरित दोन लाख प्रवाशांकडून अनामत रक्कम घेत बेडरोल द्यायचे व उतरताना ते परत घेऊन रक्कम परत करायची असा उपाय प्रायोगिक तत्त्वावर काही मार्गांवर योजला. रोज सरासरी ४५ हजार प्रवाशांनी रक्कम देण्यास नकार दिला. उर्वरित प्रवाशांनी पैसे मोजले. मात्र वर्षभरात दहा हजार फेऱ्यांमधील साहाय्यकांनी त्याचा हिशेबच पुरवठादारांना दिला नाही. पाचशे साहाय्यक पैसे घेऊन पसार झाले. या सर्वांच्या विरुद्ध गुन्हे दाखल केले. अनामत देणाऱ्या ५० टक्के प्रवाशांनी रक्कम परत न घेताच बेडरोल सोबत नेले.' हे ऐकून वैष्णव हताश झाले. एवढ्यात चौथा म्हणाला. 'बहुतांश भारतीयांमध्ये चोरी करण्याची वृत्ती उपजतच! मग ते मंदिर, हॉटेल असो वा आपली रेल्वे. त्यामुळे जेवढे बेडरोल चोरले जातील तेवढे जाऊ द्यावे. इतका खर्च करून लोकांना सुधारण्याचे काम आपले नाही.' हे ऐकताच सर्व उपाययोजना थांबवा असे आदेश देत वैष्णव निघून गेले.

राजवाडे विचारविश्व

शहाजीकालीन पोथीची शिवकालीन नकल

आपल्या हाती लागलेल्या पोथीचा मूळ लेखक मनोहर पुराणिक नसला, तरीही 'तो एक साक्षेपी गृहस्थ होता म्हणूनच त्याने त्याला मिळालेल्या जीर्ण पोथीची डागडुजी करून व तिच्यावर आपली दखल घालून ती आपल्या संग्रहात ठेवून दिली. कालांतराने पोथी पुराणिकाच्या घरून रबड्यांच्या घरात जाऊन सध्या ती प्रस्तुत संपादकाच्या आश्रयास प्रकाशनार्थ आली आहे. मनोहर पुराणिकाच्या दखलेतील (नोंदीतील) अक्षरांचे वळण त्याने स्वतः लिहिलेल्या इतर ग्रंथांमधील अक्षरांच्या वळणांशी जुळते', अशी माहिती देऊन राजवाड्यांनी नंतर त्या पोथीच्या रक्षणकर्त्याबद्दल आणखीही खुलासा केला.

'मनोहर लक्ष्मण पुराणिक हा गृहस्थ मूळचा भीमेकाठच्या खेड गावचा राहणारा. खेडहून चिंचवडास त्याने स्थलांतर केले, ते पहिले बाजीराव बल्लाळ याच्या कारकीर्दीच्या सुमारास. हा यजुर्वेदी माध्यंदिन ब्राह्मण बराच व्यासंगी असून याला प्राकृत व संस्कृत कविता करण्याचा नाद होता. रबड्यांच्या घरात जो ग्रंथसमूह मला सापडला, त्यापैकी बहुतेक सर्व पोथ्या या मनोहर पुराणिकाच्याच आहेत. या ग्रंथसमूहात वेद, इतिहास, पुराण, व्याकरण, न्याय, वेदान्त, काव्य, नीति इत्यादिविषयक संस्कृत ग्रंथ असून ज्ञानेश्वर, एकनाथ, मुक्तेश्वर, वामन, कृष्णयाज्ञवल्क्य वगैरेंचे प्राकृत ग्रंथही आहेत. शिवाय याने स्वतः रचिलेली काही प्राकृत अभंग, श्लोक वगैरे मराठी ग्रंथरचनाही आहे. हा आपल्याला मनकवि, मनोहरकवि असे अभंगांच्या किंवा श्लोकप्रबंधांच्या समाप्तीच्या प्रसंगी वारंवार म्हणतो. कित्येक स्थली याने आपले गाव, नाव, मातापितरे, गुरू, शक, महिनामिती इत्यादी त्रोटक तपशीलहि दिला आहे, त्यावरून असे दिसते की, हा कवि बाजीराव बल्लाळ व बाळाजी बाजीराव या दोन पेशव्यांच्या कारकीर्दीत चिंचावटग्रामी (चिंचवडला) वास्तव्य करून होता...'

पोथीच्या रक्षणकर्त्याचा अंदाजे काळ कोणता असावा, हे सूचित केल्यानंतर राजवाड्यांनी पुन्हा एकदा पोथीच्या वर्णनाकडे लक्ष वळवले. त्यांनी पोथीच्या काळाबद्दलचा अंदाज व्यक्त करीत लिहिले, 'राधामाधवविलासचंपूची माझ्या हाती लागलेली पोथी शक १६५० पूर्वीची आहे. किती पूर्वीची आहे, या बाबीचा अंदाज पोथीच्या जीर्णत्वावरून व अक्षराच्या वळणावरून अदमासाने ताडता येतो. इ, क, ज, य, भ वगैरे अक्षरांची मोडणी शिवकालीन दिसते. सबब, ही पोथी बहुधा शक १६००च्या सुमारची असावी. मूळ पोथीतील अक्षरे न लागल्यामुळे कोठे कोठे जागा रिकामी सोडिली आहे व कोठेकोठे श्लोकांचे सबंध चरणच्या चरण खाल्ले आहेत किंवा अर्थ न लागल्यामुळे अंदाजाने काहीतरी अक्षरे एकापुढे एक लिहून वेळ मारून नेली आहे, त्यावरूनही ही शिवकालीन पोथी (मूळची नसून) तिच्याहून जुन्या अशा पोथीवरून नकललेली आहे.'

साहजिकच प्रश्न उपस्थित झाला, तो मूळ पोथीबद्दलचा. त्याचे उत्तर मिळवण्यासाठी त्या पोथीतल्या मजकुराचाच धांडोळा घेणे भाग होते. राजवाड्यांनी ते काम चिकाटीने पार पाडले आणि खुलासा करीत लिहिले, 'सगळ्यांत अत्यंत जुनाट पहिली पोथी शहाजीराजे भोसले यांची पहिली राजधानी जे बंगळूर शहर तेथे लिहिली गेली व तिच्यावरून किंवा तिच्या प्रतीच्या प्रतीवरून ही सध्याची पोथी शिवकाळात नकलली गेली असावी. अर्थात या चंपूच्या आणखीही काही प्रती म्हैसूर, मद्रास व तंजावर या प्रांतांत असण्याचा संभव आहे. त्या धुंडाळून मिळवणे ही बहुत कालान्तराची वाव होणार म्हणून या एकाच पोथीवरून इतिहासज्ञान मिळवण्यासाठी प्रस्तुत प्रकाशन आरंभिले आहे.'

राजवाड्यांनी त्यानंतर मूळ पोथीबद्दलची माहिती द्यायला सुरुवात केली. त्यांनी लिहिले, 'हा राधामाधवविलासचंपू ग्रंथ प्रथम बंगळूर प्रांती उदयास आला. स्वतः ग्रंथकारच म्हणतो की, शहाजी महाराजांनी हे काव्य श्रवण केले. कोठे श्रवण केले? तर बंगळूर प्रांती श्रवण केले. तैलंगणादि इतर प्रांतांत कशावरून श्रवण केले नाही? तर कवि स्वतः दोनतीन ठिकाणी महाराष्ट्रदेशाहून शहाजीमहाराजांसन्निध आल्याचा उल्लेख करतो. महाराष्ट्रदेशाहून शहाजीमहाराजांसन्निध येणे म्हणजे बंगळूरप्रांती येणेच होय, कारण कर्नाटकात बंगळूरखेरीज इतरत्र त्यांचे वास्तव्य शेवटची पंधरा वर्षे नव्हते.'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

‘बेस्ट’ ते सरले...

शहरे चालवणाऱ्यांच्या मनात त्या शहराविषयी काही भावना हव्यात आणि जबाबदारीची जाणीव हवी. तिचा पूर्ण अभाव आपल्या सर्वच शहरांत सर्रास दिसून येतो...

नवीन उत्तम काही उभारता येत नाही आणि जुने उत्तम राखता येत नाही या आधुनिक भारताच्या वास्तवाचे मूर्तिमंत स्वरूप म्हणजे मुंबईची ‘बेस्ट’ सेवा. ‘बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अॅण्ड ट्रान्सपोर्ट’ ऊर्फ ‘बेस्ट’ ही केवळ मुंबई वा महाराष्ट्रातच नव्हे, तर संपूर्ण देशातच गौरवली गेलेली पहिली आणि बराच काळ एकमेव राहिलेली शहर सार्वजनिक वाहतूक सेवा. तिच्या स्थापनेची शताब्दी बुधवारी- १५ जुलैस साजरी झाली. या शतकभराच्या काळात ‘बेस्ट’चा आलेख चढताच राहिला. त्याचे श्रेय अशी शहर सेवा सुरू करणाऱ्या साहेबाच्या व्यापक नियोजकतेस जसे जाते तसेच त्या श्रेयाचा मोठा वाटा नियोजनाचा आदर करणाऱ्या नागरिकांच्या मानसिकतेकडेही जातो. वास्तविक महानगराच्या वाहतूक व्यवस्थेसाठी शंभर वर्षे म्हणजे एक स्वल्पविराम. या शंभर वर्षात जुन्यातील जे जे चांगले त्याची भर मुदलात घालून त्या चांगुलपणाच्या व्याजावर पुढच्या मार्गाची उभारणी करणे अपेक्षित असते. विकसित आणि कायमस्वरूपी विकसनशील यांच्यातील हाच तो फरक. तो लंडन ते वॉशिंग्टन अशा अनेक ठिकाणी पदोपदी अनुभवास येतो. लंडनमधील भुयारी मेट्रो सुरू झाल्यानंतर अवघ्या दहा वर्षांत साहेबाने मुंबईत ट्राम सुरू केली आणि तिच्यासाठी वाडीबंदर येथे स्वतंत्रपणे वीजनिर्मिती केंद्रही उभारले. ही १८७३ सालची घटना. त्याआधी दहा वर्षे, म्हणजे १८६३ साली, सुरू झालेली लंडन मेट्रो आज ज्या रीतीने गौरवली जाते त्याचा काही अंश तरी शताब्दी साजरी करणाऱ्या ‘बेस्ट’मध्ये आढळतो काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्या नागर जीवनाची लक्तरे आहेत.

सुरुवातीच्या घोड्याकडून ओढल्या जाणाऱ्या ट्राम कंपनीचे रूपांतर १९२६ साली यांत्रिक बस सेवेत झाले आणि आपला ‘बेस्ट’ लौकिक ही सेवा दिवसागणिक वाढवत गेली. वास्तविक मुंबई आणि अर्थातच भारतावर राज्य होते इंग्रजांचे. पण कापूस आदी घटकांच्या व्यापारात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचलेल्या बॉम्बेत अशी सेवा सुरू करण्याची मूळ कल्पना अमेरिकी कंपनीची. त्या वेळचा इतिहास असा की अंतर्गत यादवीमुळे अमेरिकी अर्थव्यवस्था डबघाईस आली होती आणि बॉम्बे शहराकडे अमेरिकी व्यापारी हे मंदीकाळातील संधी म्हणून पाहात होते. अमेरिकी कंपनीस मुंबईत वाहतूक सेवा सुरू करावी असे वाटले ते त्यातूनच. या सेवेसाठी सदर कंपनीने ९०० घोड्यांची स्वतंत्र पागा राखली होती. या सेवेचे रूपांतर आधी ट्राममध्ये आणि नंतर यांत्रिक बस सेवेत झाले. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस या सेवेस मुंबईत वीजपुरवठ्याचा आणि त्याच वेळी सार्वजनिक वाहतूक सेवा चालवण्याचा सर्वाधिकार दिला गेला. ही सेवा आधी ट्रामच्या माध्यमातून चालवली गेली आणि १९२६ पासून तीत बस गाड्यांचा अंतर्भाव केला गेला. अशा बस सेवेचा शुभारंभ झाला १५ जुलै १९२६ या दिवशी. त्या वेळी ‘बेस्ट’च्या मालकीच्या २४ बस गाड्या होत्या. त्यात उत्तरोत्तर वाढच झाली. इतकी की साठच्या दशकात ‘बेस्ट’च्या स्वतःच्या मालकीच्या बस गाड्यांची संख्या हजाराहून पुढे गेली. तथापि आपल्या सेवेचा शतक महोत्सव साजरा करत असताना आजमितीस ‘बेस्ट’च्या ताब्यातील बस गाड्यांची संख्या किती? ती आहे फक्त २४९. यावरून मुंबईच्या नगरपित्यांच्या मानसिकतेतील बदल दिसून येतो आणि शतकोत्तर वाटचालीच्या उंबरठ्यावर नव्या झळाळीऐवजी ही सेवा अधिकाधिक काळवंडू लागल्याचे का दिसते याचाही अंदाज येतो.

या काळात ‘बेस्ट’ सेवा वाढल्या नाहीत असे नाही. त्यात वाढ झालीच. पण या वाढीसाठी ‘बेस्ट’ने स्वमालकीचे हात झटकले आणि सत्ताधाऱ्यांस खिसे भरण्याची संधी देणाऱ्या कंत्राटीकरणाचा मार्ग स्वीकारला. आज स्वतःच्या मालकीच्या फक्त २४९ बस गाड्या सांभाळणाऱ्या

> ...एके काळी सर्वोत्कृष्ट मानली जाणारी मुंबईची बस वाहतूक सेवा आज कंत्राटीकरण आणि कंगालीकरणाच्या गर्तेत गेली आहे; तिच्याविषयी कुणालाच ममत्व नाही...

‘बेस्ट’च्या सेवेत त्याखेरीज २,५५१ इतक्या बस गाड्या आहेत. सर्व कंत्राटी. अन्य कोणाच्या मालकीच्या या बस गाड्या त्यांच्या सर्वांगास लाल रंग फासून ‘बेस्ट’ म्हणून चालवल्या जातात. या बस गाड्यांचे चालकही असेच. कंत्राटी. बस गाड्याही मालकीच्या नाहीत आणि ते चालवणारे चालकही सेवेत नाहीत. त्याच वेळी प्रवाशांसही सेवेविषयी ममत्व नाही. या नवप्रवाशांची पैसे फेकू वृत्ती ते ज्या रीतीने बस स्टँडवर उभे राहतात आणि झडप घातल्यासारखे बसमध्ये कसे चढतात यातून स्पष्ट दिसून येते. प्रवासी हे असे. आणि कंत्राटी बसचालकास बस स्टँडपर्यंतही आणण्याचे सौजन्य नाही. अलीकडे बस गाड्या त्यांच्यासाठी अधोरेखित जागेत उभ्या न राहता भर रस्त्यात ठाण मांडून उभ्या राहतात त्या या शहराच्या बदललेल्या संस्कृतीमुळे. अगदी अलीकडेपर्यंत ‘बस’ गाड्यांचा अपघात ही गोष्ट क्वचित कधी कानावर येत असे. आता परिस्थिती अशी की ‘बेस्ट’चा अपघात हा इतका दैनंदिन झालेला आहे की त्याचे काही कोणास वाटते असे मानणे हा भाबडेपणा ठरेल. गेल्या काही महिन्यांत किमान अर्धा डझन नागरिकांचे जीव ‘बेस्ट’ अपघातात गेले. या नव्या ‘बेस्ट’ने जे जे बेस्ट त्या सगळ्याचा त्याग केलेला आहे हे या आस्थापनाच्या कारभारावरूनच समजून यावे. नागरिकांत कोणत्याच सेवेविषयी आपलेपणाची भावना नाही आणि ती देणाऱ्या कोणाच्याही मनात नागरिकांविषयी ममत्व नाही, असा हा समसमा संयोग.

त्यातून आपल्या नागर जीवनाचे स्खलन तेवढे दिसते. शहरे केवळ चकचकीत इमारती आणि रस्ते-पूल नव्हेत. त्यास शहरे चालवणाऱ्यांच्या जबाबदार वर्तनाची साथ हवी. तर शहर चांगले की भिकार हे ठरते. शहरे चालवणाऱ्यांच्या मनात त्या शहराविषयी काही भावना हव्यात आणि जबाबदारीची जाणीव हवी. तिचा पूर्ण अभाव आपल्या सर्वच शहरांत सर्रास दिसून येतो. एखाद्याचे पोट फुटेल की काय असे वाटेल इतके फुगावे तशी आपली शहरे फुगलेली आहेत. ना आकार ना उकार. बकालपणा सार्वत्रिक. ‘स्वच्छ भारत’ वगैरे कितीही घोषणांचा कंठशोष करा वा त्यांच्या यशाचे गोडवे गा. ते किती फोल आहेत याचे वास्तव आपल्या कोणत्याही शहरात वा गावात वा कोठेही दिसेल. शहरी जीवनाची म्हणून एक शिस्त असावी लागते. ती राखण्यासाठी कसलेच प्रयत्न झाले नसतील आणि उठवळ लोकांहाती आपले प्रशासन गेले असेल, बाकी सर्वत्र कंगालीकरण मोठ्या जोमाने होत असेल तर ‘बेस्ट’ सेवा बेस्ट कशी राहणार?

दुःख हे की शहरांच्या हाती पैसा अधिक खेळू लागलेला असताना, आपली एकूणच सामाजिक सांपत्तिक स्थिती सुधारत असताना देशातील एकाही शहरात आपण ‘बेस्ट’ लौकिकाच्या जवळपास जाईल अशी सेवा सुरू करू शकलो नाही. दिल्लीतील बस सेवेविषयी न बोलणे बरे आणि मुंबईलगतच्या पुणे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सेवा आणि गुणवत्ता यांचा संबंध जन्मात कधी आलेला नाही. कोलकाता, चेन्नई, बेंगळूरु आदी शहरांतील सार्वजनिक वाहतूक म्हणजे मूर्तिमंत कल्लोळ. सुमारे दशकभरापूर्वी आपली शहरे ‘स्मार्ट’ होणार अशी आवई उठली होती. पण नव्या वसवल्या जाणाऱ्या शहरांचा ‘स्मार्टनेस’ सोडा; आपली होती ती शहरे जगण्याचा होता नव्हता तोही दर्जा झपाट्याने घालवून बसली. शिवाय देशातील एकही ‘मेट्रो’ सेवा नफ्यात नाही. त्यातल्या त्यात गुंतवणुकीवर बरी कमाई आहे ती दिल्ली मेट्रोची. तरी प्रवाशांच्या तिकिटांतून दिल्ली मेट्रोला होणारी कमाई ४८ टक्केच. बाकीच्या शहरांतील मेट्रो म्हणजे शुभ्र पांढरे हत्ती. ‘बेस्ट’ची शताब्दी काय काय बेस्ट आपण मागे सोडले याची वेदना जागृत करते. तीवर फुंकर घालेल असे एखादेही शहर डोळ्यासमोर नाही.

निवडणुकीची दिनदर्शिका बदलेल, पण लोकशाही सुधारेल?

लेख

विजय केळकर, अजित रानडे

लेखकद्वय अनुक्रमे पुणे इंटरनॅशनल सेंटरचे उपाध्यक्ष तसेच सीनियर फेलो आहेत.

> केंद्र सरकारला एक देश एक निवडणूक ही पद्धत आणायची आहे. पण ती भारतीय राजकीय व्यवस्थेला जो आजार झाला आहे, तो बरा करणार का?

‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना वरवर पाहता फार आकर्षक वाटते. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका थांबतील, खर्च वाचेल, सरकारी यंत्रणेवरील ताण कमी होईल आणि सरकारांना पाच वर्षे सलग विकासकामे करता येतील– असा तिचा साधासरळ युक्तिवाद आहे. त्यामुळे या कल्पनेला विरोध करणे म्हणजे जणू काटकसर, कार्यक्षमता आणि विकासालाच विरोध करणे, असा आभास निर्माण होतो. पण प्रश्न इतका सरळ नाही. लोकसभा आणि सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यासाठी केंद्र सरकार लवकरच संसदेत घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. या विधेयकाद्वारे घटनेत नवे कलम ८२-अ समाविष्ट करणे, तसेच कलम ८३ आणि १७२ मध्ये बदल करणे प्रस्तावित आहे. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत दोन-तृतीयांश बहुमत आणि त्यानंतर किमान निम्म्या राज्यांची मान्यता लागेल. म्हणजे ही केवळ निवडणुकीची नवी दिनदर्शिका नाही; देशाच्या संसदीय लोकशाहीचा आणि संघराज्यीय रचनेचा तो व्यापक फेरविचार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ चार प्रमुख फायदे मांडले आहेत. निवडणुकीचा खर्च कमी होणे, आचारसंहितेमुळे येणारा कथित धोरणलकवा दूर होणे, सरकारी कर्मचारी व सुरक्षा दलांवरील भार कमी होणे आणि आर्थिक वाढीला चालना मिळणे. यातील आर्थिक वाढीचा दावा विशेष लक्षवेधी आहे.

एका संशोधनानुसार लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्यानंतर वास्तविक आर्थिक वृद्धीदर सुमारे दीड टक्क्याने अधिक वाढेल. या दाव्यामागे निवडणुकीनंतर वाढणारा सरकारी खर्च, भांडवली खर्च आणि गुंतवणूक हे संभाव्य मार्ग सांगितले आहेत. हा निष्कर्ष प्रभावी वाटतो. पण एवढ्या मोठ्या घटनात्मक बदलाचा पाया एका सांख्यिकीय संबंधावर ठेवायचा असेल, तर तो संबंध कसून तपासला पाहिजे.

भारताच्या आर्थिक इतिहासाची धावती पाहणी केली, तरी हा दावा त्याच्याशी विसंगत वाटतो. १९५२ ते १९६७ या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका प्रामुख्याने एकत्र होत होत्या. पण हाच भारताच्या साडेतीन टक्के वार्षिक वाढीचा, परवाना-राजचा आणि बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा काळ होता. याउलट २००३ ते २०११ या वेगवान वाढीच्या काळात दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका सुरू होत्या. देशाने आठ ते नऊ टक्क्यांचा वृद्धीदर निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असतानाच साधला. अर्थात, यावरून वेगवेगळ्या निवडणुका झाल्यामुळे वाढ होते, असेही म्हणता येणार नाही. मुद्दा एवढाच की वाढीचे श्रेय निवडणुकांच्या वेळापत्रकाला देणे अतिशय धाडसी आहे. आर्थिक उदारीकरण, जागतिक व्यापार, माहिती-तंत्रज्ञानाची भरारी, भांडवलाचा ओघ, वित्तीय क्षेत्राचा विस्तार आणि १९९१ नंतरच्या सुधारणा - या सगळ्यांचा प्रभाव निवडणुकीच्या तारखांपेक्षा कितीतरी मोठा होता. शिवाय संबंधित संशोधनात वाढीबरोबर वित्तीय तूट आणि सरकारी खर्चही वाढताना दिसतो. मग ही अर्थव्यवस्थेची टिकाऊ संरचनात्मक सुधारणा म्हणायची, की निवडणुकीभोवती होणारा सरकारी खर्च एकाच काळात अधिक केंद्रित झाला, असे म्हणायचे? घटनात्मक फेरबदलासाठी केवळ सहसंबंध पुरेसा नसतो. कारण-परिणामाचा पुरावा अधिक मजबूत हवा.

आता खर्चाचा मुद्दा घ्या. निवडणुका फार महाग झाल्या आहेत, असे वारंवार म्हटले जाते. पण एक साधा प्रश्न विचारला पाहिजे. नेमका खर्च कोण करत आहे? निवडणूक आयोग आणि सरकारचा अधिकृत खर्च हा केंद्र सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या अत्यंत लहान भागाइतकाच आहे. ०.२ टक्क्यांपेक्षाही कमी. खरा मोठा खर्च राजकीय पक्ष आणि उमेदवार करतात. आणखी गंमत अशी की निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या अधिकृत हिशेबानुसार अनेक उमेदवार खर्चाच्या कायदेशीर मर्यादेच्या जवळही पोहोचत नाहीत. कागदावर ते मर्यादेपेक्षा खूपच कमी खर्च करतात. प्रत्यक्षात निवडणुकीत पैशाचा पूर वाहतो, हे सगळ्यांना माहीत आहे. मग उरलेला पैसा कुठे आहे? तो हिशेबात नाही. तो रोखीत आहे, काळ्या पैशात आहे, मतदारांना केलेल्या वाटपात आहे, वाहतूक, प्रचार, माध्यमे, स्थानिक जाळी आणि अपारदर्शक राजकीय व्यवहारांत आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण खर्च सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असावा, असा अंदाज ‘सीएमएस मीडिया’ने व्यक्त केला होता. पण एकत्र निवडणुका हा काळा पैसा रोखणार कसा? निवडणूक दरवर्षी झाली किंवा पाच वर्षांतून एकदा झाली, तरी रोख पैसा, आश्रयदात्यांचे जाळे (पॅट्रनेज नेटवर्क), मतदारांना प्रलोभने आणि अपारदर्शक देणग्या यांची राजकीय अर्थव्यवस्था तशीच राहते. उलट खर्च कमी होण्याऐवजी तो एका प्रचंड राष्ट्रीय महोत्सवात एकवटला जाऊ शकतो.

निवडणुकीचा खरा रोग पैशाची अमर्याद ताकद असेल, तर औषध निवडणुकीची तारीख बदलणे नाही. सर्व राजकीय देणग्यांचे सक्तीचे प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) आणि पारदर्शकता, पक्षांच्या खर्चावर प्रभावी मर्यादा, स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि निवडणूक आयोगाला अधिक स्वायत्त अधिकार - ही खरी उपाययोजना आहे. पैशाच्या दुष्प्रभावाला आळा घालण्यासाठी अनेक सुधारणा शक्य आहेत; त्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ आवश्यक नाही.

आचारसंहितेचाही मुद्दा तितकाच तपासण्यासारखा आहे. निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर साधारण ४५ ते ६० दिवस आचारसंहिता लागू असते. राज्यांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होत असल्याने वर्षातील काही महिने देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे निर्णयप्रक्रिया थांबते, विकास खुंटतो, असा दावा केला जातो. पण आचारसंहिता सरकारला राज्यकारभार बंद करण्यास सांगत नाही. नियमित प्रशासन सुरूच राहते. आधीच मंजूर झालेली कामेही सुरू राहू शकतात. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांना प्रभावित करणाऱ्या घोषणा करू नयेत, एवढाच तिचा मुख्य हेतू आहे. ही लोकशाहीतील आवश्यक मर्यादा आहे; प्रशासनातील बिघाड नव्हे. आज विविध राज्यांत वेगवेगळ्या वेळी लागू होणारी आचारसंहिता ‘एक देश, एक निवडणूक’ अंतर्गत एकाच वेळी संपूर्ण देशावर लागू होईल. म्हणजे व्यत्यय नाहीसा होणार नाही; तो पाच वर्षांतून एकदा देशभर एकवटला जाईल. त्या काळात केंद्र आणि सर्व राज्यांच्या नवीन घोषणांवर एकाच वेळी मर्यादा येतील. त्यामुळे कथित धोरणलकवा कमी होईलच, असे नाही. तो अधिक व्यापक होऊ शकतो.

याहून सर्वात गंभीर प्रश्न घटनात्मक आहेत. भारतातील संसदीय लोकशाहीचे मूलतत्त्व असे की सरकारकडे विधिमंडळाचा विश्वास असेपर्यंतच ते सत्तेत राहू शकते. बहुमत गेले की सरकार बदलले पाहिजे किंवा नव्या निवडणुका झाल्या पाहिजेत. पण संपूर्ण देशाने एका ठरावीक पाच वर्षांच्या चक्रातच राहायचे असेल, तर एखाद्या राज्यातील सरकारने मध्येच बहुमत गमावल्यावर काय करायचे? अल्पमतातील सरकारला निवडणुकीच्या ठरलेल्या तारखेपर्यंत ओढत ठेवायचे? राष्ट्रपती राजवट लावायची? की उरलेल्या अल्प कालावधीपुरते नवे सरकार बसवायचे? यापैकी एकही मार्ग समाधानकारक नाही. उच्चस्तरीय समितीने जर्मनीच्या धर्तीवरील ‘रचनात्मक अविश्वास ठराव’ सुचवला आहे. म्हणजे विद्यमान सरकारविरुद्ध अविश्वास ठराव आणताना पर्यायी सरकारलाही एकाच वेळी बहुमत दाखवावे लागेल. वरवर पाहता यामुळे स्थैर्य मिळते, पण भारतीय परिस्थितीत त्याचा अर्थ असा होऊ शकतो की, बहुमत गमावलेले सरकार पर्याय तयार होत नाही म्हणून सत्तेत टिकून राहील. लोकशाहीत स्थैर्य महत्त्वाचे आहे; पण उत्तरदायित्वापेक्षा ते मोठे नाही. विद्यमान पद्धतीशी अशी छेडछाड संसदीय लोकशाहीच्या मुळांवर (‘बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन’वर) परिणाम करू शकते, असा घटनातज्ज्ञांचा इशारा आहे. पहिल्या एकत्रित निवडणुकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी काही विधानसभांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल आणि काहींचा कमी करावा लागेल. दोन्ही मार्ग चुकीचे आहेत. कार्यकाळ वाढवला, तर मतदारांनी दिलेल्या पाच वर्षांच्या जनादेशापेक्षा अधिक काळ प्रतिनिधी सत्तेत राहतील. कार्यकाळ कमी केला, तर मतदारांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा कालावधी त्यांच्या संमतीशिवाय कापला जाईल. मतदार आणि प्रतिनिधी यांच्यातील कराराची मुदत सरकारच्या सोयीसाठी बदलता येईल का? विधी संस्थेच्या विश्लेषणात हा मुद्दा विशेष ठळकपणे मांडला आहे.

संघराज्याचाही प्रश्न आहे. भारत म्हणजे केवळ एक राष्ट्रीय राजकीय रंगमंच नाही. प्रत्येक राज्याचे प्रश्न, इतिहास आणि राजकीय प्राधान्ये वेगळी आहेत. विदर्भातील शेतकरी संकट, केरळच्या किनारपट्टीवरील उपजीविका, आसाममधील पूरनियंत्रण, महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था किंवा मुंबई-पुण्याची शहरी पायाभूत सुविधा - हे प्रश्न राष्ट्रीय निवडणुकीच्या अजेंड्यापेक्षा वेगळे असू शकतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या की राष्ट्रीय लाटेचा प्रभाव राज्यांवर पडतो. मतदार दोन्ही पातळ्यांवर एकाच पक्षाला मतदान करण्याची शक्यता वाढते. मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांना त्याचा फायदा होतो; प्रादेशिक पक्षांचे स्वतंत्र राजकीय अवकाश आकुंचन पावते. यामुळे भारताच्या राजकीय विविधतेला आणि संघराज्यीय संतुलनाला धोका निर्माण होऊ शकेल हे स्पष्ट आहे.

आणखी एक विसंगती म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्त्यांनी पंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांना स्वतंत्र घटनात्मक स्थान दिले. त्यांच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेतात. मुंबई, पुणे किंवा बेंगळूरुच्या महापालिकांचे अर्थसंकल्प अनेक लहान राज्यांपेक्षा मोठे आहेत. या निवडणुका किरकोळ नाहीत. त्यांनाही एकाच राष्ट्रीय चक्रात आणले, तर राज्य निवडणूक आयोगांची स्वायत्तता आणि स्थानिक लोकशाहीचे स्वरूप बाधित होईल. त्यांना वेगळे ठेवले तर खर्च, सुरक्षा यंत्रणा आणि आचारसंहितेबाबत ‘एक देश, एक निवडणूक’चा मूळ युक्तिवादच कमकुवत होतो. पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका तरीही वेगवेगळ्या वेळी चालूच राहतील.

सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की भारतीय निवडणुकांचे जे खरे आजार आहेत, त्यांना या प्रस्तावाने हातही लावलेला नाही. पक्षांच्या खर्चावर मर्यादा नाही. मोठ्या देणग्यांमध्ये पुरेशी पारदर्शकता नाही. गुन्हेगारी आरोप असलेले उमेदवार निवडणुका लढवतात. सरकारी यंत्रणेच्या गैरवापराच्या तक्रारी येतात. मतदारांना रोख रक्कम आणि वस्तू वाटल्या जातात. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेविषयी प्रश्न उपस्थित होतात. यासाठी लक्ष्यित सुधारणा हव्यात - सर्व देणग्यांचे पूर्ण प्रकटीकरण, राजकीय पक्षांच्या खर्चावर कायदेशीर मर्यादा, गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणांच्या जलदगतीने सुनावण्या किंवा अपात्रतेचे निकष अधिक कठोर करणे, पक्षांच्या खात्यांचे स्वतंत्र लेखापरीक्षण आणि खऱ्या अर्थाने स्वायत्त निवडणूक आयोग. या सर्व सुधारणा घटनेच्या संघराज्यीय आणि संसदीय पायाला धक्का न लावता करता येतात. ‘एक देश, एक निवडणूक’ निवडणुकांची दिनदर्शिका बदलू शकते, पण भारतीय निवडणूक व्यवस्थेत जे खरोखर बिघडले आहे ते ती दुरुस्त करत नाही. सुधारणा म्हणून मांडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बदलाकडे म्हणूनच संशयाने नव्हे, पण चिकित्सक नजरेने पाहिले पाहिजे. कार्यक्षमतेसाठी लोकशाही नसते; लोकशाहीच्या सेवेसाठी कार्यक्षमता असते.

अन्वयार्थ

अगतिक खलाशी, हतबल सरकार!

हे गेल्या काही महिन्यांतले प्रारूप ठरून गेले आहे : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत वरकरणी शांतता दिसून येणार. मग जहाजांची वर्दळ वाढणार. शांतता मंजूर नसलेल्यांकडून अचानक एक-दोन किंवा अधिक जहाजांवर अग्निबाण वा तत्सम मारा होणार. म्हणायला हा मारा म्हणजे जहाजांना दिलेला इशारा असतो. बऱ्याचदा यातून जहाजाचे नुकसान तर होतेच. पण मनुष्यहानीही होते. यातही सातत्याने भारतीय खलाशांचे बेपत्ता वा मृत होणे वारंवार घडू लागले आहे. ताज्या घटनेत हेरंब करमरकर हे पुण्यातील अभियंता मृत्युमुखी पडले. काही दिवसांपूर्वी एका जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात ते बेपत्ता झाले होते. अखेर त्यांच्या मृत्यूची दुर्दैवी वार्ता त्यांच्या कुटुंबीयांना ऐकावी लागली. बेपत्ता झालेल्या खलाशांचा शोध घेण्यासाठी मदतकार्य यंत्रणाच होर्मुझच्या आखातात सक्रिय नाही. कारण गेले काही महिने हा टापू एक युद्धभूमीच बनला आहे. पण त्याची झळ दोन्ही देशांना मित्र मानणाऱ्या भारताला सातत्याने बसणे खेदजनक आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून आखाती देशांतील खनिज तेल जगभर मार्गस्थ होते. आखाती देशांमध्ये इतर देशांतून बरीचशी वस्तुमाल आयातही याच जलमार्गाद्वारे होत असते. तेव्हा आखाती देश आणि जगातील इतर अनेक देश यांच्यासाठी हा जलमार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण जुन्या काळात महामार्गांवरील दरोडेखोर किंवा जलमार्गांवरील समुद्री चाचे वागायचे तद्वत सध्या अमेरिका, इराण आणि आणखी काही संबंधित देश वागत आहेत. त्यातही प्रामुख्याने दोष अमेरिका आणि इराणचाच. दोन्ही देशांमध्ये सातत्याने शस्त्रसंधी जाहीर होतो. काही दिवस त्याचे पालन होते. पण अल्पावधीनंतर शस्त्रसंधीचा भंग करण्याची स्पर्धाच दोन्ही देशांमध्ये दिसून येते. दोन्ही देश त्याबद्दल परस्परांना दोष देतात. होर्मुझवर ताबा कोणाचा राहणार हा मुद्दा आता केंद्रस्थानी आला आहे. या जलमार्गावरून जहाजांची निर्धोक वाहतूक व्हावी यासाठी ‘शुल्क’ आकारण्याची भूमिका इराणने युद्ध सुरू झाल्यापासून मांडायला सुरुवात केली होती. अमेरिका आणि इस्रायलच्या हल्ल्यांमध्ये आमचे जे नुकसान झाले, त्याची भरपाई करण्यासाठी शुल्क आकारणे आवश्यक असल्याचे इराणचे नेते म्हणू लागले. होर्मुझचा एक भाग इराणच्या ताब्यात आहे नि दुसरा भाग ओमानच्या. पण हा अत्यंत महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग असल्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांच्या नियमांनुसार, त्यातून होणाऱ्या वाहतुकीवर दोन्ही देशांना शुल्क आकारता येऊ शकत नाही. ही बाब जशी इराणला ठाऊक नाही, तशी ती अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही ठाऊक नसावी. त्यामुळे जलवाहतुकीस संरक्षण हमी म्हणून शुल्क आकारण्याची कल्पना त्यांच्याकडून वारंवार व्यक्त होत असते. या दोन्ही युद्धपिपासू देशांनी होर्मुझला वेठीस धरले आहे. नजीकच्या काळात हा मार्ग निर्धोक होण्याची चिन्हे नाहीत. जोवर युद्धसमाप्ती होत नाही आणि कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही तोवर असेच चालू राहणार. आता तर परस्परांवर हल्ल्यांची तीव्रता वाढल्यामुळे पुन्हा एकदा युद्धाला तोंड फुटण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. त्यामुळे आखातात स्थायिक आणि जहाजांवर तैनात भारतीयांचे जीव पुन्हा एकदा धोक्यात येऊ लागले आहेत.

एका आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारीपासून एकट्या होर्मुझवरील हल्ल्यांमध्ये १५ भारतीयांचा मृत्यू झाला आहे. जीव धोक्यात घालून रोजगारासाठी अशा जहाजांवर राहण्याची त्यांची अगतिकता समजण्यासारखी आहे. पण याविषयी भारत सरकारने दाखवलेली हतबलता अधिक अनाकलनीय आहे. सातत्याने भारतीयांचा जीव जात असतानाही आपण पुरेशा तीव्रतेने याविषयी इराण किंवा अमेरिकेला जाब विचारत नाही हे अस्वस्थ करणारे वास्तव आहे. अशा भारतीयांची इत्थंभूत माहिती संकलित करण्यातही आपण कमी पडत आहोत हे उघड आहे. संघटित वा असंघटित, कौशल्यधारी किंवा अकुशल कामगारांचे लोंढे भारतातून जगभर जात आहेत. कधी वैध मार्गाने, कधी अवैध मार्गाने. आपले भारतीय कधी रशियाकडून लढताना युक्रेनच्या युद्धभूमीवर प्राण गमावतात, कधी लेबनॉनमध्ये शेतमजूर म्हणून राबताना इस्रायली हल्ल्यांत प्राण गमावतात. सर्वाधिक वेगाने वगैरे वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी हे जितके नामुष्कीजनक, तितकेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात वजनवृद्धीचा दावा करणाऱ्या आपल्या शासकांसाठी ते चिंताजनकही. या अभागी भारतीयांचे जीवितरक्षण घोषणांतून नव्हे, तर कृतीतून साधावे लागेल.

निकृष्ट सोयाबीनचा फटका किती गंभीर?

विश्लेषण

दत्ता जाधव
dattatray.jadhav@expressindia.com

> विदर्भ, मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादक पट्ट्यातील तब्बल १० प्रमुख जिल्ह्यांत पेरणी केलेल्या सोयाबीनची अपेक्षित उगवण झाली नाही. तब्बल १८ बियाणे कंपन्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या आहेत.

सोयाबीन बियाणांबाबत नेमके काय घडले?

सोयाबीनच्या निकृष्ट बियाणांचा विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दहा जिल्ह्यांना फटका बसला आहे. अपेक्षित उगवण झाली नाही, अशी १८ बियाणे कंपन्यांच्या विरोधात तक्रारी असून, त्यापैकी चारविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आहेत. देशात सरासरी २०० लाख क्विंटल सोयाबीन उत्पादित होते. त्यापैकी महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशात प्रत्येकी सरासरी ५० लाख हेक्टरवर पेरणी होऊन प्रत्येकी सरासरी १०० लाख टन सोयाबीन उत्पादित होते. राज्यात यंदा १३ जुलैअखेर राज्यात ३७ लाख ३६ हजार हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली आहे. यंदा सोयाबीन बियाणांच्या उगवण क्षमतेबाबत अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वर्धा, चंद्रपूर, नागपूर, वाशिम, लातूर, धाराशिव, या जिल्ह्यांतून कृषी विभागाकडे तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी अकोला, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ या चार जिल्ह्यांत तक्रारीचे प्रमाण जास्त आहे.

कृषी विभागाने काय कारवाई केली?

कृषी विभागाने संबंधित बियाणे कंपन्यांवर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम कलम, बीज कायदा, बियाणे नियम १९६८ आणि भारतीय न्याय संहितेतील कलमांनुसार गुन्हे दाखल करून बियाणे विक्री बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. निकृष्ट बियाणांचा फटका बसला आहे, अशा शेतकऱ्यांनी संबंधित बियाणे कंपनी विरोधात तातडीने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे नुकसानभरपाईसाठी दावे दाखल करावेत. संबंधित कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना निःशुल्क, चांगले बियाणे बदलून द्यावेत अशा सूचना दिल्या आहेत.

बियाणे कंपन्यांना मोकळे रान मिळाले?

अकोला कृषी विद्यापीठाने पांढऱ्या फुलाचे बियाणे विकसित केले आहे. त्याला चांगला दर मिळतो, अशी आवई उठविण्यात आली. त्यासाठी गतवर्षी सोयाबीन कंपन्यांनी वाशीम, अकोला येथील बाजार समितीतून पांढऱ्या फुलाच्या सोयाबीनची तब्बल नऊ हजार प्रति क्विंटल दराने खरेदी केली. कंपन्यांनी हे सोयाबीन खरेदी करून जुजबी प्रक्रिया करून २५ किलोची बियाणांची पिशवी सरासरी चार हजार रुपये किलो दराने विकली. कृषी विभागाने या कंपन्यांची बियाणे कुठून आली, बियाणांसाठी स्वतंत्र लागवड केली होती का, संबंधित कंपन्यांनी प्रचार - प्रसिद्धी करताना केलेले दावे, कंपनीच्या क्षमतेपेक्षा जास्त सोयाबीनची विक्री याकडे दुर्लक्ष केले. दरवर्षी कृषी विभाग सोयाबीनचे घरातील बियाणे पेरा, असे आवाहन करतो, यंदा ते दिसून आले नाही. उगवण क्षमता तपासणी नेमक्या कोणत्या बियाणांची केली, असे विविध प्रश्न उपस्थितीत झाले आहेत.

देशातील बियाणे कायदे कुचकामी?

देशात बियाणे कायदा २९ डिसेंबर १९६६ रोजी तयार केला गेला. त्याची नियमावली १९६८ मध्ये अस्तित्वात आली. स्वतंत्र बियाणे आदेश १९८३ मध्ये काढण्यात आले. या तिन्हींच्या आधारे सध्या बियाण्याची बाजारपेठ नियंत्रित केली जाते. मात्र, गैरप्रकार रोखण्यास व शेतकऱ्यांना भक्कम आधार देण्यास या तरतुदी प्रभावी नाहीत. बोगस किंवा निकृष्ट बियाणे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद कोणत्याही सरकारने केली नाही. बियाणे सुधारणा विधेयक - २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणारे कायदेशीर कलम प्रथमच समाविष्ट केले गेले आहे. नव्या कायद्याच्या २१व्या कलमात, ‘शेतकऱ्यांना चुकीचे बियाणे दिल्यास उत्पादक, विक्रेता, वितरक यांच्याकडून ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार भरपाई मागता येईल,’ अशी स्पष्ट तरतूद केली गेली आहे. पण, झालेला खर्च पाहता, मिळणारी नुकसानभरपाई अत्यंत तोकडी असते.

शेतकऱ्यांची आर्थिक, कायदेशीर कोंडी कशी होते?

बोगस बियाणांसंबंधी तक्रार केल्यानंतर कृषी विभागाकडून केले जाणारे पंचनामे ही शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच असते. बियाणे किती खोलीवर जमिनीमध्ये टाकले आहे, बियाणे तिफणीने पेरले की ट्रॅक्टरने, तिफणीपासून बैल किती अंतरावर चालत होता, तिफणीच्या फनाची लांबी किती, उंची किती, कोणत्या खताचा वापर केला, शेणखताचा वापर केला का, बियाणे पेरले त्या शेतातील माती परीक्षण केले होते का, अशा प्रश्नांचा भडिमार शेतकऱ्यांवर केला जातो. कृषी सेवा केंद्राकडून बियाणांच्या नावाखाली होणारी लूट, कृत्रिम टंचाई वेगळीच.

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

भ्रष्टाचार के खिलाफ

भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी राज्य सरकार या राजनेता का हर कदम सुखद और स्वागतयोग्य है। विपक्ष में बैठने वाले राजनेताओं के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन सत्ता में बैठे नेता कभी-कभार ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई विचार या समाधान पेश करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ समाधान पेश करने वालों की कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय का भी नाम जुड़ गया है। उन्होंने लोगों से कहा है कि जब कोई रिश्वत मांगे, तो इनकार कर दीजिए। उनके राज्य में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी या सत्ता के दुरुपयोग में लिप्त किसी भी व्यक्ति को ऐसे कृत्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री का यह बयान ध्यान खींचता है, लेकिन क्या इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम कहा जा सकता है? दरअसल, फिल्म अभिनेता रहे मुख्यमंत्री की अपील में सिनेमाई भावुकता ज्यादा है। उन्होंने लोगों से कहा है कि मैं आपके साथ हूं। रिश्वत मांगने वालों से कहे दें कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा विजय इस राज्य पर शासन कर रहा है। जाहिर है, मुख्यमंत्री की इस बात पर तालियां खूब बजीं, लेकिन क्या वाकई उनकी सलाह व्यावहारिक है? क्या रिश्वत देने से इनकार करने या मुख्यमंत्री को भाई या बेटा बता देने से भ्रष्ट अधिकारी या नेता सुधर जाएंगे?

अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है। आम आदमी पार्टी के नेता भी जनता और अपनी पार्टी के स्वयंसेवकों को भ्रष्ट अफसरों को बेनकाब करने के लिए अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। यह पार्टी करीब एक दशक सत्ता में रही, लेकिन दिल्ली में कितने भ्रष्ट अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई? दरअसल, भ्रष्टाचारियों से लड़ने के दावे करना और उनके खिलाफ सक्रियता से लड़ने के बीच बहुत फासला है। यहां कथनी और करनी का अंतर विशाल हो जाता है। ओडिशा में आज भी याद किया जाता है कि वहां के मुखर मुख्यमंत्री बीजू पटनायक ने साल 1991 में सार्वजनिक रूप से नागरिकों को भ्रष्ट अधिकारियों को पीटने के लिए प्रोत्साहित किया था, लेकिन लगे हाथ यह भी कह दिया था कि पीटने से पहले मेरी मंजूरी के लिए मुझे एक टेलीग्राम भेज दें। अब तो वैसे टेलीग्राम का जमाना नहीं रहा, अब साइबर टेलीग्राम व अन्य सोशल मीडिया मंचों का जमाना है, लेकिन संचार माध्यमों की अत्याधुनिकता के बावजूद भ्रष्टाचार की शिकायत के मोर्चे में हम पिछली सदी में ही छूट गए हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत करना पिछली सदी के समान ही कठिन है।

विजय जैसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री से उम्मीद करनी चाहिए। एक अपेक्षाकृत संपन्न राज्य तमिलनाडु में भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, तो लाभ पूरे देश को होगा।

भ्रष्टाचार पर यदा-कदा होने वाले जन-सर्वेक्षण साफ बयान कर देते हैं कि देश में कहां-कितना भ्रष्टाचार है। बेशक, डिजिटलाइजेशन और 'डायरेक्ट फंड ट्रांसफर' होने की वजह से भ्रष्टाचार घटा है, लेकिन हमारी व्यवस्था में आंतरिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी सख्त उपायों का अभी भी अभाव है। अनेक दफ्तरों या सौदों में पैसों की लेन-देन में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं आई है। यह सर्वविदित है कि रिश्वत में सीधे धन लेने के बजाय सेवा या सामग्री लेने का चलन बढ़ा है। हम एक ऐसे दौर में हैं, जब हमारे तंत्र के सबसे विश्वसनीय स्तंभ न्यायपालिका में भी गलत आचरण की खुली शिकायतें सबके सामने हैं। निस्संदेह, विजय जैसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री से लोगों को उम्मीद करनी चाहिए। देश के एक अपेक्षाकृत संपन्न राज्य तमिलनाडु में अगर भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है, तो लाभ पूरे देश को होगा। दूसरे राज्यों के लोगों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम बढ़ाने के लिए एक नई राह दिखाई पड़ेगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 16 जुलाई, 1951

कांग्रेस का घोषणा पत्र

देश में आम चुनाव निकट आ रहे हैं और उनमें मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों को अपनी नीति और कार्यक्रम के बारे में घोषणा पत्र के रूप में अपना मतव्य प्रकाशित करना होगा। कांग्रेस देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाली मुख्य संस्था थी। देश को विदेशी गुलामी से मुक्त देखने की इच्छा रखने वाले सभी तत्वों का उसे समर्थन प्राप्त था। पूंजीपति, व्यापारी, किसान और मजदूर आदि सभी वर्ग कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस का यह दावा था कि वही देश का एकमात्र प्रतिनिधित्व करती है। उसके इस दावे को विदेशी शासकों ने भी स्वीकार किया और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता सौंप कर यहां से विदा हुए।

किन्तु अब स्थिति बदल गई है। अवश्य ही आजादी के लिए लड़ने और अन्त में सफलता प्राप्त करने वाली संस्था के रूप में कांग्रेस ने जो असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त की, उस पुरानी पूंजी की वह अब भी उत्तराधिकारिणी है। कांग्रेस के नेता आज भी वही है, जिन्होंने वर्षों त्याग और तपस्या का जीवन बिताया है और जिनके प्रति जनता के दिल में श्रद्धा और आदर की भावना है। किन्तु कांग्रेस का अब पुराना राष्ट्रीय स्वरूप बदल गया है। उसकी हैसियत एक राजनीतिक दल की हो गई है। भले ही कांग्रेस देश का सबसे अधिक व्यापक साधन सम्पन्न और शक्तिशाली दल हो, किन्तु है वह देश के अनेक दलों में से एक दल। आगामी चुनावों में कांग्रेस को अनेक राजनीतिक, धार्मिक, साम्प्रदायिक दलों की प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ेगा। पिछले चार वर्षों से कांग्रेस सत्तारूढ़ है और सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में वह अन्य पार्टियों के मुकाबले सुविधाजनक स्थिति में है। किन्तु साथ ही उसके लिए उन सब आशाओं को पूरा करना संभव नहीं हो सका है, जो जनसाधारण ने उससे की थी। इस कारण लोग कांग्रेस से थोड़े निराश भी हुए हैं। पिछले चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवारों का मार्ग जितना सरल रहा उतना आगे रहने की आशा नहीं की जा सकती। अतः मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को पहले से अधिक परिश्रम करना होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र ने कांग्रेस के आदर्शों, नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने प्रस्तुत कर दिया है। आज कांग्रेस पर सबसे अधिक छाप नेहरूजी की है। चुनाव घोषणा पत्र उन्होंने ही तैयार किया है।

अपनी हदें पार नहीं करेंगे दोनों देश

अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर बैठ जाएं, ऐसी कोशिश परदे के पीछे से खाड़ी के कई देश कर रहे हैं, हालांकि वे जानते हैं कि यह काम अब आसान नहीं है।

यहां स्कैन करें

विवेक काटजू | पूर्व राजनयिक

अमेरिका और ईरान के बीच जून में जिस 'मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग' (सहमति-पत्र) पर सहमति बनी थी, वह पिछले हफ्ते नए हमलों की शुरुआत के साथ तार-तार हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस को बताया है कि तेहरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई करनी होगी। हालांकि, दोनों देश यह जानते हैं कि कुछ ऐसी लाल रेखाएं हैं, जिनके भीतर ही उनको रहना होगा। अगर उन्होंने इन हदों को पार किया, तो खाड़ी के तेल व गैस भंडारों को व्यापक क्षति पहुंचेगी और यहां जनजीवन खतरे में पड़ सकता है। अमेरिकी हमलों के कारण ईरान से पलायन भी शुरू हो सकता है। ये ऐसी परिस्थितियां हैं, जिन्हें न अमेरिका चाहता है, न ईरान और न ही दुनिया का कोई अन्य देश।

मुश्किल यह है कि अमेरिका में ट्रंप और ईरान में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं। हालांकि, सवाल ईरान के शीर्ष नेतृत्व को लेकर भी उठने लगे हैं, क्योंकि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में उनके उत्तराधिकारी और बेटे मुजतबा खामेनेई नहीं दिखे। अगर मुजतबा अपने अवाम और दुनिया के सामने थोड़े समय के लिए ही सही, आ जाते, तो यही माना जाता कि ईरान में अंतिम निर्णय वही ले रहे हैं। अब चूंकि तेहरान में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता नहीं है, इसलिए यह कहना कठिन है कि वहां युद्ध और शांति के फैसले कौन लेगा?

बहरहाल, इन सभी घटनाक्रमों ने एक बार फिर खाड़ी से तेल और गैस की आपूर्ति में रुकावटें पैदा कर दी हैं। कच्चे तेल के दाम चढ़ गए हैं और कुछ हद तक दुनिया के तमाम शेयर बाजारों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ा है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? इस वक्त होर्मुज जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही कठिन है। अमेरिका ने भी अब नाकेबंदी की घोषणा कर दी है, जिसका अर्थ है कि होर्मुज के जरिये ईरान भी अपना तेल दुनिया में निर्यात नहीं कर सकेगा। हालांकि, तेहरान ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर हालात यूं ही बने रहे, तो वह बाकी जलमार्गों पर भी आवाजाही रोक देगा। उसका इशारा यमन और अफ्रीका के बीच स्थित बाब-अल-मंदेब जलमार्ग है, जहां वह अपने साथी हूती विद्रोही समूह के जरिये रुकावटें पैदा कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, तो दुनिया में ऊर्जा की स्थिति और व्यापार पर गंभीर असर पड़ेगा।

साफ है, जिस एमओयू से यह उम्मीद जगी थी कि ईरान युद्ध का अब अंत होगा और बेपटरी हो चुकी विश्व अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ेगी, वह धूमिल पड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी बातों पर अटल नहीं रहते। वह कभी कुछ कहते हैं, तो कभी कुछ। पिछले दिनों ही उन्होंने एलान किया कि अमेरिका होर्मुज को सुरक्षा देगा और उसके एवज में 20 प्रतिशत फीस वसूलेगा, लेकिन 24 घंटे बाद ही वह इससे पलट गए। जब से (28 फरवरी) ईरान युद्ध शुरू हुआ है, तब से ट्रंप ने अपने बयान इतनी बार बदले हैं कि अब उनकी कथनी पर भरोसा नहीं रह गया है। नजर अब अमेरिका की करनी पर है, और नाकेबंदी का एलान करके उसने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है।

परदे के पीछे से खाड़ी के कई देश इस कोशिश में हैं कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान सैन्य टकराव का रास्ता छोड़कर बातचीत की मेज पर बैठ जाएं, मगर वे जानते हैं कि यह काम आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका की शर्त यही है कि ईरान के पास न परमाणु हथियार हों और न वह यूरेनियम का संवर्द्धन करे। इसे मानना तेहरान के लिए कठिन है। हालांकि, बात यहां तक पहुंची भी नहीं है। उधर, ईरान की मंशा है कि समुद्री जहाज उस रास्ते से गुजरें, जो उसके तट के पास से निकलता है। ओमान के तट के पास से खुल चुके नए रास्ते का वह विरोध कर रहा है और वहां से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना रहा है। वह यह सरासर गलत कर रहा है। उसे समझना चाहिए कि यदि वह अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करेगा, तो न विश्व समुदाय में और न ही इस्लामी दुनिया में उसे समर्थन मिल सकेगा।

जहां तक भारत की बात है, तो हम हमेशा से यही मानते रहे हैं कि ईरान युद्ध का समाधान राजनय के सिद्धातों से ही निकल सकता है, युद्ध से तो कतई नहीं, क्योंकि इससे विनाश होता है। खाड़ी युद्ध से भारत में ऊर्जा संकट बढ़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों घोषणा की थी कि अपने कुशल राजनय के चलते भारत ने ऊर्जा संकट को टालने में सफलता हासिल की है। यह संतोष की बात है, लेकिन ऊर्जा के साथ-साथ भारत के आर्थिक और व्यापारिक हित भी खाड़ी से जुड़े हुए हैं। और, इन सबसे बढ़कर करीब 90 लाख से एक करोड़ तक भारतीय वहां रहते और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। युद्ध की आग बढ़ने पर उनके भविष्य पर खतरा पैदा हो सकता है।

ऐसे में, भारत को अपने कूटनीतिक प्रयास और व्यापक व तेज करने होंगे। साथ ही, खाड़ी के देशों को भी यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि नई दिल्ली संतुलित नीति अपनाती है, इसलिए यह अनिवार्य था कि अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधिमंडल गया और कुछ दिन पूर्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खाड़ी के चार देशों का दौरा किया। हां, भारत के संबंध संयुक्त अरब अमीरात के साथ घनिष्ठ हैं और प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते भी अबूधाबी के शासक के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कूटनीति की मांग यही है कि इन संबंधों को भी कायम रखा जाए और दूसरे देशों को भी ऐसा न लगे कि उनकी अनदेखी की जा रही है।

भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया का हरेक देश ईरान युद्ध से हलकान है। बेशक, पाकिस्तान ने पहले मध्यस्थता की थी और उसे कुछ हद तक इसमें सफलता भी मिली, लेकिन चूंकि युद्ध के कारण दक्षिण एशिया के तमाम देशों के हितों पर प्रतिकूल असर पड़ा है, इसलिए भारत सरकार को एक ऐसा राजनयिक कदम उठाना चाहिए कि सभी दक्षिण एशियाई देश एक स्वर में इस युद्ध की समाप्ति की मांग करते दिखें। आखिरकार विश्व की करीब 25 प्रतिशत आबादी इसी खित्ते में रहती है और ईरान युद्ध का उन पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

ग्रेट निकोबार परियोजना का विरोध कितना जायज

यहां स्कैन करें

दिलीप मंडल | वरिष्ठ पत्रकार

विकास या पर्यावरण? यह बहस नई नहीं है। यह बहस जितनी पुरानी है, उतनी ही भ्रामक भी है, क्योंकि वास्तविक प्रश्न विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। वास्तविक प्रश्न है कि क्या भारत अपने विकास के अधिकार व अवसरों का उपयोग करते हुए पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रह सकता है? इसका उत्तर 'हां' है। यह केवल संभव ही नहीं, बल्कि सबसे श्रेयस्कर मार्ग भी है।

विकसित भारत बनाना एक राष्ट्रीय स्वप्न है। करोड़ों भारतीयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर देश को निम्न-आय वाले देशों की श्रेणी से निकालकर मध्यम आय वर्ग वाले देशों की श्रेणी में शामिल कराना एक पवित्र लक्ष्य है। इसके लिए बिजली, सड़कें, रेल, बंदरगाह, कारखाने, डाटा सेंटर, आधुनिक खेती, गोदाम और आधुनिक बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार करना होगा। भारतीय दृष्टि यहां ठहरकर सोचने को कहती है और फिर यह मार्ग सामने आता है। ऐसा विकास नहीं चाहिए, जो प्रकृति को केवल लूटे जाने वाले संसाधन के रूप में देखता हो। साथ ही, ऐसा पर्यावरणवाद भी स्वीकार्य नहीं हो सकता, जो हरेक राष्ट्रीय परियोजना को संदेह की दृष्टि से देखता हो। ग्रेट निकोबार परियोजना इस बहस को समझने का अच्छा अवसर देती है। निकोबार द्वीप समूह भारत की व्यापारिक क्षमता और सामरिक भविष्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मलक्का जलडमरूमध्य के निकट इसकी स्थिति इसे वैश्विक समुद्री व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल करती है। चोल राजाओं के समय यह व्यापार और सैन्य अभियानों में शामिल जहाजों का महत्वपूर्ण पड़ाव था। आज जब हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल रहा है, होर्मुज जैसे संकट आपूर्ति श्रृंखला की संवेदनशीलता उजागर कर रहे हैं, तब इस क्षेत्र में आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित करना देश की आर्थिक रणनीतिक आवश्यकता है। फिर भी इस परियोजना का विरोध हो रहा है।

बीते कुछ दशकों में देश में ऐसी पर्यावरणीय राजनीति उभरी है, जिसका स्थायी भाव विरोध है। मानो विकास आपराधिक गतिविधि हो।

किसी भी प्रोजेक्ट के पर्यावरणीय प्रभावों की जांच होनी चाहिए। 'नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल' ने इस परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय चिंताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जो उचित है। समस्या तब शुरू होती है जब पर्यावरणीय चिंताओं का उद्देश्य समाधान खोजना नहीं, बल्कि विकास को रोकना बन जाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत में एक ऐसी पर्यावरणीय राजनीति उभरी है, जिसका स्थायी भाव विरोध है। मानो विकास स्वयं में एक आपराधिक गतिविधि हो। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह दृष्टिकोण सही नहीं है।

इस बहस का वैचारिक-दार्शनिक पक्ष भी है। पश्चिम में लंबे समय तक यह विचार प्रभावशाली रहा कि मनुष्य प्रकृति का स्वामी है और प्रकृति उसके उपभोग के लिए है। इस सोच ने आधुनिक औद्योगिक विकास को गति दी, पर इसी ने संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को भी वैचारिक आधार दिया। इस दृष्टि के सूत्र *बाइबिल* की उस व्याख्या में मिलते हैं, जो मनुष्य को सृष्टि पर विशेष अधिकार देती है। इसलिए जब पश्चिम के ईसाई देश औद्योगिकीकरण की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब विकास व पर्यावरण में संतुलन का प्रश्न नहीं उठा। इस्लाम समेत अन्य अब्राहमिक परंपराओं में भी मनुष्य को सृष्टि में विशेष स्थान प्राप्त है। इसलिए वहां प्रकृति के उपयोग को लेकर वैसी दार्शनिक दुविधा नहीं दिखाई देती, जैसी भारतीय परंपराओं में मिलती है।

भारतीय परंपरा प्रकृति को निर्जीव वस्तु नहीं मानती। यहां नदियां, दिशाएं, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत सब पूजनीय हैं, वृक्षों का धार्मिक महत्व है और जीव-जंतु-पेड़-घास सब सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा हैं। भारतीय चिंतन मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं, उसका एक अंग मानता है। *ऋग्वेद* का मूल स्वर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और सह-अस्तित्व का है। बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग भारत का दार्शनिक लैंप पोस्ट है। न प्रकृति सबसे ऊपर है, न मनुष्य। न विकास हर कीमत पर उचित है, न उसका पूर्ण निषेध। इसलिए ग्रेट निकोबार में डीप-सी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना चाहिए।

आज भी भारत के कंटेनर व्यापार का एक बड़ा हिस्सा सिंगापुर, कोलंबो और अन्य विदेशी बंदरगाहों के जरिये ट्रांसशिप होता है। अंडमान-निकोबार का 94 प्रतिशत क्षेत्र आज भी वनों से आच्छादित है। ग्रेट निकोबार परियोजना से इसका एक छोटा हिस्सा प्रभावित होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सबसे श्रेष्ठ मौन दीक्षा

क्या उपदेश का यह मतलब है कि मंच पर खड़े होकर लोगों के समक्ष ऊंची आवाज में प्रवचन करते फिरें? उपदेश ज्ञान का सीधा संक्रमण है। वस्तुतः ज्ञानोपदेश मौन से ही दिया जा सकता है। आप उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं, जो एक घंटे तक प्रवचन सुनने के पश्चात प्रभावित हुए बिना चला जाता है और उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसकी तुलना किसी दूसरे मनुष्य से कीजिए, जो किसी पवित्र संत के पास बैठता है और थोड़ी देर बाद अपनी जीवन-दृष्टि में पूर्ण परिवर्तन के साथ वापस जाता है। इनमें से क्या बेहतर है? जोर-शोर से प्रभावहीन प्रवचन करना या फिर मौन बैठकर आंतरिक शक्ति प्रसारित करना?

दूसरी बात, वाणी कैसे उत्पन्न होती है? प्रथम अमूर्त ज्ञान है, उसमें से अहंकार उत्पन्न होता है, जो विचार को जन्म देता है और विचार से मौखिक शब्द उत्पन्न होता है। इस प्रकार शब्द मूलस्त्रोत का प्रपौत्र है। यदि शब्द असर करता है, तो आप ही निर्णय कीजिए कि मौन उपदेश कितना प्रबल होना चाहिए? आपके मन में सवाल उठ सकता है कि मौन क्या इतना शक्तिशाली होता होगा? सिद्ध पुरुष आध्यात्मिक प्रभाव की तरंगें प्रसारित करता रहता है, जो जिज्ञासु मनुष्यों को उसकी ओर आकृष्ट करती हैं। वह चाहे गुफा में बैठा हो या पूर्ण मौन रखता हो, उसका प्रभाव अमोघ होता है। हम सत्य पर प्रवचन को सुनकर विषय को समझे बिना ही वापस चले आते हैं, लेकिन किसी आत्मनिष्ठ महात्मा के संपर्क में आने से, चाहे वह कुछ भी न कहे, सत्य के विषय में बहुत अधिक समझ हमें प्राप्त होती है। उसे लोगों के बीच जाने की कभी भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वह दूसरों को निमित्त बना सकता है।

सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है, जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में निरंतर प्रकट होता रहता है। यदि सद्गुरु की दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है, तो मौखिक शब्द-व्यवहार बिल्कुल निरर्थक है। मौन सबसे श्रेष्ठ तथा सबसे अधिक प्रभावशाली दीक्षा है। श्री दक्षिणामूर्ति ऐसी ही दीक्षा देते थे। स्पर्श, दृष्टि इत्यादि से दी जाने वाली दीक्षा निम्न स्तर की है। मौन दीक्षा सबके हृदयों में परिवर्तन लाती है। शिष्यों के पास आने पर दक्षिणामूर्ति मौन रहते। यह सबसे ऊंची दीक्षा है। इसमें दीक्षा के अन्य प्रकारों का समावेश है।

सद्गुरु मौन अवस्था का प्रदाता है, जिसमें आत्मज्ञान का प्रकाश शेष सत्य के रूप में प्रकट होता रहता है। यदि उसकी दृष्टि शिष्य की दृष्टि से मिलती है, तो मौखिक शब्द-व्यवहार निरर्थक है।

दूसरी दीक्षाओं में द्रष्टा-दृश्य का संबंध स्थापित करना पड़ता है। प्रथम द्रष्टा और तब दृश्य प्रकट होना चाहिए। जब तक ये दो नहीं होते, एक-दूसरे को देख या छू कैसे सकता है? मौन दीक्षा परिपूर्ण है। इसमें देखना, स्पर्श करना और उपदेश देना शामिल हैं। यह दीक्षा शिष्य को सब तरह से शुद्ध कर देती है, और उसको सत्य में प्रतिष्ठित कर देती है।

रमण महर्षि

ओम बिरला | लोकसभा अध्यक्ष

भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने के सबसे मजबूत आधार हैं। देश के युवा नवाचार अपनाएं, तो भारत दुनिया का सबसे सक्षम और अग्रणी राष्ट्र बनेगा।

अनशन खत्म करना पराजय नहीं

सोनम वांगचुक से पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अब यह अनशन समाप्त कर दीजिए। आपकी लड़ाई गलत नहीं है, परीक्षा व्यवस्था में होने वाली गड़बड़ियों पर आपका गुस्सा भी गलत नहीं है, सत्ता से जवाबदेही की मांग करना भी गलत नहीं है, लेकिन अपने शरीर को रोज थोड़ा-थोड़ा समाप्त करना किसी आंदोलन की अनिवार्य शर्त नहीं है। देश को आपकी मृत्यु से पैदा होने वाली दो दिन की सनसनी नहीं चाहिए। देश को आपकी बुद्धि, रचनात्मकता आपके अनुभव और साहस अगले कई वर्षों तक चाहिए। किसी आंदोलन की सफलता इस बात से नहीं नापी जाती कि उसके सबसे सम्मानित व्यक्ति ने अपने शरीर को कितना कष्ट दिया, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि आंदोलन ने सत्ता के लिए उसे अनदेखा करना कितना महंगा बना दिया।

अनशन एक नैतिक हथियार है, लेकिन हर हथियार हर परिस्थिति में काम नहीं करता। वह तभी असर करता है, जब उसके पीछे व्यापक जनसमर्थन हो, मांग स्पष्ट और बातचीत योग्य हो। अन्ना हजारे के 2011 वाले आंदोलन से इसकी तुलना भी अधूरी है। अगस्त 2011 में अन्ना का उपवास बारह दिन चला और तेरहवें दिन समाप्त हुआ, लेकिन उस समय देशभर में प्रदर्शन हो रहे थे, चौबीसों घंटे मीडिया कवरेज थी, संसद बहस कर रही थी और सरकार के प्रतिनिधि लगातार बातचीत में लगे थे। उस आंदोलन के पीछे एक ऐसा जन-दबाव खड़ा हो गया था, जिसे सरकार केवल आंख बंद करके समाप्त नहीं कर सकती थी। आज जंतर मंतर पर बैठे लोगों की भावना उतनी ही सच्ची हो सकती है, लेकिन भावना और राजनीतिक ताकत एक ही चीज नहीं होती।

सीजेपी को भी आत्ममंथन करना चाहिए। आंदोलन कोई रोज प्रसारित होने वाली कंटेंट सीरीज नहीं है, जिसमें हर दिन एक नया वीडियो, एक नया नारा, एक नया भावुक दृश्य और अगले दिन के लिए नया सस्पेंस तैयार किया जाए। राजनीतिक संगठन का काम अपने सबसे प्रतिष्ठित समर्थक की देह को दांव पर लगाकर सरकार को ललकारना नहीं, बल्कि ऐसी रणनीति बनाना है, जिसमें कार्यकर्ता लड़ें और व्यक्ति सुरक्षित रहे। यदि पूरा आंदोलन एक व्यक्ति के गिरते रक्तचाप और घटते वजन पर टिक गया है, तो यह आंदोलन की शक्ति नहीं, उसकी रणनीतिक विफलता है।

ऐसे में, अनशन समाप्त करना पराजय नहीं होगा। सोनम वांगचुक, कृपया उठ जाइए। देश को आपकी आवाज चाहिए, आपके विचार चाहिए, आपके प्रयोग चाहिए और आपकी जिद चाहिए। हर लड़ाई में मर जाना बहादुरी नहीं।

असीम तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

सोनम वांगचुक

वांगचुक अपने उसूलों से पीछे हट रहे

सोनम वांगचुक का उपवास जारी है। कई लोग अपील कर रहे हैं कि वह अनशन तोड़ दें, क्योंकि जिनके लिए कर रहे हैं, उन्हें ही फिक्र नहीं है। कुछ लोग तो समाज को ही मरा हुआ ठहरा रहे हैं। कुछ कह रहे कि अहंकारी सत्ता के सामने मरने से भला क्या लाभ? कोई छात्रों को कह रहा, कोई समाज को, यही नहीं, कुछ लोग तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं कि वे कहां हैं? इस धरने में वे क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं?

सोनम वांगचुक से मेरा प्रश्न यह है कि क्या अनशन से पहले इस सत्ता का चरित्र आप नहीं जानते थे? क्या आपको यह नहीं पता था कि वह आपके साथ क्या बर्ताव करेगी? क्या आपने शुरुआत में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को अपने मंचों से दूर रहने को नहीं कहा था? क्या आपने इसे अराजनीतिक कहकर केवल छात्रों के लिए केंद्रित करने की वकालत नहीं की थी? क्या आपको नहीं पता था कि जिनके लिए आप लड़ने जा रहे हैं, पहले उन्हें संगठित करना जरूरी है? आप ये सब जानते थे, हम यह जानते हैं। हमने तो आपको एक बार भी गलत नहीं कहा। अब अचानक यह क्यों शुरू हो गया कि फलाने आए कि नहीं आए? अगर फलाने नहीं आएंगे, तो देश उन्हें माफ नहीं करेगा। आपकी लड़ाई सत्ता से है या विपक्ष से? कुछ लोगों को कड़वी लगेगी, मगर सच यही है कि आप अपने उसूलों से हट रहे हैं। जब आपने कहा था कि यह अराजनीतिक है, तो रहिए अराजनीतिक। जिसमें संवेदना होगी, वह खुद समर्थन दे देगा। रही बात समाज की, छात्रों की, तो आप इतिहास पलटकर देख लें। आक्रोश जन्मता है, तो उसे बनाए भी रखा जाता है। समाज को करवट दिलाने में बड़ी मेहनत लगती है। नील की खेती, चंपारण का आंदोलन पढ़ लीजिए। जब बापू को बुलाया ही इसलिए गया था कि वह उनकी लड़ाई लड़ें, तब भी लोग हट गए थे। राजेंद्र बाबू समेत कितने लोगों को कार्यकर्ता बनकर घर-घर जाकर लोगों को तैयार करना पड़ा था कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। कोई समाज यूं ही नहीं किसी मुद्दे से चिपक जाता है। बड़ी मेहनत लगती है समाज और मुद्दों के बीच चुंबकत्व पैदा करने में।

निस्संदेह, सोनम वांगचुक साहसी, समझदार और गंभीर व्यक्ति हैं। उनकी जीवटता संदेश देगी। उन्हें मेरा समर्थन है, मगर मैं यह नहीं मानूंगा कि समाज मरा हुआ है। न यह मानूंगा कि लोग इस सत्ता के चरित्र को नहीं जानते, और न यह कि छात्रों में कमी है कि वे जुड़ क्यों नहीं रहे। आप मजबूती से रहिए। सामने कोई भी हो, मजबूर होगा, आज नहीं तो कल।

हफीज किदवई, टिप्पणीकार

एआई के भविष्य में कहां बढ़ेंगे रोजगार

कामकाज के लिए एआई तकनीक को ज्यादा वास्तविक और उपयोगी बनाने पर तेजी से काम हो रहा है। इसीलिए भविष्य में सबसे ज्यादा मांग वाले कौशलों की सूची में एआई के कोर–टेक्निकल स्किल शीर्ष पर हैं। वर्तमान में भी एआई के तकनीकी कौशल को सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला कहा जा रहा है। किन एआई तकनीकी स्किल की ज्यादा है मांग, क्या हैं भविष्य के एआई कोर–स्किल, बता रहे हैं राजीव रंजन

कल की तैयारी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह नौकरियां खत्म करेगा या नए अवसर पैदा करेगा? हालांकि, दुनिया भर से रोजगार के आंकड़े एक अलग तस्वीर दिखाते हैं। लिंक्डइन के 2025 डाटा के अनुसार एआई इंजीनियर की भूमिका तेजी से उभर रही है। एक अन्य लेख के अनुसार वर्तमान में पांच लाख के लगभग एआई संबंधी पद वैश्विक स्तर पर खाली पड़े हैं और पिछले एक दशक में एआई प्रतिभाओं की मांग में 130 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

स्किल गैप कितना : वर्तमान में एआई क्षेत्र में करीब 50 प्रतिशत का स्किल गैप है और 2027 तक भारत में 12.5 लाख से अधिक एआई विशेषज्ञों की जरूरत हो सकती है।

भविष्य के एआई इकोसिस्टम

डॉ. चंद्रशेखर बुद्ध (सीईओ, अनुवादिनी एआई एवं चीफ को-ऑर्डिनेटिंग ऑफिसर- एआईसीटीई, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) कहते हैं, 'कुछ वर्ष पहले तक एआई मॉडल तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग की गहरी समझ जरूरी थी, लेकिन आज नैचुरल लैंग्वेज आधारित एआई प्लेटफॉर्म ने इस तकनीक को अधिक लोगों तक पहुंचा दिया है। अब काम करने का तरीका इंटेलिजेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन इंटेलिजेंस, ऑटोनॉमस एआई एजेंट्स और इंटीग्रेटेड एआई इकोसिस्टम्स की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भविष्य उन्हीं पेशेवरों का होगा, जो एआई टूल्स व तकनीकों के अनुसार खुद को लगातार तैयार करते रहेंगे।'

करियर रोडमैप बनाएं

पाइथन, सांख्यिकी और एसक्यूएल की समझ विकसित करें। 12वीं या स्नातक के बाद मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जेनरेटिव एआई सीखते हुए गिटहब व कागल पर प्रोजेक्ट तैयार करें। इंटर्नशिप के साथ एआई इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर जैसे करियर विकल्पों की ओर बढ़ सकते हैं।

विशेषज्ञ की राय

अभी एआई में रोजगार की सबसे अधिक मांग व्यावहारिक कौशल में है, जैसे जेनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड इंटीग्रेशन, डाटा पाइपलाइन्स और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के साथ काम करने की क्षमता। कंपनियां अब ऐसे पेशेवर चाहती हैं, जो एआई को वास्तविक समस्याओं के समाधान में इस्तेमाल कर सकें। कोर स्किल्स में भविष्य में एजेंटिक एआई, मल्टी–एजेंट सिस्टम्स, एआई गवर्नेंस, एथिकल एआई और डोमेन स्पेसिफिक एप्लीकेशन्स जैसी विशेषज्ञताओं की मांग बढ़ेगी।

–**बालेंदु शर्मा 'दाधीच'**
(एआई और भाषा तकनीक के विशेषज्ञ एवं सीईओ– एल्गो टेक्नोलॉजीज, दुबई)

नए कौशल

इस क्षेत्र में केवल प्रोग्रामिंग आना ही पर्याप्त नहीं है। उद्योग दो तरह की क्षमताओं वाले विशेषज्ञों की मांग कर रहा है-

1. कोर टेक्निकल स्किल्स ये कौशल एआई सिस्टम को विकसित और संचालित करने वाले विशेषज्ञों के लिए जरूरी हैं। इनमें पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा स्ट्रक्चर, सांख्यिकी, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, एमएलऑप्स और क्लाउड एआई जैसे तकनीकी कौशल शामिल हैं।

2. एप्लाइड स्किल्स : ये कौशल एआई के व्यावहारिक, नैतिक और व्यावसायिक उपयोग से जुड़े हैं। इनमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जेनरेटिव एआई, एआई ऑटोमेशन, बिजनेस एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैब्लो, एआई प्रोडक्ट मैनेजमेंट और एआई एथिक्स जैसे कौशल शामिल हैं। इनकी मदद से पेशेवर एआई आधारित समाधान तैयार और लागू करते हैं।

उच्च शिक्षा के प्रमुख विकल्प : एआई क्षेत्र में करियर के लिए बीटेक (एआई/मशीन लर्निंग या कंप्यूटर साइंस), बीएससी-डेटा साइंस, बीसीए, एमसीए, एमटेक और एमएससी जैसे पाठ्यक्रम विकल्प हैं। प्रवेश के लिए जेईई, सीयूईटी और विश्वविद्यालयों की अपनी प्रवेश प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं।

प्रमुख संस्थान : प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैं- (आईआईटी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु **iisc.ac.in**, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हैदराबाद/ बैंगलुरू **iiitb.ac.in**, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

उभरती करियर भूमिकाएं

एआई ऑर्केस्ट्रेटर, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर, रैग आर्किटेक्ट, मल्टीमॉडल डाटा आर्किटेक्ट, एआई ट्रस्ट एंड एथिक्स इंजीनियर, एक्सप्लेनेबल एआई स्पेशलिस्ट, एज एआई ऑप्टिमाइजेशन इंजीनियर और रोबोटिक्स एआई इंजीनियर जैसे रोल भविष्य में अहम होंगे। इनमें एआई मॉडल वर्कफ्लो, एलएलएम, डाटा सिस्टम, एआई सुरक्षा, नैतिकता और रोबोटिक्स से जुड़े काम शामिल हैं। इनके लिए एआई, एमएल, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, डीप लर्निंग और जेनरेटिव एआई की विशेषज्ञता के साथ पाइथन व एआई टूल्स की प्रैक्टिकल समझ जरूरी होगी।

भविष्य में रहेगी एआई के इन कोर-स्किल की मांग

- एजेंटिक एआई यानी अपने से निर्णय लेने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता
- मल्टीमॉडल एआई
- रोबोटिक्स एआई
- एआई सिक्योरिटी
- एक्सप्लेनेबल एआई
- एआई गवर्नेंस कोर टेक्निकल स्किल्स में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और एडवांस आरएजी (RAG) सबसे ऊपर होंगे। ये सामान्य प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आगे का कौशल है। इसके साथ ही, वीडियो, ऑडियो और सेंसर्स के जटिल डेटा को संभालने के लिए मल्टी–मॉडल डाटा आर्किटेक्चर और स्केलिंग के माहिर इंजीनियर्स की जबर्दस्त मांग होगी।

कड़े सरकारी नियमों और सुरक्षा के चलते एआई एथिक्स, गवर्नेंस और 'ट्रस्ट इंजीनियरिंग' एक अनिवार्य स्किल बन जाएगी, जो एआई के पक्षपात को रोकने, ऑडिट करने और साइबर हमलों से सिस्टम को सुरक्षित रखने का काम करेगी।

अपस्किलिंग कोर्स एवं मंच

- **एआई फॉर एवरीवन (डीपलर्निंग .एआई–कोर्सेरा):** गैर-तकनीकी लोगों में एआई की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए।
- **गूगल एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट:** डाटा और एआई की समझ के लिए।
- **मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन (कोर्सेरा):** तकनीकी शुरुआत के लिए।
- **प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर चैटजीपीटी (वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी):** एआई के व्यावहारिक उपयोग के लिए।
- **आईबीएम एआई इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट**

वेतन : फ्रेशर से अनुभवी विशेषज्ञों तक वेतन लगभग 6 लाख से 1 करोड़ रुपये सालाना तक।

जॉब/करियर

- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टेक्नीशियन ग्रेड–I एवं ग्रेड III के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।
कुल पद : 6557
अंतिम तिथि: 29 जुलाई 2026
आवेदन प्रक्रिया : आरआरबी की वेबसाइट है- **rrbapply.gov.in**

- आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड में जूनियर टेक्नीशियन, कंसल्टेंट समेत अन्य पद रिक्त हैं। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
कुल पद : 1213
अंतिम तिथि: 25 जुलाई 2026
आवेदन प्रक्रिया : देखें वेबसाइट: **avnl.co.in**

- इंडियन ओवरसीज बैंक में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। ये रिक्तियां विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के लिए निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होनी है।
कुल पद: 750
आवेदन तिथि: 10 अगस्त 2026 से शुरू होगा।
आवेदन प्रक्रिया : बैंक की वेबसाइट **iob.bank.in** के करियर सेक्शन में देखें।

- उत्तर प्रदेश में जनपद देवरिया के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों पर महिला उम्मीदवारों से आवेदन मांगे जा रहे हैं।
कुल पद : 408
अंतिम तिथि: 31 जुलाई 2026
आवेदन प्रक्रिया : इस वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर जाएं।

- रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। स्नातक या समकक्ष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
कुल पद: 119
अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। वेबसाइट है– **rrbapply.gov.in**

- जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में गैर–शिक्षण पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इसके तहत असिस्टेंट लाइब्रेरियन, क्यूरेटर आदि पद भरे जाएंगे।
कुल पद : 267
अंतिम तिथि: 27 जुलाई 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है– **jnu.ac.in**

- इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न सार्वजनिक बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जल्द ही समाप्त होने वाली है।
कुल पद : 6715
अंतिम तिथि: 21 जुलाई 2026
आवेदन प्रक्रिया : देखें वेबसाइट: **ibps.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

नर्सिंग में बढ़ती जाएंगी संभावनाएं

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

- **मैं बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूं। आगे नर्सिंग के क्षेत्र में ही अच्छे पद पर अपना करियर बनाना चाहती हूं। मेरा मार्गदर्शन करें।**
– शैली भट्ट

नर्सिंग आज सबसे सम्मानजनक, सुरक्षित और सर्वाधिक मांग वाले करियर विकल्पों में से एक है। भारत और विदेश में प्रशिक्षित नर्सों के लिए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। बी.एससी. नर्सिंग के दौरान विषयगत ज्ञान के साथ क्लिनिकल प्रशिक्षण, संचार कौशल, सहानुभूति, टीमवर्क और पेशेवर नैतिक सिद्धांतों पर विशेष ध्यान दें। यही गुण आपके सफल करियर की मजबूत नींव बनेंगे।

कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन और स्वास्थ्य सेवाओं में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों की अच्छी समझ विकसित करें। यदि विदेश में करियर बनाना चाहते हैं तो अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ रखें। साथ ही सेमिनार, वर्कशॉप, हेल्थ कैंप, इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लें तथा बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस), एडवांस्ड कार्डियो वैस्क्यूलर लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस), इमरजेंसी व क्रिटिकल केयर जैसी प्रमाणपत्र ट्रेनिंग लेकर अपने पेशेवर कौशल को मजबूत बनाएं। स्नातक के बाद आप अस्पतालों, स्पेशियलिटी क्लीनिक, सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों, सशस्त्र बलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों, शोध संस्थानों, कॉरपोरेट हेल्थकेयर और मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं। आगे एम.एससी. नर्सिंग, नर्स प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ या हेल्थकेयर मैनेजमेंट जैसे उच्च अध्ययन के विकल्प भी उपलब्ध हैं। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और खाड़ी देशों में भी लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को पूरा करने पर मौके मिल सकते हैं।

- **मैंने आट्र्स विषय से 12वीं की है। मैं एक सफल ब्लॉगर बनना चाहता हूं। इसके लिए केवल एसईओ सीखना जरूरी है या डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी करूं? कुछ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कोर्स एवं संस्थानों की भी जानकारी दें। - मो. अमानुल्लाह**

सफल ब्लॉगर बनने के लिए केवल अच्छा कंटेंट लिखना और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन (एसईओ) सीखना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रमोशन, मोनेटाइजेशन, वेबसाइट मैनेजमेंट, बेसिक ग्राफिक डिजाइन, एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की समझ भी जरूरी है।

शुरुआत डिजिटल मार्केटिंग से करें, क्योंकि यह ऑनलाइन ब्रांडिंग, ऑडियंस एंगेजमेंट, कंटेंट प्रमोशन, ईमेल मार्केटिंग, पेड एडवरटाइजिंग और एनालिटिक्स की व्यापक समझ देता है। जब आपकी बुनियादी समझ अच्छी हो जाए, तो एसईओ सीखें। इससे आपका ब्लॉग गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर दिखाई देता है और बिना विज्ञापन के ज्यादा लोग उसे पढ़ने आते हैं। साथ ही, आकर्षक कंटेंट और नियमित रूप से मौलिक व गुणवत्तापूर्ण लेख प्रकाशित करना भी सफलता के लिए जरूरी है। ऑनलाइन लर्निंग के लिए गूगल डिजिटल गैराज, गूगल स्किलशॉप, हबस्पॉट एकेडमी, कोर्सेरा, यूडेमी और लिंक्डइन लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म उपयोगी हैं। यहां डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और एआई आधारित मार्केटिंग टूल्स से जुड़े शुरुआती से लेकर एडवांस स्तर तक के कोर्स उपलब्ध हैं।

क्लासरूम लर्निंग के लिए डिजिटल विद्या, दिल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग (डीएसआईएम), एनआईआईटी और टेकस्टैक एकेडमी (दिल्ली-एनसीआर) जैसे संस्थान डिजिटल मार्केटिंग के व्यापक कोर्स उपलब्ध कराते हैं। इनमें एसईओ, ब्लॉगिंग, वर्डप्रेस, गूगल ऐड्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और वेब एनालिटिक्स जैसे विषय शामिल होते हैं। ट्रेनिंग के साथ वर्डप्रेस या ब्लॉगर जैसे मुफ्त ऑनलाइन मंच पर अपना ब्लॉग शुरू करें, अच्छी सामग्री प्रकाशित करें, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं और नए कौशल सीखते रहें।

(sanjibacharya.com)

हिन्दुस्तान क्विज-14

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. हिन्दुस्तान (अविभाजित) की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के पहले कप्तान कौन थे?
2. हिन्दुस्तान के किस उद्योगपति की मां मोहम्मद अली जिन्ना की इकलौती बेटी थीं?
3. हिन्दुस्तान की कौन सी बिस्किट दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली बिस्किट है?
4. हिन्दुस्तान के किस मशहूर फिल्म अभिनेता को 'जम्पिंग जैक' के नाम से भी पुकारा जाता था?
5. हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
6. हिन्दुस्तान का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस प्रसिद्ध हिन्दुस्तानी के सम्मान में मनाया जाता है?
7. हिन्दुस्तान के किस राज्य में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन होता है?
8. हिन्दुस्तान की पहली रासायनिक उर्वरक की फैक्ट्री कहां स्थापित की गई थी?
9. हिन्दुस्तान के पहले एफ1 (F1) ड्राइवर कौन थे?
10. हिन्दुस्तान की कौन–सी झील है, जो उल्का पिंड के टकराने से बनी है?

उत्तर : 1. गोष्ठ पाल 2. नुस्ली वाडिया 3. पार्ले जी 4. जितेंद्र 5. गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद झील) 6. पी.सी. महालनोबिस 7. तेलंगाना 8. सिंदरी (तब बिहार अब झारखंड में) 9. नारायण कार्तिकेयन 10. लोनार झील (महाराष्ट्र)

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : बातचीत में संतुलित रहें। घर में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। परिवार के साथ यात्रा पर भी जा सकते हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखें।

वृष : परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी में कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। वाहन सुख में वृद्धि भी हो सकती है।

मिथुन : संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, परंतु कार्यक्षेत्र में परिवर्तन के साथ किसी दूसरे स्थान पर भी जा सकते हैं।

कर्क : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी। सेहत का ध्यान रखें।

सिंह : मन अशांत रहेगा। संतान एवं जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं।

कन्या : कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। वाहन के रख-रखाव और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : नौकरी में परिवर्तन के साथ परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। पिता की सेहत का ध्यान रखें। कारोबार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सचेत रहें। आय में कमी आ सकती है।

धनु : आत्मसंयत रहें। क्रोध के अतिरेक से बचें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्च बढ़ेंगे। कारोबार से आय में वृद्धि होगी।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। वाहन के रख-रखाव और वस्त्रों पर खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ : कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा भी लाभप्रद रहेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें।

मीन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। परिश्रम अधिक रहेगा। लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

16 जुलाई, गुरुवार, **शक संवत्**: 25, आषाढ़ (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग**: 01, श्रावण मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम**: 01, सफर, 1448, **विक्रमी संवत्**: आषाढ़ शुक्ल द्वितीया प्रातः 08.54 मिनट तक पश्चात तृतीया तिथि, आश्लेषा नक्षत्र सायं 07.53 मिनट तक पश्चात मघा नक्षत्र, सिद्धि योग रात्रि 01.23 मिनट तक, चंद्रमा कर्क राशि में सायं 07.53 मिनट तक।

सूर्य दक्षिणायन। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। रथयात्रा उत्सव (श्री जगन्नाथपुरी)। श्रावण संक्रान्ति। वर्षा ऋतु। सफर (मु.) मास प्रारंभ।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

अगर फोटोग्राफी स्टूडियो बनाएं, तो सेहत के लिए ध्यान रखें:

- फोटो शूट का कमरा हल्के शेड में रखें, बहुत डार्क रंग न लगाएं। आपका शूट करने की दिशा कमरे के दक्षिण में करें, ताकि आपका मुख उत्तर की ओर रहे। कमरे के बीच में कोई बीम न आए, यदि हो तो उसे फाल्स सीलिंग से कवर करें। थोड़ा सुगंध का प्रयोग करें।
- स्टूडियो की एंट्रेंस पर सीढ़ियां के नीचे से निकल कर अंदर का प्रवेश न रखें। अगर ऐसा हो, तो यहां पर एक प्लाई का टुकड़ा ऐसा लगाएं, जो कि सीढ़ियों और गेट के बीच में हो।

वर्ग पहेली : 8391

1	■	2		3			4	
	■		■		■	■		■
5				■	6			7
	■		■	8		■	■	
9		■	10	■		■	11	
	■	■	12		■	13	■	
14	15			■	16			
■		■	■	17	■		■	
18							■	

बाएं से दाएं
2. ढुंढवाना; खोज करवाना (3,4)
5. कतवार; कूड़ा (4)
6. इन दिनों; एक-दो दिन में; वर्तमान दिनों में (4)
8. ढांचा; नक्शा; मानचित्र; रेखाचित्र; रूपरेखा (2)
9. आर्तव; ऋतु; कुसुम; धूल; पराग; चांदी (2)
11. खटिया; चारपाई; माचा (2)
12. औषधि; इलाज; उपचार; चिकित्सा (2)
14. ठूंस-ठूंस कर भरा; मुंह तक; लबालब (2,2)
16. कामकाज; धंधा; व्यवसाय (4)
18. अत्यधिक धन प्राप्त होना; बहुत धन लाभ होना; समृद्धि होना (3,4)

ऊपर से नीचे
1. भार से दबाए रखना; कठोर नियंत्रण में रखना; विवश करना (4,3)
2. तड़ करके टूटना; तड़पना; झुंझलाना; बिगड़ना (4)
3. प्राणरहित देह; मृत शरीर; लाश (2)
4. ढोने वाला; ले जाने वाला; वाहन करने वाला (3)
6. आकृति; रूप; कद; डील डौल; बनावट (3)
7. भाग्य का जोर मारना; भाग्य चमकना; माथा चमकना (3,4)
10. बाजा बजाने वाला; वादन करने वाला; संगीतज्ञ (3)
13. आवेश में आना; क्रुद्ध होना; क्रोध से चेहरा लाल होना; रुष्ट होना; चमकना (4)
15. आवरण; छाल; जिरह बख्तर (3)
17. अतिकाल; विलंब; वक्त; समय (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8390

1 ब	■	2 वि	ज्ञा	3 प	न	■	4 आ	■
र	■	का	■	स	■	5 वि	शा	ल
6 सा	ह	स	क	र	ना	■	ज	■
ना	■	क	■	ना	■	7 व	न	ज
■	8 म	र	ना	■	9 म	ह	क	■
10 सु	हा	ना	■	11 अ	■	म	■	12 दा
■	भि	■	13 अ	न	र्थ	क	र	ना
14 सं	यो	ग	■	म	■	र	■	पा
■	ग	■	15 जा	ना	मा	ना	■	नी

सुडोकू : 8345

*मध्यम

		5		2				
1					4			2
2			8		7	9		
4	5					8		6
3								9
7		2					5	4
		7	4		6			5
6			3					1
				8		3		

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8344

9	1	6	8	2	7	3	5	4
2	7	5	3	6	4	1	8	9
8	3	4	5	9	1	2	7	6
1	6	2	4	8	5	7	9	3
3	4	8	2	7	9	6	1	5
7	5	9	6	1	3	8	4	2
5	9	1	7	3	2	4	6	8
4	8	3	1	5	6	9	2	7
6	2	7	9	4	8	5	3	1

कल्पमेधा

कोई भी सुधार तभी हुआ है, जब साहसी व्यक्तियों ने समाज में प्रचलित अमानवीय प्रथाएं और रीति-रिवाज स्वयं तोड़ डाले हों।
– महात्मा गांधी

पारदर्शिता का पैमाना

करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास पर बने मंदिरों में वित्तीय अनियमितताओं की परतें अब सिलसिलेवार खुलने लगी हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर और बद्रीनाथ धाम के बाद जम्मू के माता वैष्णो देवी मंदिर में चांदी के चढ़ावे में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के आरोप लगे हैं। इस मामले में पुलिस की जांच प्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि अब स्थानीय अदालत ने पुलिस को शिकायत के संबंध में पूरा ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि मंदिर प्रबंधन के जिन लोगों पर वित्त की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और इसकी संपत्तियों की रक्षा करने का दायित्व होता है, या तो उनके लिए इन जिम्मेदारियों का कोई महत्त्व नहीं होता या फिर वे खुद ही कठघरे में खड़े दिखाई देते हैं! जाहिर है कि व्यापक साठगांठ के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता है।

माता वैष्णो देवी मंदिर में पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के चांदी के चढ़ावे में हेराफेरी का आरोप है। इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट पर ही सवाल उठने के बाद मामला अदालत पहुंच गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि पुलिस की रिपोर्ट में इस बात का कोई जिक्र नहीं है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई या नहीं, और न ही श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए करीब बीस टन चांदी के संबंध में लगे आरोपों की कोई सार्थक या विस्तृत जांच की गई। दरअसल, हाल ही में मंदिर प्रबंधन की ओर से यह दावा किया गया था कि चढ़ावे के रूप में लगभग 550 करोड़ रुपए की चांदी प्राप्त हुई थी, जिसमें से केवल बीस से तीस करोड़ रुपए की चांदी ही असली थी, जबकि शेष चांदी नकली या मिलावटी थी। इस दावे पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि चढ़ावे की चांदी में 'कैडमियम' मिले होने की बात सामने आई है। चूंकि कैडमियम एक विषैली धातु है और इसका व्यापार एवं उपयोग नियमानुसार ही किया जा सकता है तथा इस पर सरकार की कई एजंसियों की नजर रहती है।

इस मामले में आरोपों को इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि प्रथमदृष्टया यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैडमियम युक्त नकली चांदी खरीद सकते हैं! अगर मंदिर प्रबंधन का यह दावा सच पाया जाता है, तो इसका सीधा मतलब होगा कि देश भर के अनगिनत दुकानदार इस जहरीली धातु वाली मिलावटी चांदी को खरीदने एवं उसे आम लोगों को बेचकर अच्छा-खासा मुनाफा कमाने के गोरखधंधे में लिप्त हैं और यह अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है। पुलिस का तर्क है कि इस मामले में शिकायत प्राप्त होने के बाद उसे मंजूरी के लिए पुलिस महानिरीक्षक और अपराध शाखा को भेजा गया था। बाद में इसे किसी अन्य पुलिस प्राधिकरण को स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब अपराध शाखा खुद एक अधिसूचित थाना के रूप में काम कर सकती है, तो फिर शिकायत को किसी अन्य प्राधिकरण को स्थानांतरित करने की जरूरत क्यों महसूस की गई? बहरहाल, मंदिरों में अनियमितता का जैसा स्वरूप सामने आ रहा है, उसके मद्देनजर अब यह जरूरी हो गया है कि देश भर के मंदिरों में चढ़ावे और वित्तीय खातों की निगरानी के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे संपूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

अपराध का जाल

यह विचित्र बात है कि जेल में बंद होने पर भी कुख्यात कैदी अपने गिरोह के जरिए आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं और कारागार प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग पाती है! मामला चाहे नशीले पदार्थों के काले कारोबार का हो, रंगदारी वसूलने एवं लक्षित हत्या का हो या फिर अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त का, ऐसी तमाम वारदात की साजिश सलाखों के पीछे रहते हुए रचे जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस ने हथियारों की तस्करी के एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसे दिल्ली की तिहाड़ जेल से संचालित किया जा रहा था। गिरोह के तीन तस्करों की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ है। इस गिरोह का जाल इतना बड़ा था कि वे दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में हथियारों की खेप पहुंचाते थे। सवाल है कि जेल में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच कोई कैदी किस तरह गिरोह को चलाता है और उसे दिशा-निर्देश देता है।

गौरतलब है कि जेल में बंद किसी कैदी की ओर से अपने गिरोह के जरिए रंगदारी, फिरौती और हत्या को अंजाम देने जैसे मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके अभी तक ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया जा सका, जिससे ऐसे कैदियों की गतिविधियों पर स्थायी रूप से अंकुश लगाया जा सके। पिछले दिनों अमेरिका के न्याय विभाग ने अपने आरोपपत्र में गुजरात की जेल में बंद कुख्यात अपराधी लारेंस बिश्नोई पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जाहिर है कि जेल कर्मियों की लापरवाही या फिर मिलीभगत के बिना यह सब संभव नहीं हो सकता। ऐसे में यह सवाल महत्त्वपूर्ण है कि क्या एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत नहीं है, जिससे कैदियों को किसी भी दशा में संचार की सुविधाएं हासिल न हों। तिहाड़ जेल जैसे अति सुरक्षित और आधुनिक कारागार में भी अगर कोई कैदी कई राज्यों में अवैध हथियारों की तस्करी में संलिप्त हो, तो समझा जा सकता है कि हमारे सुरक्षा तंत्र में किस तरह की खामियां हैं। जब तक जेलों में सुरक्षा और सतर्कता के मानकों पर कड़ाई से अमल नहीं होगा, तब तक इस तरह की आपराधिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश नहीं लग पाएगा।

तकनीक में आत्मनिर्भरता की राह

सुपर कंप्यूटर अब तकनीकी संप्रभुता और सामरिक शक्ति का सूचक बन गया है। चीन ने इस क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत को भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाने होंगे।

अभिषेक कुमार सिंह

सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक उपकरण नहीं हैं, बल्कि किसी भी देश की तकनीकी संप्रभुता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और सामरिक शक्ति के महत्त्वपूर्ण सूचक हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की प्रतिष्ठित सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करना केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व का प्रतीक भी है। विडंबना यह है कि जिस समय हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन कुछ दशक पहले के सुपर कंप्यूटरों से भी अधिक सक्षम हो चुका है, उसी दौर में आधुनिक सुपर कंप्यूटर की उपलब्धियां आम जन की चर्चा से लगभग गायब हैं। हाल ही में जब चीन के सुपर कंप्यूटर 'लाइनशाइन' ने अमेरिका के 'एल कैपिटन' को पीछे छोड़ते हुए इस सूची में पहला स्थान हासिल किया, तब भी भारत में इस महत्त्वपूर्ण घटना पर अपेक्षित चर्चा नहीं हुई। यह उपलब्धि इसलिए भी उल्लेखनीय है, क्योंकि वर्ष 2017 के बाद पहली बार चीन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनाने का तगमा मिला है।

इस लिहाज से भारत के लिए यह आत्ममंथन का समय है। नवीनतम शीर्ष-500 की सूची में भारत का सुपर कंप्यूटर ऐरावत-पीएसएआइ 188वें स्थान पर है। ऐसे में सवाल केवल क्रम स्थान का नहीं, बल्कि इस बात का है कि भविष्य की एआइ-आधारित अर्थव्यवस्था और वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा में भारत अपनी क्षमता को किस गति से विकसित कर पाएगा। सुपर कंप्यूटर की चर्चा आगे बढ़ाने से पहले शीर्ष सूची पर नजर डालने से पता चलता है कि इसमें शुरुआती दस में से चार अमेरिका के तथा जर्मनी, जापान, स्विटजरलैंड, फिनलैंड और इटली के एक-एक सुपर कंप्यूटर शामिल हैं। इनमें अब पहले नंबर पर चीन का 'लाइनशाइन' है। इन उपलब्धियों के बीच भारत की 'सुपर कंप्यूटिंग' की तस्वीर थोड़ी निराश करती है। शीर्ष-500 की सूची में ऐरावत-पीएसएआइ 188वें, अर्क सुपर कंप्यूटर 196वें, अरुणिका 251वें, प्रत्यूष 338वें और अर्क एआइ-एमएल 469वें स्थान पर हैं। हालांकि अब उम्मीद वर्ष 2024 से जारी की गई नई श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों यानी 'परम-रुद्र' से जगी है, जो देश के अलग-अलग विज्ञान केंद्रों में तैनात किए गए हैं। मगर यह सच है कि 'सुपर कंप्यूटिंग' के करिश्मे की अब कोई ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा है और न ही कहीं इसकी ज्यादा फिक्र दिखाई दे रही है।

विज्ञान जगत से बाहर 'सुपर कंप्यूटिंग' की हलचलों पर कम ध्यान दिए जाने के संभवतः दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि आज की दुनिया में इतने ज्यादा तकनीकी करिश्मे हो रहे हैं कि कोई बड़ा तहलका होने तक किसी बड़े बदलाव को भी सामान्य माना जाता है। दूसरा कारण यह है कि अब पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर और कृत्रिम बुद्धिमता जैसे क्षेत्रों में तेजी से काम होने के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में सुपर कंप्यूटरों से संबंधित नए घटनाक्रम की अपेक्षित चर्चा नहीं हो रही है। मगर सुपर कंप्यूटरों की भूमिका को देखते हुए कहना होगा कि किसी भी तकनीकी उन्नति का आज भी ये अहम आधार हैं। इसलिए चीनी सुपर कंप्यूटर की खबर यह जानने का अवसर पैदा करती है कि आखिर इस समय 'सुपर कंप्यूटिंग' में भारत कहां पर है। हमारे देश में

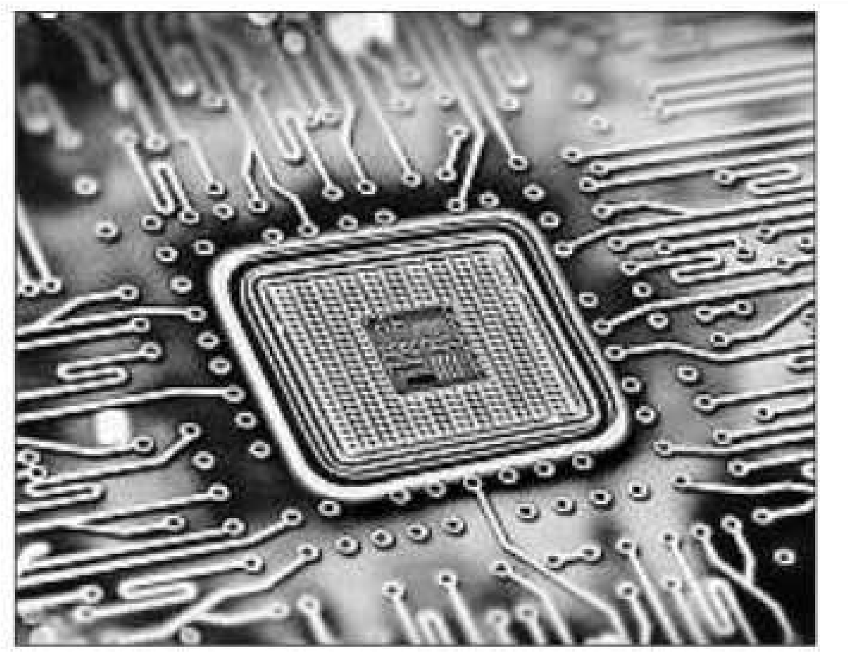

सुपर कंप्यूटर की कोई चर्चा अक्सर इस संदर्भ के साथ शुरू होती है कि एक जमाने में अमेरिका ने हमें मौसम की भविष्यवाणी करने के उद्देश्य से इस्तेमाल में लाए जाने वाले सुपर कंप्यूटर को देने से इनकार कर दिया था। नब्बे के दशक (1987) में भारत पर लगाई गई इस पाबंदी का नतीजा यह निकला कि

> **तकनीक के क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखती है कि किसी देश में इससे जुड़ी परियोजनाओं और शोधकार्यों की शुरुआत कब से की गई है। भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर-'परम 8000' बनाने की तरफ तब कदम बढ़ाए थे, जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। इस दिशा में दूसरी बड़ी पहल वर्ष 2015 में हुई, जब राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0 के अंतर्गत हर किस्म की सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यमों के मंच पर लाने की परियोजना लागू की गई। इसका उद्देश्य आम जनता को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों की सेवाएं घर बैठे उपलब्ध करना है। 'सुपर कंप्यूटिंग' में भारत के कौशल में प्रगति तो हो रही है, लेकिन इसकी गति और बढ़ाने की जरूरत है।**

सरकार के निर्देश पर सेंटर फार डेवलपमेंट आफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक), पुणे के वैज्ञानिकों ने वर्ष 1991 में 'परम 8000' नामक पहला सुपर कंप्यूटर बना दिया। उस समय भारत विश्व का तीसरा और एशिया का दूसरा ऐसा देश था, जिसने सुपर कंप्यूटर बनाने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद 'सुपर कंप्यूटिंग' के क्षेत्र में भारत चरणबद्ध रूप से बढ़ा, जिसकी एक उपलब्धि 'परम रुद्र' नामक तीन नए सुपर कंप्यूटरों का विकास है। इस श्रेणी के तीन सुपर कंप्यूटरों में से पहला सुपर कंप्यूटर पुणे स्थित मीटर रेडियो टेलीस्कोप (जीएमआरसी) में लगाया गया है। वहां यह सुपर कंप्यूटर खगोलीय संकेतों को समझने और विशेष रूप से 'फास्ट रेडियो बर्स्ट' (रेडियो संकेतों) को पकड़ने के लिए आंकड़ों को तेजी से जुटाने में अपनी भूमिका निभाएगा।

दूसरे 'परम रुद्र' की स्थापना दिल्ली स्थित इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलेटरेटर सेंटर (आइयूएसी) में की गई। यहां इसकी भूमिका पदार्थ विज्ञान और परमाणु भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान की गति में तेजी लाने में योगदान देना है। कोलकाता के एसएन बोस सेंटर में लगाए गए तीसरे 'परम रुद्र' सुपर कंप्यूटर की मदद से भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और पृथ्वी की संचालन संबंधी गतिविधियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इन तीनों में से दिल्ली स्थित आइयूएसी में स्थापित सुपर कंप्यूटर की क्षमता सबसे ज्यादा है। अब सुपर कंप्यूटरों की जो शीर्ष सूची हर साल तैयार होती है, उसमें प्रायः अमेरिका और चीन के सुपर कंप्यूटर अव्वल आते हैं। जबकि खुद को 'कंप्यूटिंग' का पुरोधा कहने वाला भारत इस मामले में काफी पिछड़ा हुआ है।

सवाल है कि क्या हमने हार मान ली है और 'सुपर कंप्यूटिंग' के मैदान को दूसरों के लिए खाली छोड़ दिया है। यदि नहीं, तो आखिर इस क्षेत्र में पिछड़ने का कारण क्या है? असल में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में यह बात काफी मायने रखती है कि किसी देश में इससे जुड़ी परियोजनाओं और शोधकार्यों की शुरुआत कब से की गई है। भारत ने पहला सुपर कंप्यूटर-'परम 8000' बनाने की तरफ तब कदम बढ़ाए थे, जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से इनकार कर दिया था। इस दिशा में दूसरी बड़ी पहल वर्ष 2015 में हुई, जब राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान 2.0 (एनईजीपी) के अंतर्गत हर किस्म की सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यमों के मंच पर ले आने की योजना लागू की गई। इसका उद्देश्य आम जनता को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा समेत कई अन्य क्षेत्रों की सेवाएं घर बैठे उपलब्ध करना है।

इस महाभियान की सफलता चूंकि 'कंप्यूटिंग' के अत्याधुनिक इंतजामों से जुड़ी है, लिहाजा सरकार ने 4500 करोड़ रुपए की लागत से देश में 73 सुपर कंप्यूटर बनाने का फैसला भी किया था। कह सकते हैं कि 'परम रुद्र' नामक तीन नए सुपर कंप्यूटरों की स्थापना इसी सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इससे 'सुपर कंप्यूटिंग' में भारत की हैसियत में सुधार तो होगा, लेकिन यह गति अभी बहुत धीमी है। चिंता इस बात की है कि कृत्रिम बुद्धिमता जैसे नए क्षेत्रों की भावी जरूरतों के लिए हमें सुपर कंप्यूटरों के मामले में एक बार फिर पश्चिमी मुल्कों का मोहताज न बनना पड़े। खुली बाजार व्यवस्था में हम अपनी जरूरत के मुताबिक अधिक क्षमता वाला कोई सुपर कंप्यूटर कहीं से भी हासिल कर सकते हैं, पर 'सुपर कंप्यूटिंग' के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक अर्थ यह है कि हमारे देश में प्रगति की तस्वीर बदलने और रुख को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता है। इसलिए इस मोर्चे पर उसी तरह ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आजकल सेमीकंडक्टर और कृत्रिम मेधा पर दिया जा रहा है।

सूत्रधार की सीमा

मुनीष भाटिया

दुनिया मेरे आगे

मनुष्य के जीवन में सफलता जितनी आवश्यक है, उतना ही जरूरी है उस सफलता के साथ विनम्र बने रहना। इतिहास हमें यह सिखाता है कि प्रतिभा, परिश्रम और साहस मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उनके साथ विनम्रता न हो, तो वही ऊंचाइयां पतन का कारण भी बन जाती हैं। संसार में अधिकांश संघर्ष, विवाद और अहंकार का मूल कारण यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को परिस्थितियों का नियंत्रक, घटनाओं का निर्माता और दूसरों के जीवन का सूत्रधार समझने लगता है। जबकि इस विराट सृष्टि का संचालन किसी एक मनुष्य की इच्छा से नहीं, बल्कि कर्म, समय और प्रकृति की व्यवस्था से होता है।

इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण मिलते हैं, जहां अपार शक्ति रखने वाले शासकों को भी समय के सामने झुकना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी असाधारण सैन्य प्रतिभा के बल पर यूरोप के बड़े भाग पर अधिकार स्थापित कर लिया था। उसके निर्णय देशों की सीमाएं बदल देते थे और उसकी सेना के कदमों से साम्राज्य कांप उठते थे। धीरे-धीरे उसे लगने लगा कि इतिहास उसी की इच्छा से लिखा जाएगा। मगर इतिहास कभी किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। कहा जाता है कि एक दिन एक वृद्ध सैनिक ने नेपोलियन से पूछा कि 'महाराज, क्या आपने पूरी दुनिया जीत ली?' नेपोलियन ने गर्व से उत्तर दिया, 'लगभग।' सैनिक ने फिर पूछा, 'तो क्या समय भी आपके आदेश से चलता है? क्या मृत्यु आपकी अनुमति लेकर आती है? क्या कल का सूरज आपके संकेत पर उगेगा?' इस प्रश्न का उत्तर नेपोलियन के पास नहीं था। उसने स्वीकार किया कि यह किसी मनुष्य के वश में नहीं। सैनिक ने केवल इतना कहा, 'जो समय को नहीं जीत सकता, वह संसार का सूत्रधार कैसे हो सकता है?' कुछ वर्षों बाद वाटरलू के युद्ध ने उसकी अजेय छवि को तोड़ दिया। विश्व-विजेता कहलाने वाला सम्राट पराजित हुआ, सत्ता छिन गई और उसे सेंट हेलेना के एक छोटे-से द्वीप पर निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। विजय का शोर समाप्त हो चुका था। अब उसके पास केवल आत्मचिंतन का समय था।

> **जो व्यक्ति सफलता के साथ विनम्र रहता है, वही लंबे समय तक लोगों के हृदय में स्थान बनाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, वह धीरे-धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। इतिहास बताता है कि साम्राज्य बाहरी शत्रुओं से कम और भीतर के अहंकार से अधिक टूटते हैं।**

यही समय मनुष्य को वह सिखा देता है, जो हजारों प्रशंसा नहीं सिखा पाती। यह कथा हर उस व्यक्ति की है जो किसी पद, अधिकार, धन या सफलता के कारण स्वयं को सबसे बड़ा मान बैठता है। आज किसी के पास ऊंचा पद है, किसी के पास अथाह धन है, किसी के पास राजनीतिक शक्ति है, किसी के पास प्रसिद्धि है। पर क्या इनमें से कोई भी समय को रोक सकता है? क्या कोई मृत्यु को टाल सकता है? क्या कोई अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रित कर सकता है? उत्तर है- नहीं। यही सत्य हमें विनम्र बनाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हमें बड़े सपने नहीं देखने चाहिए या सफलता प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बल्कि इसका अर्थ यह है कि सफलता को अपना स्वामी नहीं बनने देना चाहिए। जो व्यक्ति सफलता के साथ विनम्र रहता है, वही लंबे समय तक लोगों के हृदय में स्थान बनाता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, वह धीरे-धीरे लोगों का विश्वास खो देता है। इतिहास बताता है कि साम्राज्य बाहरी शत्रुओं से कम और भीतर के अहंकार से अधिक टूटते हैं।

आज के जीवन में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। कार्यालय में पद मिलने पर, व्यवसाय में लाभ होने पर, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर या परिवार में अधिकार मिलने पर अगर हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तो हम उसी भूल की ओर बढ़ रहे होते हैं, जिसने इतिहास के अनेक महान लोगों को गिराया। नेतृत्व का अर्थ आदेश देना नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व निभाना है। शक्ति का अर्थ दूसरों को झुकाना नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर चलना है। सफलता का अर्थ केवल ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि वहां पहुंचकर भी इंसान बने रहना है। मनुष्य प्रयास कर सकता है, पर अंतिम परिणाम अनेक परिस्थितियों और उस व्यापक व्यवस्था पर निर्भर करता है, जिसे हम ईश्वर, समय, प्रकृति या नियति कहते हैं। इसलिए सफलता मिलने पर कृतज्ञ रहना और असफलता मिलने पर धैर्य रखना ही जीवन की सच्ची बुद्धिमानी है।

सबसे बड़ी विजय किसी दूसरे व्यक्ति, किसी राज्य या किसी प्रतियोगिता पर नहीं होती। सबसे कठिन और सबसे मूल्यवान विजय अपने भीतर छिपे अहंकार, लालच और क्रोध पर होती है। जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे बाहरी विजय की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा व्यक्ति पद मिलने पर भी विनम्र रहता है और पद छिन जाने पर भी शांत रहता है। उसकी पहचान उसके चरित्र से होती है, न कि उसके सिंहासन से। हम सफलता का स्वागत करें, पर उसे अपने सिर पर न चढ़ने दें। अधिकार मिले तो उसे सेवा का माध्यम बनाएं, शक्ति मिले तो उसका उपयोग संरक्षण के लिए करें, क्योंकि समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। आज जो शिखर पर है, वह कल इतिहास का एक अध्याय भर हो सकता है। सूत्रधार बनने की नहीं, श्रेष्ठ पात्र बनने की इच्छा रखनी चाहिए। अपनी भूमिका ईमानदारी, परिश्रम, करुणा और विनम्रता के साथ निभाना चाहिए। सिंहासन क्षणिक हैं, चरित्र शाश्वत है। सत्ता बदलती रहती है, समय चलता रहता है, लेकिन विनम्रता से जीया गया जीवन कभी पराजित नहीं होता।

इसलिए जीवन का उद्देश्य संसार की प्रत्येक डोर अपने हाथ में लेने का नहीं, बल्कि अपने हिस्से की डोर को ईमानदारी, निष्ठा और विनम्रता से संभालने का होना चाहिए। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्ता, संपत्ति और प्रसिद्धि क्षणभंगुर हैं, किंतु विनम्रता, सद्कर्म और चरित्र अमर हैं। इसलिए दूसरों पर नहीं, स्वयं पर विजय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संसार को जीतने वाले अनेक हुए हैं, पर स्वयं को जीतने वाले ही वास्तव में महान कहलाए।

संसाधन का महत्त्व

किसी भी देश की उन्नति के लिए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटक संसाधन है। संसाधनों से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। समय के साथ-साथ संसाधनों के महत्त्व की प्रकृति भी बदली है। कभी कृषि उत्पाद सर्वाधिक अहम संसाधन थे। फिर ऊर्जा संसाधनों ने उनका स्थान ले लिया, लेकिन आधुनिक विश्व में जिस संसाधन पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, वह है-मानव संसाधन। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह कम प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिना जाता है, क्योंकि वहां मानव को संसाधन के रूप में बदलने पर जोर दिया गया। यानी नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल-विकास पर बल दिया गया। जिससे वहां के तकनीकी और आर्थिक क्षेत्र में खूब प्रगति हुई। इसका एक उदाहरण चीन भी है, जो तकनीकी क्षेत्र में नए कीर्तिमान रच रहा है और यह मानव संसाधन के बूते ही संभव हो पाया है। मानव संसाधन का विकास केवल युवाओं को कौशल प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है, ताकि इस संसाधन का इस्तेमाल हो सके।

– मोहम्मद अफजल, बुलंदशहर

शिक्षा की गुणवत्ता

'कसौटी पर शिक्षा' (संपादकीय, 13 जुलाई) गंभीर जमीनी हकीकत को उजागर करता है। वास्तव में शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विद्यार्थी के संपूर्ण बौद्धिक और व्यावहारिक विकास का आधार है। इसके लिए शिक्षकों और छात्रों का सही अनुपात होना जरूरी है। मगर सरकारी आंकड़े चिंताजनक स्थिति बयां करते हैं, जहां देश के एक लाख से अधिक विद्यालय आज भी बुनियादी संसाधन के रूप में केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। याद रखना चाहिए कि शिक्षकों के अभाव का सीधा असर समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों पर पड़ रहा है, जो निजी स्कूलों को भारी-भरकम फीस नहीं दे सकते। शिक्षकों की इस कमी और बुनियादी ढांचे में गिरावट के कारण ही सरकारी स्कूलों पर लोगों का भरोसा डगमगा रहा है।

– अमृतलाल मारू 'रवि', इंदौर

सुरक्षा का सवाल

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पिछले दिनों निर्माणाधीन माल में एक बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या कर देने की घटना ने समाज को झकझोर दिया है। यह घटना बताती है कि मनुष्य की मानसिकता कितनी विकृत होती जा रही है। यह बच्ची माल में काम करने वाले मजदूर की बेटी थी। परिवार निर्माणाधीन इमारत में गुजर-बसर कर रहा था। इस इमारत में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, जो घोर लापरवाही है। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध है, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली है। समाज की प्रगति का वास्तविक मापदंड यह नहीं है कि वह कितनी ऊंची इमारतें और सड़कें बना रहा है या कितनी आधुनिक सुविधाएं विकसित कर रहा है, बल्कि यह है कि वहां महिलाएं और बच्चे कितने सुरक्षित हैं। ऐसी घटनाएं न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बनती जा रही हैं, बल्कि ये मानवीय मूल्यों के क्षरण का भी संकेत देती हैं।

– वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

नियमों के विरुद्ध

ईरान और अमेरिका के बीच जंग ने भारत को भी मुश्किल में डाल दिया है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान ईरान ने दो वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया, जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और करीब दस घायल हो गए। इससे पहले अमेरिका ने भी वाणिज्यिक जहाजों पर हमला किया था, जिसमें तीन भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। किसी वाणिज्यिक जहाज पर हमला करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। समुद्री मार्ग पर जिस तरह से ये देश ठेकेदारी और शुल्क वसूलने पर उतर आए हैं, वह जबरन वसूली जैसा है। ऐसा लगता है कि दोनों देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों का कोई औचित्य नहीं हैं। भारत को अपने नागरिकों की मौत को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कड़ा विरोध जताना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो।

– हेमा हरि उपाध्याय,'अक्षत', उज्जैन

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

तथ्य

यूडीआइएसई की रिपोर्ट के अनुसार देश में रोज 13 स्कूल बंद हुए। साल 2025-26 के दौरान देशभर में कुल 4791 स्कूल बंद हो गए। स्कूल बंद मे मध्यप्रदेश सबसे आगे है। देश में बंद हुए कुल स्कूलों में से आधे से भी ज्यादा 2,426 स्कूल सिर्फ मध्यप्रदेश के हैं। साल 2024-25 के दौरान देश में 14 लाख 71 हजार 473 स्कूल थे। लेकिन 2025-26 में ये संख्या घटकर 14 लाख 66 हजार 682 रह गई। बंद होने वाले बाकी स्कूलों में से 1392 तेलंगाना, 568 पश्चिम बंगाल, 474 आंध्र प्रदेश, 369 तमिलनाडु, 281 कर्नाटक और 266 हिमाचल प्रदेश में थे।

उच्च शिक्षा में लड़कियों की संख्या बढ़ी

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने आल इंडिया सर्वे आन हायर एजुकेशन की साल 2022-23 और 2023-24 की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, देश में उच्च शिक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है, जिसके तहत हायर एजुकेशन में ग्रास एनरोलमेंट रेशियो पहली बार बढ़कर 30 पहुंच गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर एजुकेशन में लड़कियों का जीईआर 31.2 दर्ज किया गया, जो पुरुषों से अधिक है। इससे पता चलता है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ी है, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। एआइएसएचईमें संस्थान स्वयं पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करता है। साल 2022-23 में 56,180 और 2023-24 में 59,533 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ने सर्वे में भाग लिया।

भाषा पर है पकड़ तो जीत लो दुनिया

विशेषज्ञ की कलम से

आम धारणा है कि कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) के दौर में रोजगार के अवसर केवल कम्प्यूटर और तकनीकि के क्षेत्र में उच्च दक्षता प्राप्त लोगों के लिए ही हैं। आकर्षक वेतन वाली नौकरियां केवल साफ्टवेयर डिजाइनिंग, कोडिंग, ब्लाकचेन आदि के विशेषज्ञों के लिए ही होंगी। मानविकी और भाषा के छात्रों का इस क्षेत्र में कोई भविष्य नहीं है। हालांकि वास्तविकता इससे काफी दूर है। सच्चाई ये है कि एआइ के दौर में आज तकनीकि विशेषज्ञों की जितनी मांग है, उतनी ही भाषाई दक्षता वाले लोगों की भी है और भाषाई दक्षता भी केवल अंग्रेजी या हिंदी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं के जानकारों की भी खासी मांग है।

जी हां, आज दुनिया भर की कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। जो शुद्ध और आसान भाषा में लिख सकें, संदर्भ के अनुसार अर्थ स्पष्ट कर सकें और एआइ द्वारा तैयार सामग्री की गुणवत्ता का मूल्यांकन कर सकें। यही कारण है कि भाषा विशेषज्ञों के तौर पर हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के जानकार सामान्य स्नातकों के लिए भी खूब नए अवसर तैयार हो रहे हैं।

> आज दुनिया भर की कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं जिनकी भाषा पर अच्छी पकड़ हो। जो शुद्ध और आसान भाषा में लिख सकें।

एआइ ने मानव जीवन, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, संचार और तकनीक के अनेक क्षेत्रों में बड़े बदलाव किए हैं। इनमें चैटबाट एक महत्वपूर्ण एआइ उपकरण के रूप में विकसित हुआ है, जो मनुष्य और मशीन के बीच संवाद को सरल और प्रभावी बनाता हैं। चैटबाट ऐसे साफ्टवेयर होते हैं जो भाषा को सुनकर, देखकर और पढ़कर उपयोगकताओं के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। आज एआइ केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी और अन्य भारतीय भाषाओं को भी समझने और उनमें उत्तर देने की दिशा में विकसित हो रहा है। इनका उपयोग ग्राहक सेवा, आनलाइन खरीदारी, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सलाह, तकनीकी सहायता और अनेक अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है।

एआई के तेजी से बढ़ते उपयोग ने भाषा से जुड़े विशेषज्ञों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके लिए ऐसे विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है जो भाषा, व्याकरण, अर्थ, शैली और सांस्कृतिक संदर्भों को अच्छी तरह समझते हों। यही कारण है कि मानविकी और भाषा विषयों के विद्यार्थियों के लिए एआइ भाषा विशेषज्ञ संभावनाओं से भरपूर करियर बनकर सामने आया है।

एआई भाषा विशेषज्ञ वह व्यक्ति होता है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों को भाषा समझने और बेहतर उत्तर देने में मदद करता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि एआई द्वारा तैयार की गई सामग्री व्याकरण की दृष्टि से सही, तथ्यात्मक, सहज, स्पष्ट और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो।

इस भूमिका में काम करने वाले लोग एआइ माडल का परीक्षण करते हैं, उसके उत्तरों की समीक्षा करते हैं, भाषा संबंधी त्रुटियां सुधारते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले उदाहरण तैयार करते हैं, अनुवाद करते हैं तथा एआइ को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए भाषाई सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

एआइ केवल तकनीक का विषय नहीं है; वह भाषा, संस्कृति और मानवीय अभिव्यक्ति को भी सीखता है। इसलिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, पत्रकारिता, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान और अन्य मानविकी विषयों के विद्यार्थी इस क्षेत्र में अच्छी संभावनाएं रखते हैं।

– **अविनाश चंद्र**, लोक नीति के जानकार

प्रशिक्षण कहां से लें?

पारंपरिक डिग्री के साथ-साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण अधिक महत्वपूर्ण है। आज अनेक प्रतिष्ठित आनलाइन मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव एआई, प्राम्प्ट लेखन, प्राम्प्ट इंजीनियरिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी), डेटा एनोटेशन और तकनीकी लेखन जैसे विषयों पर पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं।

कोसेर्रा : एआइ, एनएलपी, पायथन, प्राम्प्ट इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग के कोर्स।

एडएक्स : विश्वविद्यालयों द्वारा एआइ और डेटा साइंस पाठ्यक्रम।

डीप लर्निंग एआइ : एलएलएण, जेनेरेटिव एआइ और प्राम्प्ट इंजीनियरिंग पर विशेष कोर्स।

हगिंग फेस लर्न : एनएलपी व लार्ज लैंग्वेज माडल्स का प्रशिक्षण।

गूगल क्लाउड स्किल्स बूस्ट : जेनेरेटिव एआइ, क्लाउड एआई प्रशिक्षण।

माइक्रोसाफ्ट लर्न : एआइ, एज्योर एआइ और कोपायलट से संबंधित नि:शुल्क प्रशिक्षण।

जानें-सीखें

वाट्सएप के क्लाउड पर चैट बैकअप कर सकेंगे स्टोर

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वाट्सएप पर स्टोरेज का पूरा मामला बदलने वाला है। वाट्सएप जल्द ही गूगल ड्राइव और आइक्लाउड के विकल्प के तौर पर अपना क्लाउड लाने वाला है, जिस पर आप अपनी चैट स्टोर कर पाएंगे। एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि वाट्सएप का इस क्लाउड स्टोरेज को एंड्रायड के साथ-साथ आइफोन यूजर्स भी यूज कर पाएंगे। अगर आसान भाषा में समझें तो आपको वाट्सएप पर अपनी चैट के बैकअप के लिए गूगल ड्राइव और आइक्लाउड के अलावा भी एक और विकल्प मिलेगा और वाट्सएप की खुद की क्लाउड स्टोरेज होगी।

अगर आइफोन के उदाहरण से समझें तो यूजर को सिर्फ 5 जीबी फ्री आइक्लाउड स्टोरेज मिलती है। इसमें फोटो, डाक्यूमेंट्स, ऐप डेटा और डिवाइस बैकअप आदि सबकुछ होता है। अब इसमें वाट्सएप के बैकअप को भी जोड़ दिया जाए तो यह स्पेस काफी कम रहता है। एक बार क्लाउड स्टोरेज फुल होने के बाद आपको या तो फाइल्स डिलीट करनी पड़ेगी या फिर ज्यादा स्टोरेज के लिए ऐप्पल को पैसा देना पड़ेगा। ऐप्पल के सबसे सस्ते प्लान में आपको 50 जीबी स्टोरेज के लिए लगभग 100 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। वाट्सऐप का क्लाउड अब इस दिक्कत से आपको बचा लेगा।

बताया जा रहा है कि वाट्सएप के प्लान में 2 जीबी स्टोरेज फ्री दी जाएगी। आप इसमें चैट का बैकअप स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको इससे ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो इसके लिए पेड प्लान लेना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, वाट्सएप हर महीने एक डालर (लगभग 95 रुपए) में 50 जीबी स्टोरेज आफर करेगी। अगर आपको इससे भी ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है तो कंपनी 1 टीबी तक का प्लान आफर करेगी। इसके लिए आपको हर महीने ज्यादा पैसा देना पड़ेगा.

वाट्सएप के क्लाउट पर स्टोर होने वाला चैट बैकअप भी एंड-टूं-एंड एनक्रिप्टेड होगा। यानी बैकअप से भी आपकी चैट को कोई थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर पाएगी। ऐप्पल के आइक्लाउड पर एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन मिलता है, लेकिन यह वैकल्पिक होता है। यानी यूजर को इसे इनेबल करना पड़ता है। वाट्सएप में ऐसा झंझट नहीं होगा। यह बाई डिफाल्ट आन रहेगा और इसमें एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन को बंद करने का आप्शन नहीं मिलेगा। इस बैकअप को पासकी और पासवर्ड, एनक्रिप्शन की से सिक्योर भी किया जा सकेगा।

रिपोर्ट्स में बताया गया है कि फिलहाल कंपनी इस पर काम कर रही है और इसकी पब्लिक टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। इसलिए इसे रोलआउट होने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।

युवा शक्ति डेस्क

जागरूकता

मुंबई के एक स्कूल में बुधवार को एक सेमिनार के दौरान बच्चियों को गुड टच और बैड टच के बारे में जगरूक करते महिला पुलिस अधिकारी और स्कूल की अध्यापिका।

कौशल सीखकर रोजगार क्षमता बढ़ा सकते हैं युवा

परामर्श

अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या रोजगार की तलाश में हैं, तो यूनिसेफ और युवाह का आनलाइन स्किल कोर्स आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इस कोर्स के जरिए युवा नई कौशल सीखकर अपनी रोजगार क्षमता बढ़ा सकते हैं और नौकरी पाने की संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं।

आज के प्रतिस्पर्धी दौर में अच्छी नौकरी पाने के लिए केवल शैक्षणिक योग्यता ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रभावी रिज्यूमे तैयार करना, आनलाइन जाब सर्च की समझ रखना और इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी आवश्यक है। कंपनियां ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं, जिनमें ये सभी गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूनिसेफ और युवाह के सहयोग से स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफार्म पर हाउ टू गेट ए जाब ऑनलाइन स्किल कोर्स शुरू किया गया है। जो युवा अपनी पहली नौकरी कर रहे हैं या रोजगार के बेहतर अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह कोर्स उपयोगी साबित हो सकता है।

इस कोर्स में प्रतिभागियों को एक प्रभावशाली और प्रोफेशनल रिज्यूमे तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से सिखाई जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान यह समझाया जाएगा कि अपनी शैक्षिक योग्यता, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल, कार्य अनुभव, परियोजनाओं, प्रमाणपत्रों तथा उपलब्धियों को किस प्रकार सुव्यवस्थित और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाए, ताकि रिज्यूमे नियोक्ताओं पर सकारात्मक एवं प्रभावशाली छाप छोड़ सके। इस कोर्स के माध्यम से प्रतिभागियों को जाब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाना, आनलाइन आवेदन करना तथा रोजगार के अवसरों की प्रभावी ढंग से खोज करना सिखाया जाएगा। इससे युवा डिजिटल प्लेटफार्म का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

कर्नाटक में पहला कृत्रिम बुद्धिमता विश्वविद्यालय खुलेगा

जरूरी जानकारी

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने छात्रों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमता (एआइ) विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। उन्होंने इसे कर्नाटक को जिम्मेदार और विश्वसनीय एआइ विकास के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में अहम कदम बताया।

मुख्यमंत्री ने एक समर्पित एआई हब बनाने की भी घोषणा की। यह केंद्र अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) के लिए इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में काम करेगा। इसके माध्यम से स्टार्टअप, निजी कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान और नवाचार के क्षेत्र से जुड़े लोग एक मंच पर आएंगे और एआइ आधारित तकनीकों तथा समाधानों के विकास को गति मिलेगी।

कृत्रिम बुद्धिमता आज के दौर की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति बनकर उभर रही है। मुख्यमंत्री ने इसकी तुलना भाप इंजन, बिजली, इंटरनेट और मोबाइल तकनीक जैसी ऐतिहासिक तकनीकी उपलब्धियों से की, जिन्होंने दुनिया को बदलकर रख दिया था। उन्होंने कहा, कर्नाटक की महत्वाकांक्षा दुनिया के अग्रणी जिम्मेदार एआइ केंद्रों में अपनी जगह बनाने की है। बेंगलुरु सिर्फ भारत की तकनीकी राजधानी नहीं है, बल्कि यह दुनिया के सबसे सक्रिय और ऊजार्वान नवाचार पारिस्थितिकी तंत्रों में भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत के कुल साफ्टवेयर निर्यात में कर्नाटक की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत है। वहीं, बेंगलूरु में 17 हजार से अधिक स्टार्टअप सक्रिय हैं और हजारों ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर दुनिया भर के बाजारों के लिए तकनीकी उत्पाद और सेवाएं विकसित कर रहे हैं।

> एआइ तकनीक शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने, डाक्टरों को बीमारियों की जल्द पहचान करने, किसानों को सटीक सलाह उपलब्ध कराएगी।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य कर्नाटक को एक एआइ-नेटिव राज्य के रूप में विकसित करना है, जहां प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का व्यापक इस्तेमाल हो। उनके अनुसार, एआइ तकनीक शिक्षकों को बेहतर तरीके से पढ़ाने, डाक्टरों को बीमारियों की जल्द पहचान करने, किसानों को सटीक सलाह उपलब्ध कराने और नागरिकों को तेज तथा प्रभावी सरकारी सेवाएं देने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को भी प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी।

उन्होंने गूगल की सराहना करते हुए कहा कि कंपनी ने बेंगलुरु को अपने प्रमुख वैश्विक इंजीनियरिंग, अनुसंधान और नवाचार केंद्रों में शामिल किया है। साथ ही उन्होंने गूगल से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सुशासन जैसे क्षेत्रों के लिए एआई आधारित समाधान विकसित करने, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग देने और छात्रों के लिए सीखने के अवसर बढ़ाने में कर्नाटक के साथ साझेदारी को और मजबूत करने का आग्रह किया।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने डेवलपर्स, उद्यमियों, शोधकताओं और छात्रों से नवाचार की संस्कृति को आगे बढ़ाने और निरंतर सीखते रहने की सोच को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक न केवल तकनीक के भविष्य को दिशा देगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि एआइ का विकास नवाचारी होने के साथ-साथ समावेशी, जिम्मेदार और भरोसेमंद भी बना रहे।

सूचनापट्ट

नीट यूजी

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने नीट यूजी 2026 परीक्षा शुल्क रिफंड के लिए बैंक खाते की जानकारी जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 रात 11:50 बजे तक अपने बैंक विवरण जमा कर सकते हैं। एनटीए के मुताबिक, पहले तय समय सीमा तक बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते की जानकारी जमा नहीं की थी। इसी को देखते हुए एजेंसी ने छात्रों को एक और मौका देने का फैसला किया है, ताकि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा शुल्क वापसी से वंचित न रह जाए। एनटीए ने बताया कि 14 जुलाई 2026 तक कुल 11,46,401 उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाते की जानकारी जमा कर दी थी। एजेंसी ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द बैंक जानकारी जमा करने की सलाह दी गई है। नीट यूजी 2026 परीक्षा का आयोजन पहले 3 मई 2026 को होना था। हालांकि, पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई और बाद में 21 जून 2026 को दोबारा आयोजित की गई। परीक्षा दोबारा आयोजित होने के बाद उम्मीदवारों को राहत देने और शुल्क वापसी सुनिश्चित करने के लिए एनटीए ने परीक्षा शुल्क रिफंड की प्रक्रिया शुरू की है।

अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2026

उत्तराखंड टीईटी

उत्तराखंड बोर्ड आफ स्कूल एजुकेशन (यूबीएसई) ने उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूटीईटी-प्रथत और यूटीईटी-द्वितीय) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य के सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 14 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे) है। जिन उम्मीदवारों ने स्नातक में कम से कम 50 फीसद अंक प्राप्त किए हैं और उनके पास एक वर्षीय बीएड की डिग्री है, वे यूटीईटी-प्रथम (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सामान्य और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए 600 रुपए तथा दोनों पेपरों के लिए 1000 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क 300 रुपए और दोनों पेपरों का शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है।

अंतिम तिथि : 3 अगस्त 2026

विधि पाठ्यक्रम

बार काउंसिल आफ इंडिया ने देशभर के विश्वविद्यालयों, विधि विभागों, ला कालेजों और कानूनी शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य सभी मौजूदा संस्थानों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने कहा है कि जो संस्थान अपने मौजूदा कानून पाठ्यक्रमों, सेक्शन और स्वीकृत प्रवेश क्षमता को जारी रखना चाहते हैं, उन्हें 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बीसीआई ने यह फैसला आगामी प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा को रोकने और कानून की पढ़ाई करने वाले छात्रों के हितों की रक्षा के लिए लिया है। बीसीआई के अनुसार, कई संस्थानों ने या तो अभी तक जरूरी आवेदन जमा नहीं किए हैं या फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के बावजूद उसे पूरा नहीं किया है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि केवल पोर्टल पर पंजीकरण करना, आवेदन संख्या प्राप्त कर लेना, कुछ दस्तावेज अपलोड करना या आंशिक शुल्क जमा करना आवेदन पूरा माना नहीं जाएगा।

अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2026

डीयू

दिल्ली यूनिवर्सिटी को देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में गिना जाता है। देशभर से लाखों छात्रों हर साल डीयू में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। सीयूईटी में अच्छा स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को डीयू के मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन जिन छात्रों का सीयूईटी स्कोर काफी कम या किन्हीं वजहों से सीयूईटी में बैठने वाले भी डीयू में पढ़ सकते हैं। एकेडमिक सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में छात्रों को कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, वे सीधे एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 12वीं के मार्क्स देखे जाते हैं। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन के मार्क्स देखे जाते हैं। एसओएल से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को रेगुलर कॉलेज आने की जरूरत नहीं होती। शनिवार या रविवार को डीयू के चुनिंदा कॉलेजों में क्लास लगती हैं। स्टूडेंट्स 1 महीने से लेकर 1 साल तक वाले कोर्स सकते हैं। इनमें अधिकतर दाखिले 'पहले आयो-पहले पाओ' के आधार पर भी होते हैं।

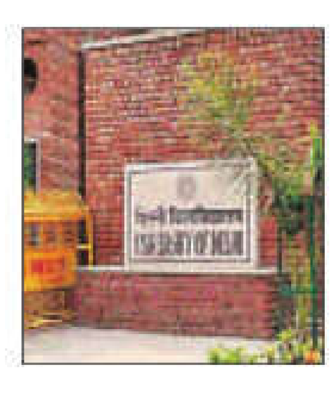

अंतिम तिथि : 24 जुलाई 2026

प्रेरणा

जब भी खुद को बहुमत के पक्ष में पाएं, तो समझिए रुककर विचार करने का समय है। –मार्क ट्वेन

संपादकीय

हमारा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी पर हो तो बेहतर

पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की नीति विगत अप्रैल में अमल में लाई गई थी यानी मूल लक्ष्य से पांच साल पहले। इससे क्रूड आयात घटा और 1.59 लाख करोड़ की विदेशी मुद्रा बची। इसका 1.18 लाख करोड़ किसानों को मदद में गया। लिहाजा सरकार अब 25-30% ब्लेंडिंग करने की सोच रही है। देखने में तो यह ठीक लगता है क्योंकि लाभ किसानों को मिल रहा है, लेकिन क्या सरकार ने सीईईडब्ल्यू की रिपोर्ट देखी है जिसके अनुसार 2032 से पेट्रोल की मांग घटने लगेगी, क्योंकि लोग तेजी से ईवी की ओर बढ़ रहे हैं? 2025-26 में ही ईवी गाड़ियां 8.5% हो चुकी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एक एथेनॉल प्लांट का जीवन 25-30 साल होता है, जबकि पेट्रोल की खपत वर्ष 2032 में 5700 करोड़ लीटर से घटते हुए वर्ष 2050 में मात्र 3700 करोड़ लीटर रह जाएगी। एक तरफ गैर-जीवाश्म ऊर्जा के रूप में ईवी पर रुझान और दूसरी ओर पेट्रोल की घटती मांग एथेनॉल उद्यमियों को हतोत्साहित कर रही है। इसके अलावा अगर एथेनॉल मिलाने पर और जोर दिया गया तो किसानों को धान की खेती से हटाकर दलहन और तिलहन की खेती की ओर उन्मुख करने के सरकारी प्रयास को पलीता लगेगा। क्यों न एथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% पर ही रोककर सोलर और विंड जैसी रिन्यूएबल-एनर्जी को और अधिक बढ़ाएं और इसके लिए जरूरी स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करें? रिन्यूएबल-एनर्जी सर्वश्रेष्ठ है, बशर्ते इसकी स्थापना-लागत और स्टोरेज की कीमत को तकनीकी इनोवेशन से घटाया जा सके, जैसा जापान और चीन ने किया है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

जो भी काम करें, गंभीरता, लगन व ईमानदारी से करें

बहानों को आगे-पीछे झूठ में बदलना ही पड़ता है, इसलिए बहाने बनाने की आदत छोड़ें। जो भी काम करें, गंभीरता, लगन और ईमानदारी से करें। बहाना एक तरह की बेईमानी है और यदि आदत में आ गया तो बहाना अपराध बन जाएगा। अगर आप बहुत काम नहीं करते हैं तो इसका मतलब आपको बहाने बनाने ही पड़ेंगे। इसका उल्टा भी है। आप कम काम करेंगे तो दूसरों से बहाने बनाएंगे और बहुत अधिक काम करेंगे तो खुद से बहाना बना रहे होंगे। यह हसल-कल्चर का वक्त है। बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगातार और अत्यधिक काम करना हसल-कल्चर कहलाता है। इसमें आप पांच चीजें दांव पर लगा रहे होते हैं- स्वास्थ्य, नींद, विश्राम, सामाजिक संबंध और पारिवारिक संबंध। 10-12 घंटे लोग लगातार काम करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि खूब मेहनत करने से ही परिणाम मिलता है। लेकिन यदि आप 10 घंटे काम करते हैं तो 8 घंटे तो परिणाम देने के लिए करिए, लेकिन 2 घंटे, उन 8 घंटों को ताकत देने के लिए करिए। फिर वह निजी रुचि का काम हो, योग हो, परिवार के साथ समय बिताना हो। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

हाइड्रेंजिया के फूल और लड़कियां

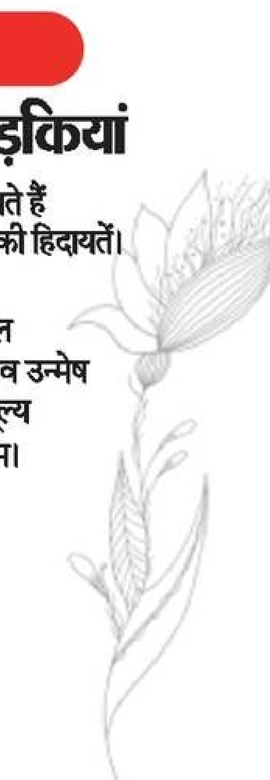

हाइड्रेंजिया के फूल बहुत पुराने फूलों में गिने जाते हैं
इतने पुराने कि जितनी लड़कियों को दी गई मां की हिदायतें।

वसंत आते ही खिल उठते हैं हाइड्रेंजिया के फूल
और पतझड़ तक बचाए रखते हैं अपनी आभा व उन्मेष
लड़कियां भी जब जानने लगती हैं स्मित का मूल्य
तो फिर मुस्कराती ही जाती हैं हर पहर हर मौसम।

सलीके से फूलने के लिए हाइड्रेंजिया के फूल
मांगते हैं इफरात में पानी
बारिशों के आते-आते ठीक वैसे ही
लड़कियों की याद से भी मां का मशविरा
धीरे-धीरे धुलने लग जाता है।

एक ही पौधे पर सफेद, नीला, गुलाबी, बैंगनी
वैसी बहुरंगी संगति आकर्षक चाहे लगे
लड़कियों का हरदिलअजीज
हो जाना मगर अखरता है
हाइड्रेंजिया में जो है यह सब कुदरती बहार
लड़कियों में तो कहलाएगा
सायास वर्जनाओं का अतिक्रमण...
–भूपेन्द्र बिष्ट, हल्द्वानी (उत्तराखंड)
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

लोग भूख से मरें तो कैसा विकास?

पंजाब के मनसा में एक महिला द्वारा गंभीर आर्थिक तंगी के चलते तीन बच्चों की हत्या कर खुद की जान देने की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह भारत के चौगुने विकास के सरकारी दावों पर धब्बा है। जब लोग भूख से मरें तो ऐसे दावे झूठे साबित होते हैं।
–एसके खोसला, चंडीगढ़

शिक्षकों को मिले प्रभावी प्रशिक्षण

शिक्षक प्रशिक्षण का अर्थ केवल नई स्किल सीखना ही नहीं है, बल्कि शिक्षकों को छात्रों की विविध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना भी है। जब शिक्षक अच्छी तरह से प्रशिक्षित होते हैं, तभी वे अपनी भूमिकाओं में अधिक आत्मविश्वासी और प्रभावी होते हैं। **–कुमार गौरव, मधुबनी, बिहार**

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

लक्समबर्ग में यात्रा का नहीं लगता पैसा

यूरोप में लक्समबर्ग पहला ऐसा देश है, जिसने अपने निवासियों और पर्यटकों को पूरे देश में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन सेवा दी है। वहां सिर्फ एसी फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट लगता है। इसके अलावा अन्य ट्रेन, ट्राम सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। 2020 में यह सुविधा शुरू की गई थी। **6 करोड़** से ज्यादा यात्री सालाना इस मुफ्त सेवा का लाभ उठाते हैं।

विशेष • जीवन में अनेक कष्ट सहे, पर सब दारुण दुःखों से उबारा है महाबाहु ने... मैं उनकी बेटी जो हूं

मेरे जीवन के उत्थान-पतन के नियंता हैं महाप्रभु

आस्था

द्रौपदी मुर्मु
भारत की राष्ट्रपति

बचपन से मुझे श्रीजगन्नाथ जी की अनेक प्रार्थनाएं और भजन याद हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ते समय मैं गीत गाया करती थी। जगन्नाथ जी का भजन गाकर मैं खुश होती थी। महाप्रभु को अपने निकट पाती थी। अब गीत नहीं गाती, किंतु सांझ-सबेरे महाप्रभु का स्मरण करके उनके भजन गुनगुना लेती हूं। मुझे लगता है कि महाप्रभु हर वक्त मेरे आस-पास ही रहते हैं। विपदा-आपदा में मेरी मदद करते हैं। भक्तकवि मधुसूदन राव का गीत आज भी मैं मन ही मन गाती हूं :

'मेरे पास दिन-रात रहते हैं महाप्रभु परमेश्वर,
यह बात याद कर हृदय में पूजूंगा उन्हें निरंतर।'

मैं कुछ समझने-बूझने की उम्र में पहुंचने तक जगन्नाथ जी को जानने लगी थी। हमारे घर में अकसर उनकी चर्चा होती थी। गांव के हर टोले में उनकी महिमा का बखान होता था। जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ती थी, भक्त सालबेग की 'आहे नीड़ो शोइड़ो' प्रार्थना गाई जाती थी। स्कूल के शिक्षक जगन्नाथ जी के बारे में तरह-तरह की बातें कहा करते थे। पुरी में बड़ा मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर और कहीं नहीं है! मंदिर में श्रीजगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र के साथ पूजे जाते हैं। जगन्नाथ जी का रंग काला है, उनकी आंखें गोल-गोल हैं। सुभद्रा जी का रंग पीला है, बलभद्र हैं चांदनी फूल की तरह सफेद। वह छवि एक बार देख लेने के बाद फिर भुलाए नहीं भूलती। सर यह भी कहते थे, जगन्नाथ हैं 'महाप्रभु', उनका प्रसाद 'महाप्रसाद' है, उनका मंदिर 'बड़ा मंदिर' है, उनका पथ 'विशाल पथ' ('बोड़ो दांडो') है और उनका समुद्र 'महोदधि' है।

मयूरभंज के उपरबेड़ा गांव से पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी की दूरी बहुत थी! भला देखने का अवसर मुझे कहां मिलता। किंतु मैं भुवनेश्वर गई और मैंने यूनिट-2 के गर्ल्स हाईस्कूल में नाम लिखवाया। होस्टल में रहने लगी। उसके बाद मैंने पुरी, भुवनेश्वर और कोणार्क देखा। पहली बार जगन्नाथ दर्शन की स्मृति मेरे मन से मिटी नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर, बड़े-बड़े देवता! भला ये सब भुलाए जा सकते हैं? क्या भुलाई जा सकती है उनकी रथयात्रा? बारह महीने में तेरह पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं श्रीक्षेत्र में। लेकिन रथयात्रा की छटा तो निराली होती है। पूरे वर्ष भक्तगण यहां आकर महाप्रभु का दर्शन करते हैं मंदिर के अंदर जाकर। किंतु वर्ष में एक बार महाप्रभु अपने भव्य मंदिर से बाहर 'विशाल पथ' ('बोड़ो दांडो') पर आते हैं। भक्तों को दर्शन देते हैं। तीन रथ पर तीन ठाकुर बैठकर चक्रराज सुदर्शन के साथ गुंडिचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। वहां सात दिनों तक रहकर वापस लौट आते हैं। महाप्रभु का यह महापर्व अतुलनीय है।

बचपन से मैं जगन्नाथ जी की भक्त हूं। वे सर्वदा मेरे परम आराध्य हैं। मेरे जीवन के उत्थान और पतन के वे नियंता हैं। मेरे दुःख-सुख के कर्ता-धर्ता हैं। जीवन में मैंने बहुत कष्ट भी सहे हैं। उन सब दारुण दुःखों से उबारा है मुझे महाबाहु ने। मैं उनकी बेटी जो हूं!

राष्ट्रपति पद के लिए मुझे उम्मीदवार बनाने की घोषणा होते ही मैंने महाप्रभु का स्मरण किया। इतनी ऊंचाई पर मुझे ले जा रहे हो प्रभु, पग-पग पर मुझे सहारा देना, सदा मेरे पास रहना- यह मेरी प्रार्थना थी। उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, सुन भी रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में दिल्ली में रहने के दौरान रथयात्रा का महापर्व आया। परंतु पुरी जाना संभव नहीं था। रथयात्रा के दिन बड़े भोर में दिल्ली के हौजखास में बने जगन्नाथ मंदिर जाकर मैंने महाप्रभु के दर्शन किए। आनंद से भर गया मन। उनका आशीष मुझ पर बरस गया। बड़े आत्मविश्वास से मैंने अपना नामांकन-पत्र दाखिल किया। अत्यंत उत्साह से चुनाव कैम्पेन में भाग लिया। 25 जुलाई 2022 को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में शपथ लेने जाते समय मैं जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते-करते जा रही थी। उनके आशीर्वाद से मेरा शपथ-पाठ खूब अच्छी तरह सम्पन्न हुआ। राष्ट्रपति के रूप में मेरे प्रथम भाषण के समय मानो वे मेरे साथ ही थे।

रथयात्रा की छटा तो निराली और अविस्मरणीय है...

पहली बार जगन्नाथ दर्शन की स्मृति मेरे मन से मिटी नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर, बड़े-बड़े देवता! भला ये सब भुलाए जा सकते हैं? क्या भुलाई जा सकती है उनकी रथयात्रा? बारह महीने में तेरह पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं श्रीक्षेत्र में। लेकिन रथयात्रा की छटा तो निराली है।

पुरी जाकर महाप्रभु के दर्शन के लिए मेरा मन व्याकुल हो उठा। दिन बीतते चले गए, लेकिन मैं पुरी नहीं जा सकी। मुझे लगा कि बिना उनके बुलावे के कोई कैसे उनके पास जा सकता है! मैंने मन ही मन उनसे कहा, मेरा कोई दोष हो तो क्षमा करो प्रभु, मुझे पुरी बुलाओ, दर्शन दो। वे भाव के ठाकुर हैं। मेरा भाव कैसे नहीं समझते? कुछ ही दिनों में पुरी जाने का कार्यक्रम तय हो गया। वह 10 नवंबर, 2022 का दिन था।

पुरी में अवतरण करने के बाद कार-केड चल पड़ा श्रीमंदिर की ओर। कार-केड पुरी के प्रशस्त पावन-पथ पर पहुंचते ही मेरे अंदर एक अपूर्व भावना का संचार हुआ। यह विशाल-पथ महाप्रभु जगन्नाथ का ही है। यहां क्या आवश्यकता है प्रोटोकॉल की? पुरी तो क्षेत्रराज के रूप में प्रसिद्ध है। महाप्रभु देवाधिदेव हैं। और अधिक कुछ सोचने से पहले मैंने गाड़ी रुकवाई। मेरी गाड़ी रुकने पर पीछे आ रही सारी गाड़ियां रुक गईं। किसी के कुछ समझने से पहले मैंने पावन-पथ पर नंगे पैर चलना शुरू कर दिया। श्रीमंदिर लगभग दो किलोमीटर दूर था। मंदिर के नीलचक्र और पतित पावन-ध्वज को देखते हुए मैं आगे बढ़ती चली गई। पथ के दोनों किनारों पर खड़े बच्चों, महिलाओं, युवा-छात्रों और बुजुर्गों को नमस्कार भी करती जा रही थी। मेरा ध्यान था जगन्नाथ जी के पास। श्रीमंदिर के सिंहद्वार के पास पहुंचते ही मैं स्थिर नहीं रह पाई। तब तक मैं खुद को भूल चुकी थी। पावन-पथ की धूल में साष्टांग लेटकर मैंने महाप्रभु को प्रणाम किया। उसके बाद मंदिर में प्रवेश। गर्भगृह में पहुंचकर चतुर्धा मूर्तियों का दर्शन करते ही मैं आनंद से अभिभूत हो गई।

महाप्रभु जगत के नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। जगत के लोगों का दुःख दूर करने के लिए वे सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनकी गोल-गोल आंखों की पलकें कभी नहीं झपकतीं। उनके लिए छोटा-बड़ा कोई नहीं है। वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समता के मंत्र से सबको अभिमंत्रित करते हैं। उनकी करुणा पाकर ही मैंने समाज के हर वर्ग की सेवा में स्वयं को समर्पित किया है। करबद्ध होकर बोली, आपके आशीर्वाद से मेरा यह समर्पण भाव हमेशा बना रहे, हे महाबाहु। देश-दुनिया पर अपनी छत्र-छाया बनाए रखें, हे कृपानिधि!

यह कहते हुए मैं भक्तिभाव से विह्वल हो उठी!

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

सुर्खियों से आगे • सरकार जो कर दे, वही सही?

ई-20 सरकार है, हम थाली के बैंगन

देश-समाज

नवनीत गुर्जर
navneet@dbcorp.in

ई-20 ऐसा पेट्रोल है, जिसमें 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है। देशभर के पंपों पर अब ये एथेनॉल मिक्स पेट्रोल ही मिल रहा है। एथेनॉल दरअसल, गन्ने, मक्का और कुछ अन्य कृषि उत्पादों से बनता है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के पीछे सरकार तीन मुख्य वजहें बताती है। पहली, प्रदूषण कम करना। दूसरी, कच्चे तेल के आयात में कमी करना और तीसरी, किसानों की आय बढ़ाना।

प्रदूषण कम करने का तर्क सही हो सकता है, लेकिन कच्चे तेल का आयात घटता है तो इस एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटे? यह तो सरकार भी मान रही है कि इस पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि गाड़ियों का एवरेज लगभग तीन से सात प्रतिशत घट रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस मिक्स पेट्रोल के कारण जो थोड़े पुराने वाहन हैं, उनके इंजन पर बुरा असर हो सकता है। इस तरह के वाहनों के लिए दूसरा कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया है।

जहां तक किसानों का सवाल है- उनका गन्ना कौन-सा दोगुनी कीमत पर बिक रहा है? वे तो वर्षों से अपना सारा गन्ना बेच ही रहे हैं। वो भी कम से कम दाम पर। वैसे भी एथेनॉल बड़ी मात्रा में अमेरिका से आयात किया जा रहा है। 2024 का आंकड़ा ही लें तो भारत ने 67.98 करोड़ लीटर एथिल अल्कोहल आयात किया था, जिसमें करीब 92 प्रतिशत यानी 62.29 करोड़ लीटर केवल अमेरिका से आया था।

सरकार का कहना है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के खिलाफ उसके पास कोई शिकायत नहीं आई है। हम जो इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से कर रहे हैं, दरअसल थाली के बैंगन हैं। हमारा कोई पक्ष ही नहीं है। मत ही नहीं है। कोल्हू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं बिना सिर उठाए। पीछे से कोड़े भी पड़ रहे हैं, लेकिन मजाल कि उफ भी कर दें! जो सरकार कर दे वही सच! जो सरकार कह दे वही ब्रह्मवाक्य! हमें न किसी तरह की महंगाई से फर्क पड़ता, न किसी तरह के गलत निर्णय से! दरअसल, ठहरकर, रुककर सोचने का हमारे पास वक्त ही नहीं है। सचाई तो ये है कि हम चेहरे देखकर तिलक करने के आदी हो चुके हैं। मुद्दों पर न तो हम बात करना चाहते और न ही उन्हें छूना चाहते। दरअसल, मुद्दों पर बात करने के लिए पढ़ना जरूरी होता है। उससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं रहा। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और वॉट्सएप के मुरीद हो चुके हैं। यहां जो कोई, जो कुछ भी कह देता है, उसी को सच मान लेना हमारी फितरत हो गई है। हम अपने बच्चों को भी किताबों से बुरी तरह दूर करते जा रहे हैं।

किसी ने कहा- गांधी जी ऐसे थे, हमने मान लिया। अब कोई कह रहा है गांधी वैसे थे, हमने इसे भी मान लिया। एक लंगोटी में पूरा जीवन काट देने वाली इस महान आत्मा के बारे में हमने कभी कुछ पढ़ना चाहा ही नहीं। पढ़ भी नहीं पाए।

एथेनॉल से कच्चे तेल का आयात घटता है तो इस एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के दाम क्यों नहीं घटे? सरकार भी मान रही है कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। किसानों का गन्ना कौन-सा दोगुनी कीमत पर बिक रहा है? वे तो वर्षों से अपना सारा गन्ना बेच ही रहे हैं।

यही सब नेहरू जी के बारे में भी हुआ। ठीक है, अब का दौर भी महान है और इसका कोई मुकाबला नहीं हो यह भी संभव हो, लेकिन गांधी-नेहरू का दौर, तब की परिस्थितियां और उन हालात के बीच देश को खड़ा करना, खड़ा रखना कोई मामूली बात थी क्या? जाने क्यों हम पढ़े-लिखे बिना तुलनाओं में चले जाते हैं! कुल मिलाकर बात ये है कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं रहा। ज्वलंत मुद्दों से तो बिलकुल नहीं।

खैर, बात ई-20 की हो रही थी। एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि एथेनॉल तो वर्षों से मिला रहे हैं। तब कारों को नुकसान क्यों नहीं हुआ? वर्षों से मिला रहे होंगे- दो-चार प्रतिशत। अब तो पूरा 20 प्रतिशत मिला दिया। अब तो नुकसान जितना भी हो, होगा ही। आखिर तो चीजों का फायदा या नुकसान उनकी मात्रा पर ही निर्भर होता है! उस मात्रा पर बात क्यों नहीं करते!

विश्लेषण • दतिया और बांकीपुर सीटें चर्चा में हैं

राजनीति में उपचुनावों का ट्रेंड किस ओर इशारा करता है?

सियासत

संजय कुमार
प्रोफेसर और चुनाव विश्लेषक
sanjay@csds.in

भारत में उपचुनाव तभी कराए जाते हैं, जब किसी विधानसभा या लोकसभा सीट के रिक्त हो जाने के बाद अगला चुनाव होने में छह माह से अधिक का समय शेष हो। लेकिन लोगों का ध्यान कुछ उपचुनाव ही खींच पाते हैं। वर्तमान में तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव प्रस्तावित हैं। इनमें बिहार की बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट शामिल हैं। मंजलपुर को लेकर शायद ही कोई चर्चा हो रही हो, लेकिन दतिया और बांकीपुर उपचुनाव अलग-अलग कारणों से सुर्खियों में हैं। सियासी तौर पर दोनों सीटों के उपचुनाव ने लोगों में रुचि पैदा की है। लेकिन यह रुचि थोड़े समय की ही साबित हो सकती है, क्योंकि दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी बड़ी संख्या में वोटरों की पसंद बनी हुई दिखाई देती है।

आंकड़े भी बताते हैं कि उपचुनावों में अधिकतर वोटरों की पहली पसंद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी ही होती है। बीते पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों में 153 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से 119 सीटों पर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन ने जीत हासिल की, जो 78% सफलता दर को दर्शाता है। वहीं विपक्षी दलों या गठबंधनों के उम्मीदवार 34 सीटें ही जीत पाए। उनकी सफलता दर 22% रही। उपचुनावों के संदर्भ में यही पैटर्न बीते पांच सालों से दिखाई दे रहा है।

मौजूदा उपचुनावों से पहले 2026 में 7 अन्य उपचुनाव हुए थे और सभी सीटों पर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन जीता था। 2025 में 15 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से 9 सीटें राज्य की सत्ता पर काबिज दल या गठबंधन ने जीतीं, जबकि 6 विपक्ष के खाते में गईं। 2024 की तस्वीर भी इससे अलग नहीं थी। उस वर्ष 86 सीटों पर हुए उपचुनाव में 69 सीटें सत्तारूढ़ दल/गठबंधन ने जीती, जबकि 17 पर विपक्षी दलों/गठबंधनों ने जीत दर्ज की। 2023 में 17 उपचुनावों में 12 सीटों पर सत्ताधारी दल/गठबंधन जीता और 5 सीटें विपक्षी उम्मीदवारों के खाते में गईं। इसी तरह 2022 में 28 सीटों के उपचुनाव में 22 पर सत्तारूढ़ दल या गठबंधन विजयी रहा और विपक्ष के उम्मीदवार केवल 6 सीटें ही जीत पाए।

दतिया और बांकीपुर के उपचुनावों ने सियासी दिलचस्पी पैदा की है। खासकर तब, जब भाजपा ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया और मध्यप्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र को दतिया से टिकट नहीं दिया गया तो भाजपा कार्यकर्ता इसके विरोध में उतर आए। मिश्र राज्य के कद्दावर नेता रहे हैं। लेकिन पार्टी ने उनकी जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय किया।

बांकीपुर सीट पर भी भाजपा ने पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा ने नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया। बांकीपुर सीट इसलिए भी सुर्खियों में है, क्योंकि जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर यहां से चुनावी डेब्यू कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उनकी पार्टी वर्ष 2025 में पहली बार बिहार चुनाव में मैदान में उतरी थी, लेकिन प्रशांत खुद किसी सीट से चुनाव नहीं लड़े थे। चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। उसे केवल 3.5% मत मिले और वह खाता तक नहीं खोल पाई थी।

बीते 5 वर्षों के 153 उपचुनाव एक ट्रेंड की ओर संकेत करते हैं। यह कि एक औसत भारतीय वोटर उम्मीदवार के बजाय पार्टी के लिए वोट देना पसंद करता है। छोटे राज्य इसमें अपवाद हो सकते हैं, जहां प्रत्याशी की लोकप्रियता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

यह समझना महत्वपूर्ण है कि दतिया और बांकीपुर सीटें इसलिए चर्चा में नहीं हैं कि विपक्ष ने इनमें कद्दावर नेताओं को उम्मीदवार बनाया है अथवा यहां कोई बेहद दिलचस्प चुनावी मुकाबला होने जा रहा है। इन दोनों उपचुनावों पर चर्चा किन्हीं अन्य कारणों से हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा के भीतर कुछ उथल-पुथल है, जो कि एक असामान्य स्थिति मानी जाती है। इसके चलते भी ये दोनों उपचुनाव दिलचस्प बन गए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • बड़ी संख्या में सड़क हादसे खराब सड़कों नहीं, बल्कि खराब ड्राइविंग का नतीजा होते हैं...

सड़कों के साथ ही 'ड्राइवरों' का अच्छा होना भी उतना ही जरूरी है

सिविक-सेंस

आदर्श जोशी
सुप्रीम कोर्ट में वकील
aadarshjoshi65@gmail.com

आप अपनी लेन में चल रहे हैं, सुरक्षित दूरी बनाए हैं और गाड़ी भी निर्धारित स्पीड में ही चला रहे हैं। तभी अचानक कोई दूसरा वाहन बिना चेतावनी के सामने से कट मार देता है। कोई मोटरसाइकिल वाला गलत दिशा से आ जाता है। कोई कार एग्जिट चूक जाने के बाद हाईवे पर ही रिवर्स होने लगती है। कोई ट्रक फास्ट-लेन घेरे रहता है। इंडिकेटर दिखावे की चीज बने रहते हैं। हाई बीम सामने से आने वालों को लगभग अंधा बना देती है। मोबाइल ड्राइवर का ध्यान स्टीयरिंग से भटकाता रहता है।

ये दृश्य इतने आम हो चले हैं कि अब हमें हैरानी भी नहीं होती। कई मायनों में ये भारत में रोजमर्रा की ड्राइविंग का हिस्सा बन चुके हैं। जब भी कोई गंभीर एक्सीडेंट होता है तो सार्वजनिक बहस आमतौर पर सड़कों के इर्द-गिर्द ही घूमती है। क्या सड़क पर गड्ढा था? हाईवे का डिजाइन खराब था? सेफ्टी बैरियर नहीं थे? ये सवाल महत्वपूर्ण भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फलोदी दुर्घटना मामले में ऐसी कई चिंताओं को हाईलाइट किया और हाईवे की सुरक्षा सुधारने के निर्देश जारी किए। अदालत ने हाईवे प्रबंधन और अतिक्रमण से लेकर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम तथा दुर्घटना रोकथाम उपायों तक कई मुद्दों पर विचार किया। यह दखल जरूरी था, क्योंकि बेहतर सड़कें, सुरक्षित हाईवे और तेज इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जान बचा सकते हैं। लेकिन यह फैसला ऐसे सवाल पर भी ध्यान दिलाता है, जो शायद ही कभी पूछा जाता है- क्या हम ड्राइवरों पर भी ध्यान दे रहे हैं?

सड़क सुरक्षा की शुरुआत हाईवे से नहीं होती, बल्कि तब होती है जब कोई वाहन चलाने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ड्राइविंग लाइसेंस सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अनुमतियों में से एक है। यह किसी व्यक्ति को पल भर में भारी नुकसान पहुंचा सकने वाली मशीन चलाने का अधिकार दे देता है। लेकिन व्यवहार में ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को अकसर कौशल, निर्णय-क्षमता और जिम्मेदारी के गंभीर आकलन के बजाय एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान लिया जाता है। इसके नतीजे रोज दिखते हैं। लेन अनुशासन की अनदेखी होती है। गलत साइड से ओवरटेक आम बात है। चालक असुरक्षित स्थानों पर वाहन रोक देते हैं, बेमतलब हाई बीम का इस्तेमाल करते हैं और ट्रैफिक सिग्नल को मानते नहीं। ऐसे व्यवहार को अकसर महज अनुशासनहीनता माना जाता है। लेकिन समस्या इससे गहरी है : बहुत-से ड्राइवरों को कभी ठीक से सिखाया ही नहीं गया कि ये नियम आखिर क्यों बनाए गए हैं।

वाहन को स्टार्ट करना, गियर बदलना, रिवर्स और पार्क करना मैकेनिकल स्किल हैं, जबकि ड्राइविंग के लिए जागरूकता, निर्णय-क्षमता और अनुशासन जरूरी होता है। मतलब, खतरों का अनुमान लगाना, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, लेन अनुशासन का पालन, ब्लाइंड स्पॉट्स को समझना और यह मानना कि सड़क पर लिया हर निर्णय दूसरों की सुरक्षा को प्रभावित करता है। कोई व्यक्ति वाहन चलाना जानता हो, तब भी वह अनसेफ ड्राइवर हो सकता है। पर लाइसेंसिंग प्रक्रिया मानती है कि वाहन चला सकना ही सुरक्षित ड्राइविंग की क्षमता भी है।

भारत में 2024 में 4.68 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 1.75 लाख से अधिक लोग मारे गए। 61% से अधिक दुर्घटनाएं अकेले ओवर-स्पीडिंग से हुईं। 26% का कारण खतरनाक या लापरवाही भरी ड्राइविंग और ओवरटेकिंग रहा। ज्यादातर दुर्घटनाओं के लिए ये दोनों ही जिम्मेदार हैं। वर्षों तक हमने इस बात पर चर्चा की है कि सड़कें कैसी बनाई जानी चाहिए। लेकिन अब हमें सुनिश्चित करना होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस वास्तव में योग्यता का प्रमाण बने। ड्राइविंग-एजुकेशन को मजबूत करने की भी जरूरत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

फुल स्पीड • अप्रैल-जून में रिकॉर्ड 12.74 लाख कारें बिकीं, सालाना 26% बढ़ोतरी

एसयूवी की बिक्री कारों से ढाई गुना ज्यादा, स्कूटर की बाइक से दोगुनी

जीएसटी में कटौती, सस्ती फाइनेंसिंग ने मांग बढ़ाई

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

देश में कारों और दोपहिया की बिक्री के आंकड़ों से नया ट्रेंड सामने आया है। अप्रैल-जून तिमाही में यूटिलिटी वाहनों (यूवी) की बिक्री सामान्य हैचबैक-सेडान कारों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ी। दोपहिया बाजार में भी अब स्कूटर, मोटरसाइकिलों को पीछे छोड़ दिया है।

वाहन कंपनियों के संगठन सियाम के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल-जून में कारों की कुल बिक्री (डीलरों को डिस्पैच) 26% बढ़कर रिकॉर्ड 12.74 लाख तक पहुंच गई। लेकिन इस उछाल की मुख्य वजह यूवी रहे। इनकी बिक्री सामान्य कारों से करीब 7 पर्सेंटेज पॉइंट ज्यादा रफ्तार से बढ़ी। दोपहिया में भी स्कूटरों की बिक्री मोटरसाइकिलों के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ी। सियाम के प्रेसिडेंट शैलेश चंद्रा ने कहा कि जीएसटी में कमी और सस्ती फाइनेंसिंग ने गाड़ियों की घरेलू मांग बढ़ाई है। आगे त्योहारों के सीजन में गाड़ियों की मांग और बढ़ सकती है। इसे देखते हुए कंपनियों की प्रोडक्शन लाइन मजबूत करना शुरू कर दिया है।

देश में बड़ी, ऊंची और मजबूत गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ने के साफ संकेत

ट्रेंड 1 • आम कारें 3.67 लाख, एसयूवी 8.62 लाख बिकीं

कैटेगरी	अप्रैल-जून 25	अप्रैल-जून 26	बिक्री बढ़ी
सेडान-हैचबैक	3.03 लाख	3.67 लाख	21.3%
यूटिलिटी व्हीकल	6.70 लाख	8.62 लाख	28.6%
वैन	38,635	44,344	14.8%
कुल पैसेंजर व्हीकल	10.12 लाख	12.74 लाख	25.9%

ट्रेंड 2 • दोपहिया में मोटरसाइकिलों का दबदबा कमजोर

कैटेगरी	अप्रैल-जून 25	अप्रैल-जून 26	बिक्री बढ़ी
स्कूटर	16.65 लाख	21.79 लाख	30.8%
मोटरसाइकिल	29.03 लाख	33.09 लाख	14.0%
मोपेड	1.09 लाख	1.41 लाख	28.9%
सभी दोपहिया	46.78 लाख	56.28 लाख	20.3%

स्रोत: सियाम

4-व्हीलर: हर 100 कारों की बिक्री में से 68 एसयूवी

अब हर 100 कारों की बिक्री में करीब 68 यूटिलिटी वाहन (एसयूवी श्रेणी) हैं। बीती तिमाही में यूवी बिक्री 6.7 लाख से 28.6% बढ़कर 8.6 लाख हो गई। इसके मुकाबले सामान्य कारों की बिक्री 21.3% बढ़कर 3.7 लाख रही। यानी पारंपरिक कारों की बाजार हिस्सेदारी सिकुड़ रही है, जबकि बड़ी, ऊंची और मजबूत गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।

दोपहिया: स्कूटर की बिक्री 31%, बाइक की 14% बढ़ी

बीती तिमाही स्कूटर की बिक्री में 30.8% बढ़कर 21.79 लाख हो गई। लेकिन मोटरसाइकिल की बिक्री सिर्फ 14% बढ़कर 33.09 लाख रही। अकेले जून में यह फासला ज्यादा रहा। स्कूटर की बिक्री 39% से भी ज्यादा बढ़ी, जबकि मोटरसाइकिलों की सिर्फ 6.4% बढ़ पाई। मोपेड की बिक्री भी 28.9% की तेज वृद्धि के साथ 1.41 लाख तक पहुंच गई।

अप्रैल-जून

कारों के निर्यात में भी 9% बढ़ोतरी

- कमर्शियल वाहनों की बिक्री 18.3% बढ़कर 2.65 लाख हो गई। इसमें गुड्स कैरियर सेगमेंट ने ज्यादा तेज बिक्री वृद्धि देखी।
- कार निर्यात 8.8% बढ़कर 2.22 लाख हो गया। लैटिन अमेरिका से मांग ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, हालांकि मध्य-पूर्व को निर्यात घटा है।
- दोपहिया निर्यात सबसे तेज 36.6% बढ़ा। कुल 1.55 लाख दोपहिया के निर्यात में दक्षिण एशिया आगे रहा। अफ्रीकी देशों से स्थिर मांग रही।
- शहरी इस्तेमाल और सहूलियत की वजह से स्कूटर अब दोपहिया बाजार का सबसे तेज बढ़ता हिस्सा बन गए हैं।

दांव • कनाडा के प्रेम वत्स की कंपनी का भारतीय बैंकिंग में सबसे बड़ा 53,000 करोड़ निवेश

IDBI बैंकः फेयरफैक्स ले सकती है 61% हिस्सा

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

कनाडा की फेयरफैक्स होल्डिंग्स भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा विदेशी निवेश करने जा रही है। यह कंपनी आईडीबीआई बैंक में 60.72% हिस्सेदारी खरीद सकती है। यह डील करीब ₹53,000 करोड़ की होगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने फेयरफैक्स का नाम फाइनल कर लिया है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि कंपनी ने अपनी बोली पिछले साल के ₹75 से बढ़ाकर ₹81 प्रति शेयर कर दी है। इस संशोधित कीमत पर सरकार अपना 30.48% हिस्सा (कुल 45.48% में से) बेचकर करीब ₹26,620 करोड़ जुटाएगी। वहीं लगभग 50% मालिकाना हक रखने वाली एलआईसी भी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी, जिससे उसे ₹26,440 करोड़ मिलेंगे। प्रेम वत्स की फेयरफैक्स को इसके बाद ओपन ऑफर लाना होगा। अभी सरकार की तरफ से इस डील की पुष्टि नहीं हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाले मंत्री समूह को डील की जानकारी दे दी गई है और जल्द ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी होगा। सफल बोलीदाता को आरबीआई के 'फिट एंड प्रॉपर' मानकों और सीसीआई से मंजूरी लेनी होगी। फेयरफैक्स के पास सीएसबी बैंक में 40% हिस्सेदारी है, इसलिए दोनों बैंकों का विलय करना होगा।

निवेशः टूटेगा अमीरात एनबीडी का पिछला रिकॉर्ड

इस सौदे पर मुहर लगती है तो यह 2025 में अमीरात एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में 2.75 अरब डॉलर में 60% हिस्सा खरीदने के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। एनएसई पर आईडीबीआई बैंक के शेयर बुधवार को 0.36% की मामूली गिरावट के साथ 86.23 रुपए पर बंद हुए। यह कीमत 30 मार्च के 52 हफ्तों के इंट्राडे निचले स्तर 61.01 रुपए से 41% अधिक है।

छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ेंगे

जोमैटो के दीपेंदर एयरोस्पेस में 200 करोड़ रुपए लगाएंगे

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

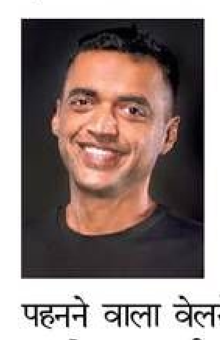

इटर्नल लिमिटेड के पूर्व सीईओ दीपेंदर गोयल अब एयरोस्पेस सेक्टर में कदम रखने जा रहे हैं। वे छोटे शहरों को विमानन सर्विस से जोड़ने के लिए एलएटी एयरोस्पेस में करीब 200 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। गोयल इसके अलावा हेल्थ टेक में भी बड़ा दांव खेल रहे हैं। वे छह महीने से एक साल के भीतर माथे पर पहनने वाला वेलनेस डिवाइस 'टेंपल' लॉन्च करेंगे। यह डिवाइस शरीर की ऊर्जा और पाचन क्षमता में होने वाले बदलावों को तुरंत मापेगा। रिसर्च के दौरान गोयल की टीम ने शरीर के आंतरिक बदलावों को पकड़ने वाला एक नया पैमाना खोजा है। यह तकनीक मुख्य रूप से तनाव, गहरी नींद और हैवी एक्सरसाइज से जुड़े शारीरिक उतार-चढ़ाव को ट्रैक करेगी।

गैजेट • 68% लोग फोन में इनबिल्ट एआई चाहते हैं

AI फीचर भी तय कर रहे कि कौन सा फोन खरीदेंगे भारतीय

हर्ष शिवम | नई दिल्ली

कैमरा कितने मेगापिक्सल का है या बैटरी कितनी बड़ी है- अब स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ यही सवाल नहीं पूछे जा रहे। भारतीय यह भी देख रहे हैं कि फोन में एआई क्या-क्या कर सकता है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म सीएमआर के एक सर्वे के मुताबिक, एआई फीचर्स अब स्मार्टफोन खरीदने के सबसे अहम पैमानों में शामिल हो चुके हैं।

सीएमआर के 'स्मार्टफोन एआई प्लस 2026' सर्वे के मुताबिक, 18-35 वर्ष के 71% स्मार्टफोन यूजर अब हर हफ्ते कई बार जनरेटिव (जेन) आई फीचर्स इस्तेमाल करते हैं। देश के आठ बड़े शहरों के किए गए सर्वे में शामिल 59% लोगों ने कहा कि नया स्मार्टफोन खरीदते समय वे एआई फीचर्स को प्रमुख आधार मानते हैं।

कौन सा फोन लें, ये फैसला 60% हार्डवेयर-एआई के बीच संतुलन पर निर्भर... स्मार्टफोन के मामले में परफॉर्मेंस अब भी सबसे अहम फैक्टर है (78%)। खरीदारी के फैसले में कैमरा क्वालिटी (70%) दूसरे नंबर पर आती है। अब एआई फीचर्स तीसरे नंबर पर 59% पर आ गए हैं। 68% यूजर अगले फोन में बेहतर एआई फीचर्स चाहते हैं। दो समान कीमत वाले फोन में से चुनाव का आधार अब 60% हार्डवेयर और एआई के बीच संतुलन हो गया है। 25% ग्राहक सीधे एआई को हार्डवेयर से ऊपर रखते हैं।

देश में... फोटोग्राफी में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल

भारत में 77% यूजर लो-लाइट एन्हांसमेंट और पोर्ट्रेट ऑप्टिमाइजेशन जैसे एआई इमेजिंग फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं। गेमर्स 91% के साथ सबसे ज्यादा एआई-सक्षम फीचर्स इस्तेमाल करते हैं। एआई के इस्तेमाल के मामले में इसके बाद कंटेंट क्रिएटर्स (86%) और प्रोफेशनल्स (80%) आते हैं।

सुरक्षा की चिंताः फोन के अंदर ही डेटा प्रोसेसिंग को तरजीह

82 फीसदी यूजर्स का कहना है कि पारदर्शी डेटा पॉलिसी भरोसा बढ़ाती है। इतने ही यूजर भरोसेमंद चिप ब्रांड को बेहतर एआई अनुभव से जोड़ते हैं।

75 फीसदी यूजर मानते हैं कि चिपसेट क्षमता एआई अनुभव को प्रभावित करती है। 14-29 साल के युवाओं में यह जागरूकता सबसे ज्यादा 83% है।

61 फीसदी यूजर मानते हैं कि ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेसिंग (फोन के अंदर ही डेटा प्रोसेस होना) प्राइवेसी और स्पीड, दोनों बेहतर करती है।

49 फीसदी लोग "हैवी एआई यूजर" हैं। ये पांच या ज्यादा फीचर्स का नियमित इस्तेमाल करते हैं। 41% मॉडरेट और 10% कभी-कभार इस्तेमाल करते हैं।

बिजनेस ब्रीफ

NSE: इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट के लिए पार्टनरशिप

मुंबई| एनएसई ने गोल्ड फिनटेक फर्म ऑगमाउंट से साझेदारी की है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (ईजीआर) सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इससे सोने को आसानी से डीमैट फॉर्मेट में रखा जा सकेगा। ईजीआर के दाम तय करने में मदद मिलेगी। ज्वेलर्स, निवेशकों को सुविधा होगी।

एसबीआई फंड्स का इश्यू दूसरे दिन 2.82 गुना भरा

मुंबई| एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का आईपीओ बुधवार को दूसरे दिन 2.82 गुना सब्सक्राइब हुआ। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम (जीएमपी) 16% है। इससे पता चलता है कि इस आईपीओ को लेकर सकारात्मक माहौल है। साथ ही दूसरे दिन 100% से ज्यादा सब्सक्रिप्शन संकेत देता है कि निवेशकों के बीच उत्साह है।

यूनियन बैंक का मुनाफा 30% बढ़ा, 5,332 करोड़

नई दिल्ली| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल-जून तिमाही में ₹5,332 करोड़ का शुद्ध मुनाफा कमाया। यह एक साल पहले के मुकाबले 30% ज्यादा है। लेकिन बीती तिमाही बैंक की कुल आय सिर्फ 1.3% बढ़कर ₹31,806 करोड़ रही। हालांकि इस बीच एनपीए (फंसे लोन) पर काबू पाने से प्रदर्शन बेहतर हुआ।

स्पेसएक्स के शेयर इश्यू प्राइस 135 डॉलर से नीचे

न्यूयॉर्क| इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का शेयर बुधवार को पहली बार अपने आईपीओ प्राइस 135 डॉलर से नीचे फिसल गया। नैस्डैक में लगातार चौथे दिन इसमें गिरावट आई। यह 0.85% गिरकर 134.92 पर ट्रेड कर रहा था। यह शेयर 12 जून को लिस्टिंग के बाद $225.64 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था।

पहली बार • केंद्र ने जारी किया 'इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन'

अप्रैल में होटल, रेस्टोरेंट की बुकिंग, बिलिंग, ऑर्डर वैल्यू 37% बढ़ी, रिटेल में ये ग्रोथ 31%

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

सरकार ने पहली बार सर्विस सेक्टर की मासिक ग्रोथ मापने वाला 'इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन' (आईएसपी) जारी किया है। इसके मुताबिक, अप्रैल में होटल-रेस्टोरेंट और फूड बिजनेस से जुड़ी कंपनियों की बुकिंग, बिलिंग, ऑर्डर (ग्रोथ) सालाना आधार पर सबसे ज्यादा 37.2% बढ़ा। रिटेल बिजनेस 30.8% ग्रोथ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यह तस्वीर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) के जारी डेटा से पहले (आईएसपी) से सामने आई है।

यहां रफ्तारः रिटेल एस्टेट, टेलीकॉम में 29% ग्रोथ

अप्रैल में प्रशासनिक एवं सहयोगी सेवाएं 28.7% और रियल एस्टेट सेवाएं 27.7% बढ़ीं। थोक व्यापार, दूरसंचार, रिपेयर सेवाएं और वेयरहाउसिंग में भी 15% से 23% के बीच सालाना वृद्धि दर्ज की गई।

आईएसपी के मुताबिक अप्रैल में शामिल 19 में से 14 प्रमुख सर्विस सेगमेंट ने सालाना 10% से ज्यादा ग्रोथ देखी। प्रशासनिक एवं सहयोगी सर्विस 28.7% और रियल एस्टेट सर्विस 27.7% बढ़ीं। थोक व्यापार, टेलीकॉम, रिपेयर और वेयरहाउसिंग में भी 15-23% ग्रोथ दर्ज की गई। 2024-25 को आधार वर्ष मानकर तैयार किया गया यह नया मासिक इंडेक्स देश के औपचारिक सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का आकलन करेगा।

यहां सुस्तीः पश्चिम एशिया संघर्ष से हवाई यात्रा प्रभावित

पश्चिम एशिया में संघर्ष से हवाई यात्रा अप्रैल में 4% घट गई। रेलवे परिवहन में 0.4% की मामूली गिरावट आई। लेकिन, डाक-कूरियर सेवाएं 3.3% और सूचना एवं प्रसारण सेवाएं 2.5% बढ़ीं।

सेंसेक्स 591 अंक चढ़ने के बाद मुनाफा वसूली से फ्लैट

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

शेयर बाजार में बुधवार को शुरुआत में हासिल बढ़त आखिरी घंटों में मुनाफा वसूली से खत्म हो गई। सेंसेक्स दिन के हाई से 461 अंक फिसलकर महज 130 अंकों की बढ़त के साथ 77,185 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 142 अंकों की तेजी गंवाकर 28 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 24,078 पर रहा। ट्रेडिंग के दौरान एक समय सेंसेक्स 591 अंकों की उछाल के साथ 77,646 तक और निफ्टी 168 अंकों की बढ़त लेकर 24,220 तक पहुंच गया था। अमेरिका में महंगाई कम होने से फाइनेंशियल शेयरों की खरीदारी से बाजार में तेजी आई थी। लेकिन उसके बाद कच्चे तेल के दाम 2.15% बढ़कर 86.55 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने से मुनाफा वसूली बढ़ गई। सेंसेक्स के शेयरों में इटर्नल, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन और एशियन पेंट्स में 3% तक तेजी रही। पावरग्रिड, लार्सन एंड टुब्रो, टाटा स्टील और इंफोसिस 1.80% तक नुकसान में रहे।

ऋषद प्रेमजी का नया ग्रोथ प्लान

एआई खतरे के साथ मौका भी, विप्रो लगा रही बड़ा दांव

भास्कर न्यूज़ | बेंगलुरु

आईटी कंपनियों के सामने एआई एक साथ चुनौती और मौका, दोनों बनकर खड़ा है। विप्रो इस दोहरी लड़ाई में क्लाइंट के साथ पुराने रिश्तों को हथियार बना रही है। कंपनी की 80वीं सालाना बैठक में चेयरमैन ऋषद प्रेमजी ने कहा कि आईटी सर्विस कंपनियों को क्लाइंट्स के बिजनेस की दशकों पुरानी समझ है, जो उन्हें एआई का फायदा दिलाने के लिए बेहतर स्थिति में रखती है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब तीन साल से कंपनी की सालाना ग्रोथ 5% से कम रही है। इस बीच एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चेतावनी दी है कि अगले तीन साल में एआई-नेटिव कंपनियां भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों की आय आधार खा सकती हैं। प्रेमजी ने बताया कि लागत-बचत वाले बड़ी डील मुनाफे पर दबाव डालते हैं, जबकि छोटे एआई-नेटिव सौदे तेजी से फायदा देते हैं और मार्जिन भी बेहतर होता है। यही वजह है कि विप्रो अब प्रोडक्ट मॉडल को नतीजों पर आधारित तरीके की ओर मोड़ रही है, और स्टार्टअप्स में 4,800 करोड़ रुपए लगा चुकी है।

निवेशकों को मिलेंगे नए मौके

तीन कंपनियां आज लिस्ट होंगी, 3 आईपीओ बंद होंगे

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

इक्विटी मार्केट में गुरुवार को तीन कंपनियों की लिस्टिंग होगी और तीन आईपीओ बंद भी होंगे। मेनबोर्ड की लेजर पावर एंड इंफ्रा बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होगी। एसएमई सेगमेंट में हैपी स्टील्स के शेयर एनएसई इमर्ज और देवसन कैटलिस्ट के शेयर बीएसई एसएमई पर लिस्ट होंगे। ग्रे मार्केट में देवसन 40 फीसदी से अधिक, लेजर पावर 20 फीसदी और हैपी स्टील्स 15 फीसदी प्रीमियम पर हैं। लेजर पावर का आईपीओ 41.05 गुना, हैपी स्टील्स का 77.81 गुना और देवसन का 220.35 गुना भरा था। लेजर पावर ने 742 करोड़, देवसन ने 42.3 करोड़ और हैपी स्टील्स ने 25 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गुरुवार को ही एसबीआई फंड्स (अब तक 2.82 गुना सब्सक्राइब), अल्पाइन टेक्सवर्ल्ड (81 फीसदी भरा) और मिलवर्क्स टेक (50.57 गुना सब्सक्राइब) के आईपीओ बंद होंगे। साथ ही, एसएमई सेगमेंट में सोटेफिन भारत का 90 करोड़ रुपए का आईपीओ खुलेगा। सोटेफिन भारत ने अपने पब्लिक इश्यू के लिए 178 रुपए से लेकर 187 रुपए तक प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है।

दिलचस्प • जंबो जेट से 1,000 फुट ऊंची पहाड़ी पर तैयार की गई आलीशान कोठी, फर्स्ट-क्लास केबिन बना गेस्टहाउस

5,200 वर्ग फुट में बना घर, 02 बेडरूम, 03 बाथरूम

कैलिफोर्निया| एक रिटायर्ड मर्सिडीज-बेंज डीलर फ्रांसी रेह्वाल्ड ने महज 30 हजार डॉलर (करीब ₹29 लाख) में एक पुराना बोइंग 747 विमान खरीदा। यह 1970 में बना दुनिया का 28वां जंबो जेट था। आर्किटेक्ट डेविड हर्ट्ज ने इसके 125 फुट लंबे पंखों को काटकर, ट्रकों से 161 किलोमीटर दूर पहुंचाया। आखिरी पड़ाव पर भारी-भरकम चिनूक हेलिकॉप्टर से समुद्र तल से 1,000 फुट ऊंची मालिबू पहाड़ियों तक पहुंचाया। यही पंख अब घर की छत बन चुके हैं। कॉकपिट मेडिटेशन पैवेलियन, फर्स्ट-क्लास केबिन गेस्टहाउस और कार्गो होल्ड एनिमल बार्न बना। यह 'विंग हाउस' हवाई जहाज जैसा ही दिखता है।

एथर एनर्जी में सरकार लगाएगी 200 करोड़

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। यह निवेश कंपनी के प्रस्तावित 1,200 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल फंडरेजिंग का हिस्सा है। सरकार यह निवेश इंडिया-जापान फंड (आईजेएफ) के जरिए करेगी, जो भारत सरकार और जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन के बीच बना 600 करोड़ डॉलर यानी 57,785 करोड़ रुपए द्विपक्षीय इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। इसे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मैनेज करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार का निवेश एथर के संस्थापकों और मौजूदा निवेशक हीरो मोटोकॉर्प की नई पूंजी के साथ-साथ आएगा। प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत इंडिया-जापान फंड 200 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदेगा। दूसरी तरफ हीरो मोटोकॉर्प 960 करोड़ रुपए के कन्वर्टिबल वारंट के जरिए निवेश करेगी।

बिजनेस एंकर कॉरपोरेट इंडिया में महिलाओं की 'ग्लास सीलिंग' बरकरारः कानून ने बोर्ड बदले, नेतृत्व नहीं

बोर्डरूम में बराबरी की बातें, लेकिन शीर्ष पदों पर महिलाओं की भारी कमी; टॉप-500 कंपनियों में सिर्फ 4% महिला एमडी, 0.4% सीईओ

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

फॉर्च्यून 500 इंडिया यानी देश की टॉप-500 कंपनियों में महिला एमडी सिर्फ 4% (20 कंपनियां) और महिला सीईओ केवल 0.4% (2 कंपनियां) हैं। 26 कंपनियों (5.2%) में महिला चेयरपर्सन हैं। इनमें से भी ज्यादातर पारिवारिक बिजनेस में हैं। अनिवार्य स्वतंत्र निदेशक नियम के बावजूद 41 कंपनियों में एक भी महिला निदेशक नहीं, 216 में सिर्फ एक। महज 18 कंपनियों के बोर्ड में महिला-पुरुष अनुपात बराबर है, जबकि सीएक्सओ (जैसे सीईओ, सीओओ, सीएफओ) में महिला भागीदारी सिर्फ 10-12% है।

देश में नियम तो हैं, पर इससे तस्वीर नहीं बदल रही

सीएफए इंस्टीट्यूट इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि कंपनी कानून, 2013 के तहत एक स्वतंत्र निदेशक अनिवार्य किए जाने के बाद बोर्ड में महिला भागीदारी बढ़कर 19% हो गई है। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि सुई जरूर हिली है, लेकिन कानून का पालन औपचारिकता तक सिमटा नजर आता है। बड़ी संख्या में कंपनियां न्यूनतम शर्त पूरी करके आगे नहीं बढ़ीं। चूंकि देश की आधी आबादी महिलाओं की है, लिहाजा बोर्ड में 50:50 अनुपात होना चाहिए था।

यह वो तस्वीर है जो हर कॉरपोरेट मीटिंग में महिला सशक्तीकरण के भाषणों के पीछे छिपी रहती है। अब इसने पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन इंद्रा नूयी के एक बयान के बाद पूरे भारतीय कॉर्पोरेट जगत को कठघरे में खड़ा कर दिया है। नूई ने कहा था कि अमेरिका की मेरिट-आधारित व्यवस्था में ही वे चेयरमैन के पद तक पहुंच पाईं, भारत में शायद ऐसा नहीं हो पाता। फॉर्च्यून इंडिया के अवॉर्ड्स में यही सवाल छाया रहा, हालांकि कैमरे के सामने बोलने से ज्यादातर लोग बचते नजर आए।

बहस के दो स्पष्ट खेमे थे। एक धड़े ने किया मोदी, किरण मजूमदार शॉ, अपोलो हॉस्पिटल्स की रेड्डी बहनों और यूनिलीवर इंडिया की सीईओ प्रिया नायर जैसे नाम गिनाते हुए कहा कि नूयी का दावा जरूरत से ज्यादा है। दूसरे धड़े ने कहा कि महिला लीडर्स की संख्या भले ही बढ़ रही हो, ऊपर लिखे आंकड़े खुद बता रहे हैं कि रास्ता कितना लंबा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नूयी जिस भारत की बात कर रही थीं, वहां कामकाजी महिलाएं ही बहुत कम थीं, अब वह तस्वीर बदल रही है- भले धीरे-धीरे।

असली अड़चन सीएक्सओ और मुनाफा-नुकसान (पी एंड एल) की जिम्मेदारी वाले पदों पर है। ये जिम्मेदारियां सीएफए इंस्टीट्यूट इंडिया की 'माइंड द जेंडर गैप' रिपोर्ट के मुताबिक, बेहद कम पद महिलाओं के पास हैं। नेस्ले इंडिया के पूर्व एमडी सुरेश नारायणन कोटा व्यवस्था के सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि कोटा से औसत दर्जे की संस्कृति पनपती है। कंपनियों को कानून का इंतजार किए बिना खुद वरिष्ठ महिला नेतृत्व तलाशना चाहिए। दिलचस्प है कि नेस्ले इंडिया के बोर्ड में खुद आधा प्रतिनिधित्व महिलाओं का है।

एग्जीक्यूटिव सर्च फर्म एकॉर्ड की मैनेजिंग पार्टनर सोनल अग्रवाल का मानना है कि कंपनियां यदि जेंडर की जगह सिर्फ काबिलियत पर फोकस करें, तो महिलाएं खुद आगे आएंगी।

सरकार अब घाटे में, एक साल पहले सरप्लस में थी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

केंद्र सरकार का चालू खाता घाटा मई में 2 अरब डॉलर यानी 19,260 करोड़ रुपए से ऊपर निकल गया। दिलचस्प है कि मई 2025 में केंद्र 0.7 अरब डॉलर (₹6,741 करोड़) के सरप्लस में था। रिजर्व बैंक के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, इस उलटफेर की सबसे बड़ी वजह व्यापार घाटा बढ़ना है। यह 22.6 अरब डॉलर से बढ़कर 27.9 अरब डॉलर हो गया, क्योंकि आयात (61.3 से 74 अरब डॉलर) निर्यात (38.7 से 46.1 अरब डॉलर) के मुकाबले कहीं तेज रफ्तार से बढ़ा। सर्विसेज निर्यात (15.7 अरब डॉलर) और विदेश से आने वाला पैसा यानी रेमिटेंस (13.6 अरब डॉलर, पिछले साल 10.5 अरब डॉलर) ने कुछ राहत दी। लेकिन व्यापार घाटे की भरपाई के लिए यह नाकाफी रहा।

सीएएफई नियमों में बदलाव पर टाटा की आपत्ति

'क्रेडिट सिस्टम से क्लीन टेक में सुस्त पड़ जाएगा निवेश'

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

इलेक्ट्रिक कार निर्माता टाटा मोटर्स ने सीएएफई (कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी) नियमों के प्रस्तावित बदलावों पर सरकार से तीखी आपत्ति जताई है। ऊर्जा मंत्रालय और बीईई को 14 जुलाई को भेजे पत्र में कहा है कि नया मसौदा स्वच्छ वाहन तकनीक में होने वाले निवेश को काफी कमजोर करेगा। नए प्रस्ताव में लक्ष्य से पीछे रहने वाली कंपनियां ₹2,500 प्रति ग्राम सीओ2 प्रति किमी की दर से सीधे बीईई से क्रेडिट खरीद सकेंगी। कंपनी का तर्क है कि यह कीमत नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले 5,000 रुपए के कानूनी जुर्माने से ठीक आधी है। ऐसे में वाहन निर्माता नई तकनीक पर भारी निवेश करने के बजाय बेहद सस्ते में क्रेडिट खरीदकर नियमों से बचना ज्यादा पसंद करेंगी।

जुर्माना • सरकार ने ऑटो कंपनियों को बड़ी राहत दी

केंद्र सरकार ने हाल में बड़ा कदम उठाते हुए कई पैसेंजर व्हीकल निर्माताओं पर सीएएफई-2 नियमों के तहत लगने वाले लगभग 2,700 करोड़ रुपए के भारी-भरकम पुराने जुर्माने को पूरी तरह माफ कर दिया है। इसी बड़े फैसले के बाद अब नियमों का पालन कराने के लिए नया बाजार आधारित क्रेडिट सिस्टम लाया जा रहा है।